चिंतन

बंगाल हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। चुनाव के बाद जिस तरह हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, वह बेहद चिंताजनक हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता कब तक राजनीतिक संघर्ष की कीमत अपनी जान और सुरक्षा से चुकाती रहेगी। चुनाव परिणाम चाहे किसी के पक्ष में आए हों, लेकिन हिंसा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी हार होती है। जीते या हारे दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस हिंसा में कई लोग जान गंवा बैठे हैं। इनमें भाजपा के प्रमुख नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ समेत कई लोगों की हत्याएं हो गई हैं। कुल मिलाकर राज्य में डर का माहौल है। बंगाल चुनाव के दौरान या बाद में हिंसा कोई नई नहीं है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि चुनाव में विजयी हुई भाजपा ने जनता से जो वादे किए हैं, उन पर खरा उतरे और यह दिखने भी चाहिए। राज्य में केंद्रीय बलों की संख्या बहुत है। साथ ही अब एक तरह से राज्य का पूरा तंत्र भी भाजपा के ही हाथ में है। इससे पहले की देर हो, उसे दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा के दोषियों को पकड़कर सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि लोग बदलाव महसूस कर सकें। प्रदेश का माहौल शांत हो और विकास कार्य गति पकड़ सकें। राज्य में कानून व्यवस्था में यह बदलाव दिखाई देना चाहिए। एक दो दिन में नई सरकार की ताजपोशी भी हो ही जाएगी। उससे पहले कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम नागरिक को कष्ट नहीं हो और दोषी किसी भी हाल में बचे नहीं। चुनाव आयोग को भी हालात की गंभीरता को देखते हुए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनानी पड़ी और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन केवल गिरफ्तारी कर लेना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण से ऊपर उठकर कानून के दायरे में लाया जाए। वर्षों से राज्य की राजनीति में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल एक दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा बन चुका है। सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संघर्ष का तरीका नहीं बदला। यही कारण है कि हर चुनाव के बाद तनाव, डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। यदि नई सरकार शुरुआत में ही उपद्रवियों को सख्त संदेश देने में सफल रहती है, तो इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि कार्रवाई केवल राजनीतिक विरोधियों तक सीमित रही और वास्तविक दोषियों को संरक्षण मिला, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। नेताओं को अपने समर्थकों को संयम और शांति का संदेश देना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत और प्रतिशोध की राजनीति अंततः समाज को ही कमजोर करती है। जनता विकास, रोजगार, शिक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था चाहती है, न कि भय और असुरक्षा का माहौल। चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब समय है कि राजनीतिक दल जनता की आकांक्षाओं को समझें और राज्य को स्थिरता तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र की असली ताकत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और कानून के सम्मान में होती है। यदि चुनाव परिणाम के बाद भी लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगे, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। इसलिए बंगाल में हिंसा के दोषियों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई होना लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है।

उम्मीद

बृजमोहन अग्रवाल

मोदी की भाजपा बंगाल का पुराना वैभव लौटाएगी

देश का विरोध करते-करते भगवान राम का विरोध करने वालों का यही हश्र होना था। यशस्वी प्रधानमंत्री शनरेंद्र मोदी और चुनावी रणनीति में बेहद चौकन्ने और अब तक के सर्वोच्च कुशल संगठनकर्ता केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की शानदार, दमदार और जानदार राजनयिक जुगलबन्दी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद अब बंगाल पर विजय हासिल करके देश को चौतरफा विकास की ओर आगे बढ़ा दिया है। भाजपा पश्चिम बंगाल की 293 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटों की जीत के साथ बंग भूमि को प्राचीन काल की तरह और उर्वर बनाने के लिए बेहद पुख्ता ढंग से काबिज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कश्मीर नीति का प्रखर विरोध करते हुए अपनी जान तक गंवाने वाले मां भारती के अजर अमर लाल और पश्चिम बंगाल में ही जन्में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज बंगाल में हर तरफ़ भगवा लहराने से संतृप्त हुई होगी। मैं डॉक्टर साहब के अमर बलिदान को याद करते हुए यही कहना चाहूंगा वंदे मातरम, तेरा वैभव अमर रहे मां...अब हम सभी बड़े गर्व से कह सकेंगे कि जहा जन्में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वह बंगाल भी हमारा है। अब गंगोत्री से गंगासागर तक हम सभी को पतित पावनी मां गंगा का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव परिणाम बंगाल के लोगों की सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का भव्य प्रदर्शन है। यह जीत देश की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ है। ये जीत सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है, ये सनातन की जीत है और घुसपैठ के विरोध की जीत है। यह जीत बंगाल में व्याप्त अनार्की (अराजकता) और कानून-व्यवस्था के समाप्त होने के विरुद्ध जनता का जनादेश है। पिछले 15-20 सालों से बंगाल का विकास रुक गया था और जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर थी, जिससे अब उन्हें मुक्ति मिली है। पश्चिम बंगाल की धरती पर भाजपा की यह प्रचंड विजय केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि उस विचार, उस संकल्प और उस बलिदान की गूंज है, जिसकी नींव अखंड भारत के शाश्वत प्रणेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। यह जीत उन सपनों की जीत है, जो उन्होंने एक अखंड, सशक्त और आत्मसम्मान से भरे भारत के लिए देखे थे। यह जीत उस राष्ट्रवाद की जीत है, जिसके लिए उन्होंने हर संघर्ष को स्वीकार किया और अंततः अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी तपस्या, त्याग और बलिदान आज हर कार्यकर्ता की प्रेरणा बनकर खड़ा है। यह विजय जन-जन के विश्वास, समर्थन और लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट आस्था का परिणाम है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से अभिनंदन है, जिनके अथक परिश्रम, निष्ठा और जनसेवा के भाव ने इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया है। भाजपा के नव नियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन के कुशल मार्गदर्शन से पार्टी को ऐसी सुनहरी जीत मिल सकी है। बूथ स्तर से लेकर प्रत्येक क्षेत्र तक कार्यकर्ताओं ने जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य किया, वही इस सफलता की असली ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं और जन जन में यह विश्वास है कि भाजपा बंगाल को उसका पुराना वैभव देने में अवश्य कामयाब होगी। पहले कांग्रेस फिर वामपंथी दलों और बाद में ममता बनर्जी की अत्याचारी और हिंदू दमनकारी सरकार की वजह से कुंद हो चुके हिंदुत्व ने आपसी प्रेम बंधुत्व और भाई चारे के माहौल में अपनी धर्म संस्कृति और संस्कारों के साथ ख़ुशी-ख़ुशी जीना शुरू कर दिया है। बंगाल के हिंदुओं के चेहरे में एक अपरिमित ख़ुशी झलक रही है। सबसे पहले अंग्रेजों ने उर्वर बंगाल की भूमि का विभाजन कर देश की आर्थिक-सामाजिक संस्कृति को चोट पहुंचाई। कालांतर में वामपंथियों ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल में शासन किया और नतीजा यह रहा कि जो राज्य कभी देश की राजधानी हुआ करता था और विकसित राज्यों की श्रेणी में था, वह आज नीचे से भी कहीं नहीं रहा। और फ़िर ममता बनर्जी का आतंक सिंडीकेट माफियाओं ने इस राज्य के लोगों के अमन चैन और ख़ुशहाल संस्कृति का सत्यानाश कर डाला। गत 45 साल यहां के धर्मिक और सामाजिक साथ ही मेहनती और लगनशील लोगों की आवाज को इन्हीं तथाकथित प्रगतिशील लोगों ने दबाकर रखा था जो बंगाल चुनाव परिणाम के रूप में साकार हुई है। बंगाल अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कुशल प्रशासनिक ढांचे में सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ साथ धार्मिक संस्कारों में फलीभूत होते हुए फ़िर से अपनी उर्वरता हासिल करते हुए देश को और विकसित करने में अपना शाश्वत योगदान देता रहेगा।

(लेखक रायपुर से भाजपा सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सोमनाथ से मिलती है एकता की सीख

वर्षगांठ

नरेंद्र मोदी

> सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी।

ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया

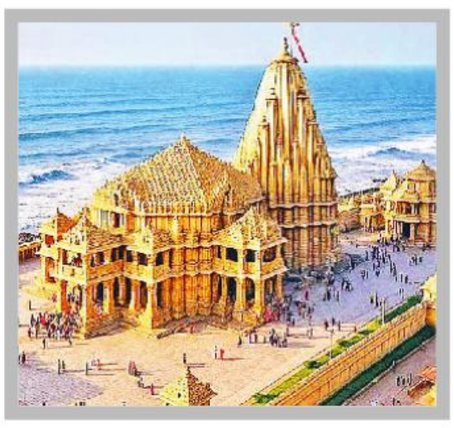

जाता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, ''इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।'' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होतें नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर 2001 को, सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं।

पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है। सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

बुरा मित्र जानवर से ज्यादा खतरनाक

संकलित

दर्शन

गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक बुरा मित्र किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बुरा मित्र हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसे जान-बूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है, इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी-मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। क्रोध को प्रेम से जीतें, बुराई को भलाई से जीतें। यह विचार प्रतिशोध के चक्र को तोड़कर करुणा और क्षमा को अपनाने का मार्ग दिखाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम चाहें कितनी ही अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुनें, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सभा में, परिषद में और एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो।

ईश्वर कैसे होते हैं प्रसन्न

संकलित

प्रेरणा

एक बार दुर्वासा मुनि, देवताओं की नगरी अमरावती में गए। पूरा शहर उत्सव की शोभा से दमक रहा था। दुर्वासा ने वहां उपस्थित नारद से इसके बारे में पूछा, इस उत्सव का क्या कारण है? देवर्षि नारद ने जवाब दिया, आज पूर्णिमा का दिन है। देवताओं के राजा इंद्र, माता अदिति की पूजा कर रहे हैं। उत्सव की वैभवपूर्ण तैयारियों को देखकर दुर्वासा मुनि आश्चर्य चकित हुए। सैकड़ों सुवर्ण थालियों में फूलों को सजाकर मां की पूजा के लिए रखे जा रहे थे। दुर्वासा मुनि इन तैयारियों के बारे में मां को स्वयं बताना चाह रहे थे। वे मां के द्वार पर गए। द्वारपालकों ने मुनि से कहा 'हे मुनिवर! मां बीमार हैं। आप उनसे अभी मिल नहीं सकते। द्वारपालकों की बातों को नजरंदाज कर मुनि सीधे मां के कक्ष में गए, जहां देव माता अदिति शैय्या पर लेटी हुई थीं। मुनि ने देवी से पूछा, 'मां! आप अस्वस्थ क्यों हैं? आप तो इससे परे हैं न?' देव माता ने नारद के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, 'यह सब देवेंद्र के कारण हुआ है, जो अपनी संपदा के दिखावे के लिए मेरी पूजा स्वर्ण पुष्पों से कर रहा है। उन स्वर्ण पुष्पों से ही मेरे शरीर पर घाव हो रहे हैं। दुर्वासा ने देवी से फिर पूछा, यह बताइए मां, आपका यह रोग कैसे ठीक होगा? मां ने जवाब दिया, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में एक व्यक्ति है, जो मेरी चिकित्सा करने में समर्थ है। दुर्वासा तुरंत वाराणसी गए।

अंतर्मन

आज की पाती

क्या किसी की भूख की तस्वीर लेना जायज है?

आज का युग 'डिजिटल करुणा' का युग बन चुका है, जहां इनसानियत, परोपकार और सहानुभूति जैसे मूल्य अब मौन संवेदनाओं की बजाय कैमरे की फ्लैश में दर्ज होते हैं। पहले जहां 'नेकी कर दरिया में डाल' की परंपरा जीवित थी, अब वह बदलकर 'नेकी कर, सोशल मीडिया पर डाल' हो चुकी है। भलाई की भावना मनुष्य की सबसे पवित्र प्रवृत्तियों में से एक है। किन्तु आज के समय में यह गुण मंच पर आ चुका है- एक ऐसा मंच जहां तालियां हैं, टिप्पणियां हैं, और सबसे ज़रूरी, एक कैमरा है जो हर क्षण को 'दृश्य' बनाता है। एक समय था जब कोई वृद्ध भूखा दिखता, तो राह चलते लोग बिना कुछ कहे उसे कुछ खाने को दे जाते थे। लेकिन अब किसी की भूख बुझाने की भी तस्वीरें ली जा रही हैं। - *गज्जू राम यादव, दुर्ग*

ट्रेंड

शासन का मूल्यांकन

हम यहां व्यवस्था का प्रबंधन करने नहीं, बल्कि उसे बदलने के लिए आए हैं। शासन का मूल्यांकन फाइलों की हेराफेरी या प्रस्तुत रिपोर्टों से नहीं, बल्कि प्राप्त परिणामों और बेहतर हुए जीवन से होता है।

- **एन चंद्रबाबू नायडू,** सीएम, आंध्र प्रदेश

कानून-व्यवस्था

बंगाल में हाल की घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। हमारे वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के एक करीबी सहयोगी की हत्या से कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। राजनीतिक मतभेदों के बीच हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

- **रेखा गुप्ता,** सीएम, नई दिल्ली

ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर, भारतीय सेना के वीर सैनिकों को हार्दिक सलाम। आपके अद्वितीय शौर्य ने राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आपकी बहादुरी ने उन कायर आतंकवादियों को दिखा दिया है कि हमारे देश पर किए गए घिनौने आतंकवादी हमलों का क्या अंजाम होता है।

-**अरविंद केजरीवाल,** पूर्व सीएम, नई दिल्ली

ईडी की रेड

ईडी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर के करीबी सहयोगियों के घरों पर छापा मारा। ईडी को आते देख इन लोगों ने नौवीं मंजिल से नोटों से भरे बैग फेंकना शुरू कर दिया। यही लोग सीएमओ में बैठकर दलाली करते हैं।

- **स्वाति मालीवाल,** राज्यसभा सदस्य

करंट अफेयर

शुभेंदु के सहयोगी की हत्या से बंगाल में बढ़ी हिंसा की आशंका

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा सत्ता परिवर्तन के रूप में सामने आने के महज 48 घंटे बाद वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या ने राज्य को ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहां चुनाव बाद की हिंसा के लोकतांत्रिक परिवर्तन पर भारी पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद छिटपुट झड़पों के रूप में जो शुरू हुआ था, वह अब तेजी से एक बड़े टकराव का रूप ले चुका है, जिसमें भय, प्रतिशोध का विमर्श और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों में क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई शामिल है। बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की तैयारी कर रही भाजपा के लिए यह हत्या एक चुनौती होने के साथ-साथ एक राजनीतिक अवसर भी है। चुनौती भावनात्मक रूप से आवेशित भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जवाबी हिंसा को रोकने की है जबकि अवसर भगवा खेमे के लंबे समय से चले आ रहे इस आरोप को पुष्ट करने का है कि तृणमूल शासन के तहत धमकियां, लक्षित हमले और मजबूत स्थानीय सत्ता नेटवर्क बंगाल की राजनीति में हिंसा की संस्कृति को दर्शाते रहे हैं। घटना को 'पूर्व नियोजित' बताते हुए, अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या करने से पहले कई दिन तक उनकी रेकी की गई।

ऑफ बीट

स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने कार्यबल का दिया प्रस्ताव

नीति आयोग ने देश में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यबल गठित करने की वकालत की है। साथ ही रचनात्मक और

छात्र केंद्रित शिक्षा के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को एकीकृत करने का सुझाव दिया है। 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: समयगत विश्लेषण एवं गुणवत्ता सुधार के लिए नीति ढांचा' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में आयोग ने स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 13 सिफारिशें दी हैं। पांच शैक्षणिक सिफारिशों में शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन एवं सीखने में बुनियादी बदलाव, समग्र शिक्षा एवं छात्र कल्याण पर जोर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल एकीकरण की पुनर्कल्पना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को मजबूत करना और शैक्षणिक नवाचार में एआई का एकीकरण शामिल हैं। इसके अलावा, आठ प्रणालीगत सिफारिशों में समग्र विद्यालयों एवं साक्ष्य-आधारित युक्तिकरण के माध्यम से विद्यालय संरचना में सुधार करना, विद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, शासन सुधार एवं प्रशासनिक क्षमता निर्माण करना, विद्यालय की गुणवत्ता पर राज्य व जिला स्तर पर कार्यबलों के जरिये 'समाज के समग्र दृष्टिकोण' को संस्थागत रूप देना तथा स्कूल प्रबंधन समितियों को सशक्त करना शामिल है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 8 मई, 2026 : ज्येष्ठ कृष्ण - 6 वि. 2083

धैर्य की नैया ही संकट में बेड़ा पार लगाती है

चुनाव बाद हिंसा का दुष्चक्र

पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान तो हिंसा से बच गया, लेकिन चुनाव बाद हिंसा से नहीं बच पा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी जिस तरह हिंसा जारी है, उससे पिछले विधानसभा चुनावों के बाद की भयावह हिंसा का स्मरण हो आया। तब ममता की सत्ता में वापसी हुई थी और उनके नेता-कार्यकर्ता निरंकुश होकर विरोधी दलों के समर्थकों पर टूट पड़े थे। उस समय ममता ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है। इस बार वे इस खोखले तर्क की आड़ में छिपती दिख रही हैं कि चूंकि जीत भाजपा को मिली है, इसलिए हिंसा रोकने की जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन यह ध्यान रहे कि अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बंगाल में हिंसा इसलिए हो रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता हार की खीझ भाजपा समर्थकों पर निकाल रहे हैं। ममता ने यह कहकर एक तरह से अपने समर्थकों को उकसाया ही है कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है और इसलिए वे त्यागपत्र नहीं देंगी। स्पष्ट है कि वे चुनाव बाद हिंसा भड़काने के आरोपों से बच नहीं सकतीं। स्पष्ट यह भी है कि तृणमूल समर्थक आतंकित करने वाली हिंसा का जो परिचय दे रहे हैं, वह उस हिंसक राजनीतिक संस्कृति की देन है, जिसे ममता ने पिछले 15 वर्षों में उसी तरह संरक्षित किया, जैसे एक समय वाम दलों ने किया था।

बंगाल में आतंक मचा रहे हिंसक तत्व कितने अधिक दुस्साहसी हैं, इसका खौफनाक प्रमाण है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मार कर हत्या। सुवेंदु का यह आरोप सच हो तो हैरानी नहीं कि रथ की टारगेट किलिंग इसलिए हुई कि उन्होंने ममता को चुनावी मात दी। इस हत्या के साथ भाजपा समर्थकों को निशाना बनाने वाली अन्य हिंसक घटनाओं के पीछे तृणमूल समर्थकों का हाथ होने की भरी-पूरी आशंका इसलिए है, क्योंकि अतीत में भी उन्होंने ऐसी हिंसा की है और सब जानते हैं कि ममता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। यह अच्छा हुआ कि इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ीं ममता को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जब तक भाजपा सत्ता नहीं संभालती, तब तक चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को यह देखना होगा कि मौजूदा हिंसा पर कैसे लगाम लगे। वैसे तो चुनाव बाद 60 दिनों तक केंद्रीय बलों को बनाए रखने का फैसला लिया गया था, पर शायद उनकी तैनाती और बढ़ानी पड़े। जो भी हो, भाजपा को यह समझ आ जाना चाहिए कि उसके सामने अन्य अनेक चुनौतियों के साथ कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे को ठीक करने की गंभीर चुनौती है। उसे इस चुनौती का सामना करना ही होगा, क्योंकि इससे ही राज्य को पटरी पर लाया जा सकता है।

नकली दवाओं की बिक्री

दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी समेत एनसीआर के साथ ही बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में नकली दवाओं की बिक्री करने वाले संगठित गिरोह को ध्वस्त किया जाना सराहनीय है। गिरोह के सदस्य नकली दवाओं की आपूर्ति के साथ ही सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाएं हासिल कर उनकी पैकिंग बदलकर बाजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर करीब छह करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवाएं बरामद की हैं। ये दवाएं कैंसर, लिवर संबंधी रोगों के साथ ही अन्य गंभीर बीमारियों से संबंधित थीं।

दिल्ली पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाजार में मौजूद नकली दवाएं तत्काल जब्त करें

ये गंभीर चिंता की बात है कि दिल्ली में संगठित गिरोह नकली दवाएं बेच रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पूर्व पिछले माह में भी दिल्ली में करोड़ों की नकली दवाएं पकड़ी गई थीं और छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ था। नकली दवाओं की राजधानी में बिक्री दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को बाजार में उपलब्ध नकली दवाओं को तत्काल जब्त करना चाहिए और आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कांग्रेस का द्रमुक से किनारा करना राजनीतिक अवसरवाद है?

आज का सवाल

क्या तमिलनाडु के राज्यपाल ने जोसेफ विजय के सरकार बनाने के दावे को ठुकरा कर सही किया?

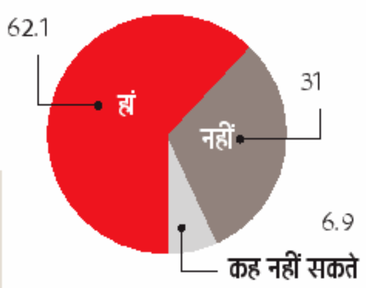

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

बंगाल के खोए गौरव को बहाल करने की चुनौती

कंचन गुप्ता

बंगाल में बहुत कुछ गलत हुआ हैं और उसे सही करने के लिए भाजपा की नई सरकार को द्रुत गति के साथ अविलंब प्रयास करने होंगे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसे याद रखने के कई कारण हैं। जिस भाजपा को एक समय राज्य में सत्ता की होड़ से बिल्कुल बाहर समझा जाता था, उसने न केवल ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बल्कि उस तृणमूल कांग्रेस को ऐसी करारी हार का सामना भी करना पड़ा, जो स्वयं को अपराजेय समझने लगी थी। हार को गरिमा के साथ स्वीकार करने के बजाय ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर और केंद्रीय सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती जैसे निर्वाचन आयोग के असाधारण कदमों का हवाला देकर भाजपा की जीत को अवैध ठहराने पर तुले हैं, लेकिन उनके इस रुख-रवैये को जनता के किसी कोने से न तो कोई समर्थन मिलता दिख रहा है और न ही उनके प्रति कोई सहानुभूति दिखती है।

दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो उसकी जीत के इस पैमाने की कल्पना भी कठिन है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जनता के असंतोष को पहले ही भांप लिया था और वह इस आक्रोश को व्यवस्थित तरीके से अपने पक्ष में भुनाने के लिए जुट गया। ममता बनर्जी की नाक के नीचे ही वर्षों से इसकी तैयारी चल रही थी और वे उसे अनदेखा करती रहीं। उनका कोई सहयोगी भी उन्हें यह समझा नहीं पाया। इसका ही परिणाम रहा कि भाजपा के विजयी रथ ने तृणमूल कांग्रेस के किले को कुचल दिया। इसके पीछे भाजपा के पक्ष में हिंदुओं के ध्रुवीकरण को एक वजह बताया जा रहा है, जिसके समक्ष ममता बनर्जी की मुस्लिम गोलबंदी बौनी साबित हुई। यह व्याख्या सतही तौर पर ही सही है, क्योंकि इसमें वे महत्वपूर्ण पहलू अनदेखे ही रह जाएंगे, जो बंगाल के राजनीतिक पटल पर तूफान की थाह लेने के लिए आवश्यक हैं। भाजपा के इस तूफान ने उन घेराबंदियों को ध्वस्त करने का काम किया, जिनकी व्यूह रचना उस पर बाहरी पार्टी का ठप्पा लगाते हुए उसे सुनियोजित तरीके से हमेशा के लिए राज्य की सत्ता से दूर रखने के लिए ही रची गई थी।

कुछ लोग यह दलील भी दे सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा और आपराधिक तत्वों का विरोध भी केवल सड़कों पर भीड़ को लामबंद करने तक ही सीमित होकर रह गया है। हालांकि बंगाल के नतीजे ऐसी धारणाओं को धता बताते हैं। बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके तृणमूल शासन के विरुद्ध अपने मतदान से आक्रोश प्रकट किया। लोगों के जेहन में ममता के बेहद करीबी मंत्री के यहां से जब्त हुई भारी नकदी की तस्वीरें ताजा रही हैं। उन हजारों शिक्षकों के

अवधेश राजपूत

साथ ही असंख्य बंगाली मध्यवर्ग की पीड़ा भी चुनाव परिणाम में अभिव्यक्त हुई, जो तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से छले गए थे, क्योंकि सरकार के कर्ताधर्ताओं ने रिश्वत लेकर उनके अवसरों पर डाका डालने का काम किया। इसी तरह असंवेदनशील या कहें उदासीन प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की मिलीभगत वाले आपराधिक रवैये को भी मतदाताओं ने सबक सिखाकर दंडित किया है। 'बंगाल में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं' जैसे दावों का तब कोई मूल्य-महत्व नहीं रह जाता, जब वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत दिखती हो। बंगाल इस मामले में कुख्यात होता गया कि अव्वल तो यहां पुलिस पीड़ित की शिकायत ही दर्ज नहीं करती और यदि किसी तरह वह दर्ज भी हो जाए तो यहां दोष सिद्धि एवं अपराध के लिए दंडित करने की दर सबसे कम है। जहां दूसरे राज्यों में बाल विवाह का चलन घटा है, वहीं बंगाल में यह बढ़ने पर है। इसी राज्य में महिलाओं को सरेआम कोड़े मारे जाते रहे और राजनीतिक नेतृत्व उस पर मौन साधे रहा और यह चुप्पी सीधे तौर पर वोटों के गणित से जुड़ी रही।

यदि ममता को लगता था कि उनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की चरम सांप्रदायिक राजनीति की कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं होगी तो शायद वे उतनी चतुर नेता नहीं हैं, जितना उन्हें माना जाता है। उनके शासन में ही बंगाल में उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। राज्य में हिंदुओं को दरकिनार करते हुए उनके राज में कट्टर इस्लामिक तत्वों और जिहादियों को मिलते संरक्षण से उपजी पीड़ा ने एक आक्रोश का जन्म दिया। बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम से इस आक्रोश की आग में और घी पड़ा, जहां हिंदुओं को चिह्नित कर प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश की भारत के साथ सटी सीमा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जमात-ए-इस्लामी की जीत के साथ बंगाली हिंदू घर की देहरी पर दस्तक दे रहे खतरे को लेकर जागृत हो गए। यह एक तरह से ममता बनर्जी और उनके सांप्रदायिक शासन के विरुद्ध हिंदुओं को लामबंद करने वाला निर्णायक पड़ाव बना।

बंगाल के नतीजों ने यह भी दर्शाया कि मुफ्तखोरी वाली योजनाएं भी एक सीमा तक ही उपयोगी होती हैं। आज बंगाल में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आजीविका के लिए पलायन ही विकल्प रह गया और घर में रह गए केवल उनके आश्रित। एक समय वह भी था जब बंगाल से विज्ञानी, तकनीशियन, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, शिक्षक, डाक्टर और वकील जैसे प्रतिष्ठित बंगाली राज्य से बाहर जाते थे और जहां जाते, वहां के सम्मानित प्रबुद्ध वर्ग का हिस्सा बन जाते। अब बंगाल के पास ऐसी प्रतिभाओं का अकाल है। इसके बजाय वह घरेलू सहायिकाओं के लिए जाना जाने लगा है, जिन्हें लेकर चुनावों के दौरान तमाम मीम भी छाए रहे, क्योंकि मतदान के लिए उनमें से अधिकांश अपने राज्य गई थीं। यह मेरे जैसे तमाम बंगालियों के लिए बहुत अपमानजक और पीड़ादायक होने के साथ ही निराश करने वाला अनुभव भी रहा।

बंगाल में बहुत कुछ गलत हुआ है और उसे सही करने के लिए भाजपा को द्रुत गति के साथ अविलंब प्रयास करने होंगे। एक 'नए बंगाल' का निर्माण और 'दूसरे पुनर्जागरण' का आविर्भाव संभव है। बंगाल के पास इन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के पर्याप्त साधन और सामर्थ्य मौजूद हैं। कमी रही तो केवल नेतृत्व की। अब भाजपा को बंगाल के खोए उस गौरव को बहाल करना होगा, जिस पर कभी बंगाल और बंगाली दोनों गर्व करते थे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार हैं)
response@jagran.com

आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार

रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखने और पश्चिम एशिया के 'न युद्ध-न शांति' के दलदल में फंसे होने के बावजूद हाल के समय के दूसरे संघर्षों के मुकाबले आपरेशन सिंदूर को एक मानक अभियान के तौर पर देखना महत्वपूर्ण है। इस आपरेशन की सबसे खास बात थी-सैन्य ताकत का तीव्र और नियंत्रित तरीके से निर्णायक इस्तेमाल, ताकि संघर्ष-विस्तार में रहते हुए ऐसे रणनीतिक नतीजे हासिल किए जा सकें, जो सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। इसका उद्देश्य था, पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकी नेटवर्क के गढ़ पर सीधा हमला करना और अगर पाकिस्तानी सेना जवाब देती है, तो उसे भारी नुकसान पहुंचाना। यह एक जिम्मेदार ताकत द्वारा राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के बार-बार दोहराए जाने वाले कृत्यों को सजा देने के लिए चलाया गया एक सटीक और संयमित प्रतिरोधी अभियान था।

हालांकि भारत ने 2019 में बालाकोट में आतंकरोधी अभियान में आक्रामक हवाई शक्ति के इस्तेमाल का प्रयोग किया था, पर इस बार जैश और लश्कर के मुख्यालयों पर हमले की तत्परता ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जोखिम उठाने की नई प्रवृत्ति और संघर्ष बढ़ाने की इच्छाशक्ति को उजागर किया। इसमें यह सोच स्पष्ट थी कि एक व्यापक संघर्ष भारत के हित में नहीं है, भले ही पाकिस्तान को और अधिक नुकसान पहुंचाने का सैन्य प्रलोभन मौजूद हो। भारत ने आपरेशन सिंदूर के दौरान कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं होने दिया और सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद पाकिस्तान के युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चार दिनों के भीतर ही संघर्ष समाप्त करने से जो सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हुई, उसने पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष के दौरान भारत की आर्थिक सहनीयता में योगदान दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका के 27 अरब डालर से भी ज्यादा खप चुके हैं और तनाव अभी भी कायम है।

आपरेशन सिंदूर की तैयारी के चरण में केंद्रीकृत नियंत्रण का एक स्पष्ट माडल देखने को मिला। इसके पहले स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय

डा. अर्जुन सुब्रमण्यम

पाकिस्तान के विरुद्ध आपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया है

आपरेशन सिंदूर में ध्वस्त जैश का आतंकी अड्डा ● एएफपी

सुरक्षा सलाहकार और रक्षामंत्री थे, जबकि दूसरे पर सीडीएस और तीनों सैन्यप्रमुख। सेना प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट और ठोस रणनीतिक परिणाम बताए गए थे। इससे उन्हें व्यावहारिक कार्ययोजना बनाने में मदद मिली।

भले ही हजारों सालों में युद्ध के स्वरूप में कई बदलाव आए हों, लेकिन कौटिल्य, सुन जू, क्लाजविट्ज, लिडेल हार्ट जैसे रणनीतिकारों द्वारा बताए गए युद्ध के अधिकांश मूल सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया। भारत ऐसा इसलिए कर पाया, क्योंकि इसने समय की कसौटी पर खरे उतरे युद्ध के कुछ सिद्धांतों और संकट के समय फैसले लेने के तरीकों का पालन किया। वायु सेना के इस्तेमाल का फैसला एक साहसी कदम था, जो आज के संघर्षों के बदलते स्वरूप को दिखाता है और जिस पर बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। चीन से मिली पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने और उन्हें जाम करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में घुसकर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में मौजूद लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने अपने हमले का दायरा और बढ़ाया तथा नूर खान, सियालकोट, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी, जैकोबाबाद एयरबेस जैसे 11 प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की सामरिक क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा। हवाई हमलों की तीव्रता से यह साफ हुआ कि पाकिस्तान को पहुंची क्षति 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई अड्डों को पहुंचाए गए कुल नुकसान से कहीं ज्यादा था।

आपरेशन सिंदूर ने भारत की एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली की परिपक्वता को भी साबित कर दिया, जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन-केंद्रित रणनीति का मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि वायुसेना को भविष्य में अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ किसी भी सीमित संघर्ष की स्थिति में अपने प्लेटफार्म, हथियारों और प्रणालियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए तेज गति से सीखने की आवश्यकता होगी। भविष्य के युद्ध-क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों से मुकाबले के लिए एकीकरण और तालमेल की जरूरत होगी। वर्तमान में चल रहे सुधारों और ढांचागत पहलों पर शायद फिर से विचार करना पड़े, ताकि एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा सके, जो आपरेशन सिंदूर के दौरान सीखे गए अनुभवों पर आधारित हो। हालांकि दुनिया भर में चल रहे संघर्षों से कई रणनीतिक सबक मिलते हैं, लेकिन भारत को दूसरी जगहों से युद्ध-लड़ाई के माडल अपने रणनीतिक और परिचालन वातावरण पर लागू करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। मिसाइल और ड्रोन पर ज्यादा जोर देने के समर्थकों को फिर से सोचना चाहिए। भारत के पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर जैसा हवाई माहौल है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, वहां सिर्फ बहुक्षेत्रीय परिचालन ही सफल होंगे।

(लेखक सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विचार और भाग्य

मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनने लगता है। जब हम किसी विचार पर गहरा विश्वास कर लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है और उसी दिशा में हमारे व्यवहार, निर्णय तथा परिस्थितियां आकार लेने लगती हैं। मानव मस्तिष्क का केवल एक छोटा भाग सचेत अवस्था में सक्रिय रहता है, जबकि उसका विशाल हिस्सा अवचेतन स्तर पर कार्य करता है। यही कारण है कि हम जिन विचारों को बार-बार दोहराते हैं, वे धीरे-धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। विचार कर्म का आधार बनते हैं, कर्म से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र अंततः हमारे भाग्य को दिशा देता है।

सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोजने की प्रेरणा देता है, जबकि नकारात्मक सोच उसे भय, भ्रम और निराशा में उलझा देता है। एक ही परिस्थिति को दो व्यक्ति अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं-एक उसे चुनौती मानकर आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा उसे विपत्ति समझकर निष्क्रिय हो जाता है। हमारे विचार केवल मन तक सीमित नहीं रहते, वे हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के माध्यम से एक प्रकार का परिवेश भी निर्मित करते हैं। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों की दिशा पर सतत निगरानी रखें। सकारात्मक विचारों को बार-बार दोहराना और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाना आत्मविश्वास को मजबूत करता है।

इसके लिए कुछ सरल उपाय अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं-नियमित ध्यान और साधना, सकारात्मक संगति, प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन, स्वास्थ्य के प्रति सजगता तथा प्रतिदिन जीवन की छोटी-छोटी उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। साथ ही स्वयं से सकारात्मक संवाद करना और नकारात्मक विचारों को चुनौती देना भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों के स्वामी बनें, क्योंकि वही हमारे भविष्य के बीज हैं।

एसएन दुबे 'स्नेही'

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

आंतरिक सुरक्षा तंत्र भी हो मजबूत

'सामरिक तैयारी को देनी होगी और धार' शीर्षक से लिखे आलेख में हर्ष वी. पंत ने आपरेशन सिंदूर की सटीक विवेचना की है। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी और सैन्य ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के प्रति कठोर और निर्णायक नीति अपनाने को तैयार है। आतंकवाद का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि देश अपनी सामरिक क्षमताओं और रणनीतिक तैयारी को और अधिक मजबूत बनाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका त्वरित और प्रभावी उपयोग किया जा सके। तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय के लिए सरकार पहले ही चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था लागू कर चुकी है। अब तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ-साथ संगठनात्मक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा, ताकि सामरिक बदलाव स्थायी रूप से स्थापित हो सकें। हालांकि बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी उतना ही मजबूत बनाना आवश्यक है। पहलगाम हमले जैसी घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि गुप्तचर तंत्र, निगरानी व्यवस्था और आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सरकार को देश के भीतर सक्रिय आतंकी तत्वों, विदेशी फंडिंग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे नेटवर्क पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। आतंकवाद को आर्थिक सहायता पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी समय की मांग है। यदि आंतरिक सुरक्षा तंत्र को 24 घंटे सक्रिय, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए, तो भविष्य में आतंकी साजिशों और निर्दोष लोगों की हत्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भीतर शांति, स्थिरता और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने से भी जुड़ी हुई है।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव, उप्र

राजनीति में परिवारवाद

भारतीय राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला है। बंगाल विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद कहा गया कि वहां परिवारवाद की हार हुई है, क्योंकि ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। तमिलनाडु में स्टालिन अन्य कारणों के अतिरिक्त इस वजह से भी हारे कि वह अपने पुत्र उदय निधि जो इस समय उन्हीं की सरकार में मंत्री भी हैं को अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपना चाहते थे। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव आदि, शिव सेना में उद्धव ठाकरे एवं आदित्य ठाकरे, राकांपा में सुप्रिया सुले, सपा में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव आदि, बसपा में मायावती के भतीजे आकाश, आनंद आदि सभी परिवाद वाद की देन हैं। एनडीए भी इससे अछूता नही है। बिहार मंत्रिमंडल में अध्यक्ष नीतीश के पुत्र निशांत भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

अमेरिका-ईरान तनाव में नरमी

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव में नरमी के संकेत पूरी दुनिया के लिए राहत भरी खबर हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर चर्चा तथा सैन्य गतिविधियों में कमी की घोषणाओं ने वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संदेश दिया है। इसका प्रभाव तुरंत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई दिया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और दुनिया के कई शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व अर्थव्यवस्था आज भी पश्चिम एशिया की स्थिरता पर बहुत हद तक निर्भर है। अमेरिका व ईरान के बीच संघर्ष केवल दो देशों का विवाद नहीं है। इसका सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार, वैश्विक महंगाई व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा पैदा हो जाता है और पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल से लेकर खाद्य वस्तुओं तक की कीमतें प्रभावित होती हैं। अमेरिका द्वारा आपरेशन एपिक फ्यूरी और आपरेशन फ्रीडम जैसे सैन्य अभियानों को रोकने का निर्णय यह संकेत देता है कि वाशिंगटन अब टकराव की जगह कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहता है। आर्थिक प्रतिबंधों व बंदरगाहों की नाकेबंदी से दबाव झेल रहे ईरान ने भी अपने रुख में कुछ नरमी दिखाई है।

विभूति बुपक्या, दिल्ली

पोस्ट

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इन्कार करके ममता बनर्जी एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार कर रही हैं, जो खेल हारने पर चिल्लाता है और कहता है कि धोखा हुआ है।

मार्कण्डेय काटजू@mkatju

बंगाल में पराजित मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के निजी सहायक की सरेआम सुनियोजित हत्या कर दी जाती है। अगर इससे भी शेष भारत बंगाल में कायम शासन के ढांचे को नहीं समझ पाता तो फिर उसे कैसे समझाया जाए।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

ईश्वर करे कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक में जुगलबंदी वाली बात सही न हो, लेकिन यदि ऐसा होता है, तो यह बहुत बड़ी दगाबाजी और अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा होगी। द्रविड़ राजनीति करने वाले दोनों दलों को जनता ने नकार दिया है। अगर द्रमुक पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करेगी तो वह विश्वासघात ही होगा। एस. गुरुमूर्ति@sgurumurthy

आप सांसद भाजपा में शामिल हों तो अलोकतांत्रिक है, पर तमिलनाडु में कांग्रेस द्रमुक का साथ छोड़ टीवीके से जुड़े तो लोकतंत्र का शिखर। अभिषेक@AbhishBanerj

जनपथ

राहुल का दल बन गया अब तो 'मुस्लिम लीग',
बालू में सिर गाड़ कर रहो हांकते डींग।
रहो हांकते डींग मिलेगी ना यूं सत्ता,
ले बस मुस्लिम वोट फोड़िए अपना मत्था।
हारें बारम्बार पार्टी की बती गुल,
किंतु समझने हेतु न राजी दिखते राहुल!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 293

जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है।

– अब्दुल कलाम

हिंसा का सिलसिला

पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान और उसके बाद हिंसक घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। विडंबना यह है कि इस तरह की घटनाओं की निंदा तो सभी दल करते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता, ताकि हिंसा के हालात बनें ही नहीं। गौरतलब है कि राज्य में इस बार विधानसभा के लिए हुए चुनावों के दौरान कोई बड़ी हिंसक घटना सामने नहीं आई, लेकिन नतीजे आने के बाद जैसी खबरें आ रही हैं, उससे साफ है कि हिंसा का सहारा लेने वाले असामाजिक तत्त्वों को रोकने के मद्देनजर एहतियातन कुछ भी नहीं किया गया। नतीजतन, बुधवार को राज्य में भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायक सहित पांच लोगों की हत्या की खबर आई। इसके अलावा, कई लोग घायल भी हुए। पहले से ही वहां इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी कि चुनाव प्रचार के दौरान आक्रामक खींचतान का असर नतीजों के बाद टकराव के तौर पर सामने आ सकता है। मगर ऐसी स्थितियों से निपटने में प्रशासनिक विफलता का ही यह नतीजा है कि राज्य में कई जगहों पर हिंसा और अराजकता के हालात पैदा हुए।

सवाल है कि आखिर किन वजहों से राज्य प्रशासन इस बात का आकलन करने में नाकाम रहा कि चुनावी नतीजों के बाद मुख्य राजनीतिक पक्षों के बीच का तनाव हिंसा में भी फूट सकता है। चुनाव के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की वजह से शांतिपूर्ण तरीके मतदान संभव हो सका, तो क्या ऐसा बाद में भी नहीं हो सकता था? राज्य के चुनावों में एक समय ऐसे तनाव और टकराव के पक्ष अलग थे, लेकिन वहां की सियासी तस्वीर में समय के साथ हुए बदलाव के बाद अब वहां के दो प्रतिद्वंद्वी दल मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं। करीब पंद्रह वर्ष बाद वहां तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद राज्य में कई जगहों पर सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बावजूद हिंसक झड़प और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में तोड़फोड़, आगजनी और उनके समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के घरों तक पर हमले की खबरें यह बताती हैं कि राजनीतिक दलों के बीच अपने विरोधियों के प्रति लोकतांत्रिक उदारता दिखाने की औपचारिकता भी खत्म होती जा रही है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हिंसक घटनाओं के दो सौ से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई और करीब साढ़े चार सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मगर जो काम पुलिस और प्रशासन ने स्थिति बेलगाम हो जाने के बाद किया, अगर पहले ऐसे कदम उठाए जाते, तो शायद कई जगहों पर हिंसा को रोका जा सकता था।

यह समझना मुश्किल है कि जो लोग नाहक या फिर प्रतिक्रिया के तौर पर हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं, वे आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर आक्रामकता और अराजकता का सहारा लेकर ऐसे लोग क्या साबित करना चाहते हैं? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति चुनावी नतीजों का विश्लेषण करता है और परिपक्व तरीके से उस पर सभ्य प्रतिक्रिया देता है। अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक दलों और उनके शीर्ष नेतृत्व की ओर से अपने समर्थकों को नियंत्रित रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध या समर्थन जाहिर करने को लेकर शायद ही कभी कोई संदेश जारी किया जाता है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूर्वसावधानी के तौर पर ऐसे ठोस कदम नहीं उठाता, जिससे अराजकता को शुरू होने से पहले रोका जा सके।

बढ़ता जोखिम

पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव में बुधवार को आवारा कुत्तों के एक बच्ची पर हमले की घटना ने एक बार फिर सभी को झकझोर दिया है। कुत्तों के झुंड ने बच्ची को उस समय नोंच कर मार डाला, जब वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। सवाल है कि अगर इलाके में कुत्ते आक्रामक हो गए थे, तो समय रहते स्थानीय शासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया। जबकि जोखिम बन गए कुत्तों को लेकर शीर्ष अदालत की ओर से स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। मगर यह दायित्वबोध किसी भी स्तर पर नहीं दिखता। पंजाब में जो हुआ, वह कोई अकेली घटना नहीं है। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। इन्हीं कारणों से लोगों का आक्रोश भी फूटा और हिंसक कुत्तों को निशाना बनाया गया। होशियारपुर जिले में आवारा कुत्तों का समूह हिंसक हो चुका है, तो उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? समय रहते उनकी पहचान कर ली जाती और उन्हें आश्रय गृह में भेज दिया जाता, तो मासूम बच्ची की जान नहीं जाती।

यह एक विचित्र विडंबना है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाना सरकारी महकमों को जरूरी नहीं लगता है। अदालत में महीनों चली सुनवाई और उस पर आए निर्देशों के बाद भी आम लोगों, खासकर बच्चों की जान जोखिम में है। देश भर में इस मुद्दे पर चिंता जताए जाने और मामले सुर्खियों में आने के बावजूद संबंधित विभागों और अधिकारियों का रवैया अब भी उदासीन दिखता है। रिहाइशी इलाकों से हिंसक कुत्तों को हटाने की कोई कवायद नहीं हो रही, तो इसे अब गंभीरता से लेना होगा। अगर नगर निकाय और जिला प्रशासन निर्देशों की अवहेलना करेंगे, तो आखिर आम लोग कहां जाएंगे। निकायों से पूछा जाना चाहिए कि हिंसक हो गए कुत्तों को पकड़ने तथा उन्हें आश्रय गृहों में रखने की हिदायत दी गई थी, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? आवारा कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं, तो तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। नगर निकायों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस दिशा में अब सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास की जरूरत है।

जय सोमनाथ

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंतकाल की अनूभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है।

नरेंद्र मोदी

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीने के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंतकाल की अनूभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है- प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा।

यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को दिवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश, इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विचार को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला।

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है।

1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद डा राजेंद्र प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्तूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्तूबर 2001 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डा राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है।

पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है।

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं।

सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है।

मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं।)

देखने समझने के बीच

विजय सिंह अधिकारी

देखने और समझने के बीच एक सूक्ष्म-सी दूरी है, पर यही दूरी धीरे-धीरे जीवन को एक अनकही थकान में बदल देती है। हम जीवन भर देखते रहते हैं- चेहरे, सड़कें, भीड़, घटनाएं, समाचार- पर उन्हें समझने का ठहराव जैसे हमारी दिनचर्या से धीरे-धीरे विलुप्त हो गया हो। जीवन हमारे सामने घटता रहता है, पर उसका अर्थ भीतर पहुंचने से पहले ही कहीं फिसल जाता है, जैसे कोई नदी रेत में समा जाए और हम केवल उसकी नमी को महसूस कर सकें, प्रवाह को नहीं। 'समय ने समय से कहा होगा कि मैं वही हूं, जो हर युग में अपने अर्थ बदल लेता हूं- कभी प्रतीक्षा बनकर, कभी गति बनकर और कभी उस मौन ठहराव की तरह, जो किसी अनुभव के बाद मनुष्य के भीतर बच जाता है।' शायद इन्हीं पंक्तियों में देखने और समझने के बीच की पूरी कथा छिपी है- एक ऐसी कथा जो हर युग में लिखी जाती है, पर कभी पूरी नहीं होती। इसी संदर्भ में यह कहावत भी सटीक प्रतीत होती है- 'आंखों देखी पर यकीन कर लेते हैं, पर समझी हुई बात जीवन बदल देती है।'

आज यह दूरी और भी सूक्ष्म होकर सर्वव्यापी हो गई है। मोबाइल फोन ने देखने को गति नहीं दी, उसने देखने को एक निरंतर प्रवाह में बदल दिया है। अब दृश्य रुकते नहीं, वे बहते हैं। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, दिनभर सूचनाओं की अनवरत दस्तक और रात तक अनगिनत चित्रों का सिलसिला- जैसे दुनिया अब कोई स्थिर यथार्थ नहीं, बल्कि एक निरंतर संपादित होती हुई फिल्म हो। दिल्ली मेट्रो में एक युवक अपने मोबाइल में लगातार रील बदल रहा था। एक दृश्य की हंसी अभी पूरी भी नहीं होती कि दूसरा दृश्य शुरू हो जाता था। मृत्यु, विवाह, विज्ञापन, युद्ध- सब एक ही समतल पर समान गति से गुजरते हैं। उस गति में किसी भी दृश्य का भार नहीं बचता। उसी डिब्बे में एक वृद्ध महिला अपने बैग को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर वर्षों का धैर्य था, पर वह दृश्य नहीं बना, क्योंकि दृष्टि पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। दिल्ली में एम्स के बाहर हल्की बारिश में एक परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। समय वहां रुकता नहीं, फैल जाता है। पिता की आंखें दरवाजे पर जमी थीं, मां की हथेलियां आपस में बंधी थीं, बच्चा हर आहट पर सिहर उठता था। यह केवल प्रतीक्षा नहीं थी- यह समय का वह रूप था, जहां भय और आशा एक ही क्षण में सांस ले रहे थे। पर बाहर से देखने वाला इसे केवल 'कतार' कह देता है। यही वह बिंदु है, जहां देखने और समझने के बीच की सबसे गहरी दरार दिखाई देती है।

इसी तरह एक चौराहे पर एक बच्चा फूल बेच रहा था। हर बार लाल बत्ती पर वह आगे आता, हर हरी बत्ती पर पीछे छूट जाता। उसकी गति नियमों से नहीं, जीवित रहने की विवशता से तय थी। एक कार में बैठे व्यक्ति ने उसे देखा, क्षणभर ठहरा, फिर स्क्रीन में लौट गया। दृश्य पूरा था, पर अर्थ अधूरा रह गया। स्टेशन पर एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन छूट जाने के बाद भी उसी जगह खड़ा रहा। भीड़ आगे बहती रही, घोषणाएं बदलती रहीं, पर उसके भीतर समय जैसे एक बिंदु पर जम गया था। वह केवल यात्री नहीं था। वह छूटते हुए जीवन का एक मौन संग्रह था, जहां हर छूटना केवल यात्रा नहीं, स्मृति बन रहा था।

गांव में यह अनुभव और भी मौलिक हो जाता है। एक किसान सूखी जमीन को देखता है, पर उसकी दृष्टि केवल दरारों तक सीमित नहीं रहती। उसमें कर्ज की परतें, मौसम की अनिश्चितता, बीज की कीमत और आसमान की चुप्पी एक साथ जीवित रहती है। उसके लिए बादल केवल पानी नहीं, एक संभावना है- एक वादा जो पूरा भी हो सकता है और टूट भी सकता है। शहर का व्यक्ति मौसम एप देखकर भी असमंजस में रहता है, क्योंकि उसके पास सूचना है, पर वह व्याख्या नहीं, जो अनुभव से जन्म लेती है। किसी बस में बैठी महिला का दृश्य भी ऐसा ही था- गोद में सोता बच्चा, खिड़की से पीछे छूटता शहर, और चेहरे पर थकान की परतें। पर उस थकान के भीतर अनेक भूमिकाएं चल रही थीं- मां, कामगार, देखभालकर्ता और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझती एक चेतना। देखने वाला उसे केवल 'यात्री' कह देता है, पर समझने वाला उसमें एक पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा पढ़ लेता है।

धीरे-धीरे हमने अनुभव को सूचना में बदल दिया है। सड़क दुर्घटना हमें कुछ क्षण विचलित करती है, फिर अगली सूचना उसे ढक लेती है। अस्पताल की कतार दिखाई देती है, पर उसमें बैठे हर व्यक्ति का समय अदृश्य रह जाता है। किसी मजदूर की झुकी हुई चाल दिखती है, पर उसका पूरा दिन हमारी दृष्टि से बाहर रह जाता है। अब दृश्य आते हैं, पर ठहरते नहीं- और जो नहीं ठहरता, वह अर्थ नहीं बनता।

यहां समय एक मौन भूमिका निभाता है। वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह हमारी दृष्टि को भी आकार देता है। 'समय ने समय से कहा होगा कि यदि तुम तेज हो जाओगे, तो मनुष्य तुम्हें केवल देखेगा, समझेगा नहीं।' गति समय को दृश्य बना देती है, पर अर्थ को धुंधला कर देती है। ठहराव ही वह स्थान है, जहां अनुभव अपने पूरे रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि देखने और समझने के बीच की यह दूरी केवल तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि की संरचना में आया एक गहरा परिवर्तन है। यह परिवर्तन हमें संसार का साक्षी तो बनाता है, पर उसका सहभागी नहीं रहने देता।

शायद सबसे मौन विडंबना यही है कि हम जितना अधिक दुनिया को देख रहे हैं, उतना ही कम उसे भीतर उतार पा रहे हैं, क्योंकि जो केवल देखा गया है, वह स्मृति बन सकता है, पर जो समझा नहीं गया, वह जीवन नहीं बनता। वह बस एक गुजरती हुई छाया रह जाता है, जो हमारे सामने से भी निकल जाती है और हमारे भीतर से भी।

दुनिया मेरे आगे

गांव में किसान सूखी जमीन की दरारें देखता है, पर उसमें कर्ज की परतें, मौसम की अनिश्चितता, बीज की कीमत और आसमान की चुप्पी एक साथ जीवित रहती है। उसके लिए बादल केवल पानी नहीं, एक संभावना है- एक वादा जो पूरा भी हो सकता है और टूट भी सकता है। शहर का व्यक्ति मौसम ऐप देखकर भी असमंजस में रहता है।

संतुलन की चुनौती

दशकों से प्रस्तावित चंबल पुल, जो मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना क्षेत्र के सैकड़ों गांवों और उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित हो सकता है, एक बार फिर वन विभाग की असहमति के कारण अटक गया है। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। मध्य प्रदेश का इंदौर-दाहोद रेलमार्ग वर्षों से लंबित है, जबकि देश का अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिल्ली-मुंबई आठ लेन मार्ग राजस्थान के दर्रा क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान के कारण बाधित रहा। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्रों की रक्षा के नाम पर विकास परियोजनाएं बार-बार रुक जाती हैं। हालांकि पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, लेकिन समस्या यह है कि विकास कार्यों के लिए ली गई वन भूमि के बदले समुचित क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। वास्तविकता यह है कि क्षतिपूर्ति के रूप में वृक्षारोपण अक्सर केवल संख्या पूरी करने तक सीमित रह जाता है। पौधे और झाड़ियां लगा कर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, लेकिन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन की वास्तविक भरपाई नहीं हो पाती।।

– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

सत्ता के बरक्स

'नतीजों का संदेश' (संपादकीय, 5 मई) पढ़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की रणनीति और सामाजिक समीकरणों पर पकड़ बना कर तथा धरातल पर पूरे हो सकने वाले वादे करते हुए भाजपा मैदान में उतरी थी। इसका असर ऐसा हुआ कि तृणमूल के इरादे और वादे ध्वस्त होते चले गए। वर्ष 2011 से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का राजमद चूर हो जाना कोई छोटी बात नहीं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को भी प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा बनाया गया। महिलाओं और बेरोजगार युवाओं की आर्थिक सहायता के वादों का भी असर पड़ा। बंगाल में चौपट होती कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का माडल लागू करने का वादा शहरी और मध्यम वर्ग को भाजपा की ओर आकर्षित करने में सफल रहा।

– युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

भ्रष्टाचार का पुल

भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिर गया। भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाली विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा रात बारह बजे के आसपास गिरा। दिन में बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन इसी पुल से होता है। अगर उस समय ऐसी घटना होती, तो जानमाल का अधिक नुकसान होता, क्योंकि यह अतिव्यस्त मार्ग रहा है। यहां से लाखों यात्रियों का आवागमन होता है। इस पुल को लेकर लगातार आशंका जताई जाती रही, लेकिन सेतु की मरम्मत के लिए उपाय नहीं किए गए। हालांकि घटना के बाद प्रशासन सजग हुआ और समय रहते लोगों को सचेत कर दिया गया, लेकिन महज पच्चीस साल में अचानक सेतु का टूट कर गिर जाना व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न करता है। आखिर एक पुल की मियाद होनी चाहिए। पुराने जमाने में बनाए गए पुल और पुराने शासकों के बनाए किले तथा स्मारक आज भी खड़े हैं।

– मिथिलेश कुमार, भागलपुर

बदलाव की बयार

पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पश्चिम बंगाल की बागडोर इस पार्टी के हाथों जा रही है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 30 वर्ष, फिर वाम मोर्चा सरकार ने 34 वर्ष और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने 15 वर्षों तक राज किया। अब राज्य की जनता ने भाजपा को शासन करने का मौका दिया है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत उसके सभी नेताओं की एकजुटता, संघर्ष और अंत तक हार न मानने की मानसिकता का परिणाम है। दूसरी ओर ममता बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का अति आत्मविश्वास उनकी करारी हार के लिए जिम्मेदार है। नई सरकार के लिए नया अवसर है, तो सामने कई चुनौतियां भी रहेंगी।

– अनित कुमार राय टिंकू, धनबाद

अमर उजाला

प्रवाह

78

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 8 मई 2026

अपनी विरासत और जड़ों पर गर्व करना चाहिए तथा उन्हें संजोकर रखने के प्रयास करने चाहिए। - सोन्या मॉर्गन

सुरक्षा की चिंता

मंगलवार रात पंजाब के दो शहरों में सैन्य परिसरों के बाहर कुछ ही घंटों के अंतराल पर हुए दो धमाके एक बार फिर राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित तो करते ही हैं, इस सीमावर्ती राज्य में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के फिर से सक्रिय होने के संकेत भी दे रहे हैं। बेशक इन दोनों बम धमाकों, जिनकी जांच जारी है, में जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, पर इन घटनाओं ने राज्य के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर की पूर्व संध्या पर सैन्य प्रतिष्ठानों के पास हुए धमाके राज्य पुलिस की खुफिया विफलता को तो दर्शाते ही हैं, जमीनी सतर्कता बढ़ाए जाने की भी मांग करते हैं। राज्य पुलिस महानिदेशक ने इन घटनाओं के पीछे आईएसआई समर्थित साजिश का अंदेशा जताया है, जिसमें दम नजर आता है, क्योंकि हथियारबंद अलगाववादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जालंधर धमाके की जिम्मेदारी ली है, जिसे अक्सर आईएसआई एवं कनाडा से समर्थन मिलता रहा है और जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय भी आतंकवादी संगठन मानता है। बीते कुछ महीनों में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली कई घटनाएं हुई हैं। अप्रैल में पटियाला-राजपुरा रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट हुआ, चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर ग्रेनेड से हमला हुआ। जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस से पहले सरहिंद रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया गया। नवंबर 2025 में मोगा के सीआईए कार्यालय पर ग्रेनेड फेंका गया था। मार्च 2025 में अमृतसर के खंदवाला इलाके में धार्मिक स्थल के बाहर विस्फोट की घटना हुई थी। इन घटनाओं से साफ है कि सीमापार स्थित दुश्मन राज्य में अलगाववादी तत्वों को लगातार शह और समर्थन दे रहा है। अगर ऐसी घटनाओं पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया, तो आमजन में डर का माहौल फैल सकता है, क्योंकि इससे 1980-1990 के दशक की खौफनाक यादें ही ताजा हो रही हैं। ऐसे समय में, जब जांच एजेंसियां इन घटनाओं की जांच में तेजी से जुटी हैं, तब राजनेताओं द्वारा इसे राजनीतिक रंग देना

अपरिपक्वता का ही परिचायक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अनावश्यक बयानबाजी करने से परहेज करें, तो बेहतर होगा। इन दो धमाकों ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को एक नाजुक मोड़ पर ला दिया है, और सुरक्षा बलों को अब न केवल सीमापार की साजिशों का मुकाबला करना होगा, बल्कि राज्य के भीतर भी कड़ी सतर्कता बरतनी होगी।

विध्वंस से सृजन तक की एक यात्रा

जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई।

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: *प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्।* अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी।

माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार

चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, ने चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से भी धन्य हुई है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर, 1947 को, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। उनके उद्देश्य को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्तूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्तूबर, 2001 को, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी।

11 मई, 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।

सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें।

जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

edit@amarujala.com

मुद्दा

लोग हैं कि मानते ही नहीं

भारत की सड़कों पर हर दिन लगभग 470 लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह किसी युद्ध से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ है।

आज दुनिया का हर इन्सान अमेरिका-इस्राइल-ईरान के युद्ध पर नजरें टिकाए बैठा है, पर इसकी विभीषिका से कहीं ज्यादा दुखद हैं रोजाना होने वाली सड़क दुर्घटनाएं। भारत की सड़कों पर हर दिन लगभग 470 लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह किसी युद्ध से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ है, जिसे हरा देना भी सरल है। अगर हम मानें तो।

हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट को बोझ समझना, गति सीमा की लापरवाही, शराब पीकर ड्राइविंग, फोन का प्रयोग, गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाना, गलत लेन में चलना, लाल बत्ती को अनदेखा करना, ये सब हमारी आदत का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार ने नियम बनाए, जुर्माने लगाए, जागरूकता अभियान चलाए। फिर भी, हालात जस के तस क्यों हैं? क्योंकि समस्या जानकारी की कमी की नहीं, हमारी मानसिकता है। सड़क दुर्घटनाओं में ओवरस्पीडिंग लगभग 70 फीसदी मामलों में दुर्घटना का कारण बनती है। यह सरकारी आंकड़े हैं। दोपहिया चालकों की मौतों में बड़ी संख्या बिना हेलमेट वालों की होती है। तो आखिर कमी कहां है? जहां एक ओर लोग नियमों का पालन नहीं करते, वहीं दूसरी ओर चेकिंग व चालान करने में ट्रैफिक नियमों का पालन करने में ढिलाई बरती जाती है। सड़क डिजाइन, और संकेतों की अनदेखी करना भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। कई जगहों पर लेन मार्किंग, साइन बोर्ड, और स्पष्ट दिशा-निर्देश ही नहीं होते। कहीं तो, मुख्य सड़कों और हाईवे पर दूर-दूर तक गति-सीमा की चेतावनी बोर्ड नहीं लगे होते। सरकारी तंत्र भी जैसे कोई नवाचार नहीं ढूंढते। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही तो सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। गांव से लेकर शहरों तक एक ही कहानी है। अगर हम और प्रशासन सच में बदलाव चाहते हैं, तो कुछ सख्त निर्णय लेने होंगे। पहले, आदतन उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर, उनका रिकॉर्ड बनाया जाए। उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए, उनका लाइसेंस निलंबित हो, और उनकी अनिवार्य काउंसलिंग हो। एआई कैमरे, ऑटोमेटेड चालान, और 'नो-एस्केप' सिस्टम लागू हों, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न बचे। सड़क इंजीनियरिंग को प्राथमिकता दें। रचनात्मक संकेत, सड़क पर विजुअल मैसेज, और व्यवहार को प्रभावित करने वाले उपाय खोजें और लागू करें। स्कूलों से लेकर हर गांव, शहर में सड़क सुरक्षा की विशेष ट्रेनिंग हो। निवासीय संस्थाओं, एनजीओ और बेरोजगार युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियान में शामिल किया जा सकता है। छिटपुट स्थानों पर तैनात एक-दो पुलिस के सिपाही, चारों ओर फैले अनुशासनहीनता से कैसे जूझ पाएंगे! प्रवर्तन पर कई गुना अधिक बल देने पर ही सड़क सुरक्षा के प्रति डर, और व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह विषय जीवन-मृत्यु का विषय है, इसलिए इसके हल में कोई अगर-मगर की गुंजाइश नहीं है। अंत में फिर वही कठिन सवाल कि क्या हम बदलना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि समाधान हमारे पास ही है, कमी केवल इच्छाशक्ति और ईमानदारी की है। नागरिक और प्रशासन, दोनों की। हर बार जब हम नियम तोड़ते हैं, हम केवल कानून नहीं तोड़ते, बल्कि हम किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी को जोखिम में डालते हैं।

सुभाष नागपाल

'लोग हैं कि मानते ही नहीं...' यह वाक्य अब एक व्यंग्य नहीं, एक राष्ट्रीय संकट का बयान बन चुका है। अगर हमें इसे बदलना है, तो शुरुआत बाहर से नहीं अपने भीतर से, और अभी करनी होगी।

बीतता समय हमें और बेहतर बनाता है

युवावस्था में हम बेशक ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारी सोच, समझ व रचनात्मकता बढ़ती जाती है। धीरे-धीरे जिंदगी को देखने की हमारी दृष्टि व्यापक होती जाती है तथा हम जीवन को अधिक गहराई से समझ पाते हैं।

हम अक्सर युवावस्था में अपनी कमजोरियों से बचने के लिए खुद ही अपने रास्ते में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। जैसे समय की कद्र न करना, बेवजह की बातें करना, हर चीज को जरूरत से ज्यादा 'परिपूर्ण' बनाने की कोशिश करना या फिर दूसरों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक व्यवहार करना। ये छोटी-छोटी आदतें हमें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी प्रगति को रोकती हैं। कई बार हम इन्हें अपनी ताकत समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही आदतें हमें खिलने और आगे बढ़ने से रोक देती हैं।

रिच कार्लगार्ड

समाज में अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव युवावस्था ही है, पर सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी सोच, समझ व रचनात्मकता और भी बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी मानसिक क्षमताएं कम नहीं होतीं, बल्कि और भी बेहतर होती जाती हैं। हम समस्याओं को अधिक संतुलित तरीके से समझते हैं और उनके समाधान भी अधिक प्रभावी ढंग से निकाल पाते हैं। युवावस्था में जब कोई व्यक्ति सफलता हासिल कर लेता है, तो वह उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मानता है, पर जब जीवन में कोई कठिनाई या असफलता आती है, तो उसके लिए वही व्यक्ति खुद को या दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इसके विपरीत, ऐसे व्यक्ति, जो जिंदगी के खट्टे-मीठे अनुभवों से होकर गुजरते हैं, वे जीवन को अधिक संतुलित नजरिये से देखते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराते।

मुड़-मुड़ के देख

बुजुर्गों के अनुभव हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर उम्र का अपना महत्व है। युवावस्था में हम बेशक ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन उम्र के साथ हम समझदारी और धैर्य सीखते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जल्दी सफलता ही सब कुछ नहीं है। असली मूल्य उस समझ में है, जो समय के साथ विकसित होती है। उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे जिंदगी को देखने की हमारी दृष्टि व्यापक होती जाती है और हम जीवन को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। यही परिपक्वता हमें सच्चे अर्थों में सफल बनाती है।

ढलती उम्र कोई 'सूर्यास्त' नहीं है, जिसे देखकर दुखी हुआ जाए, बल्कि यह एक ऐसी 'भव्य शाम' है, जिसे शांति और संतुष्टि के साथ बिताया जाना चाहिए।
-मार्क ट्वेन

इस उम्र में चीजों का मोह स्वाभाविक है

घर की चीजों के मोह में फंसे अस्सी पार बीमार दंपती को मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने कुछ यों सलाह दी :

मेरी और मेरी पत्नी की सेहत ठीक नहीं रहती। हम अस्सी पार कर चुके हैं। हमें एक ऐसे घर की जरूरत है, जहां चिकित्सा सुविधाएं हों, पर वह सामान के कारण छोटे घर में जाना नहीं चाहतीं। मैं क्या करूं?

जिंदगी भर जुटाई गई चीजों का मोह स्वाभाविक है। लेकिन लगता है कि आपकी पत्नी को चीजें जमा करने की आदत है, जो जाहिर तौर पर एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। इसका कोई आसान हल नहीं है, खासकर उनकी उम्र को देखते हुए।

पर, आप दोनों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए, अब आप दोनों को सचमुच किसी देखभाल वाले आवास में रहने की जरूरत है, न कि किसी दूसरे घर में। वहां आप दोनों को वह देखभाल मिलेगी, जिसकी आपको जरूरत है। यही नहीं, आप लोगों से घुल-मिल पाएंगे, और आपको वह चिकित्सकीय मदद भी आसानी से मिल जाएगी, जिसकी जरूरत आपको अभी है और आगे भी रहेगी।

फिलहाल, आप अपनी पत्नी के इकट्ठा किए गए सामान को रखने के लिए पास में ही किराये पर अलग से स्टोरेज ले सकते हैं, ताकि उनको भी तसल्ली रहे कि उनका सामान सुरक्षित है। अगर आप उनका सारा सामान किसी स्टोरेज में रखवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पूरी संभावना है कि वह वहीं पड़ा रहेगा और जल्द ही आपकी पत्नी भी उसके बारे में भूल जाएंगी।

आमतौर पर, जो लोग चीजों को बहुत ज्यादा सहेजकर रखते हैं, उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या-क्या छिपाकर रखा है। यदि आपकी जगह मैं होता, तो कोशिश करता कि जितनी जल्दी हो सके, उन सारे सामान से छुटकारा पा लूं या फिर अपनी पत्नी को बिना बताए, जितना हो सके उसे दान कर दूं, अथवा परिवार के उन सदस्यों को दे दूं, जिन्हें उनकी ज्यादा जरूरत हो। आप सच में नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के जाने के बाद, परिवार वालों को उन गैर-जरूरी सामानों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी उलझन से निपटना पड़े। इसलिए बेहतर है कि आप अभी ही इससे निपट लें।

हो सकता है कि आपकी पत्नी को आपकी मर्जी के मुताबिक घर बदलना जरूरी न लग रहा हो। महिलाएं अक्सर पाई-पाई बचाकर घर-गृहस्थी का सामान जुटाती हैं, इसलिए सामान के प्रति उनका मोह स्वाभाविक है। संभव है कि आपके लंबे वैवाहिक जीवन में अक्सर ऐसा होता रहा हो, कि आपने थक-हारकर उनकी जिद मान ली हो और वह अब भी यही सोच रही हों कि अंततः आप हार मान लेंगे और उन्हें अपनी मर्जी का करने देंगे।

आप उन्हें परिवार के अन्य लोगों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करें कि उम्र के इस पड़ाव पर संपत्ति नहीं, स्वास्थ्य आप दोनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर वह फिर भी नहीं मानती हैं, तो उन्हें धमकी दें कि आप उनसे अलग होकर कहीं दूसरी जगह रहने चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सचमुच आप उनसे अलग हो जाएं, बस यह कहना चाह रहा हूं कि आप अलग होकर कहीं चले जाने का दिखावा तो कर ही सकते हैं, ताकि वह आपको गंभीरता से लें। उम्मीद है कि इस हालात में वह भी समझदारी से काम लेंगी।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

80 की उम्र में 'विंग-वॉक' जैसा रोमांचक स्टंट

इंग्लैंड की 80 वर्षीय जेनी थर्गुड ने अपने जन्मदिन को एक अनोखे और साहसिक अंदाज में मनाकर सबको प्रेरित कर दिया। उम्र के इस पड़ाव पर जेनी ने आसमान में उड़ते हुए विमान के पंख पर खड़े होकर 'विंग-वॉक' किया। इस रोमांचक स्टंट के दौरान उन्होंने न केवल अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उम्र इन्सान के सपनों और जुनून को सीमित नहीं कर सकती। उन्होंने 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे जहाज पर यह कारनामा किया। जेनी का मानना है कि जीवन में डर का सामना करते रहना जरूरी है। इससे पहले भी वह वेल्स की खदान के ऊपर जिप-वायर कर चुकी हैं और पोर्ट्समाउथ की प्रसिद्ध स्पिनेकर टॉवर से एब्सेलिंग (रस्सियों के सहारे किसी ऊंची जगह से नीचे उतरने की साहसिक गतिविधि) भी कर चुकी हैं। उनका साहस यह साबित करता है कि उम्र केवल एक संख्या है, असली ताकत इन्सान के हौसले और सोच में होती है।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- *शुभ रहे फाउंडेशन* बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की भलाई तथा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह ऐसे लोगों को भोजन, कपड़े और दवाइयां उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। मानवता और समाजसेवा की भावना के साथ यह हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट shubhrahefoundation.org.in या shubhrahefoundation@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
- *राजिका सोशल वेलफेयर एसोसिएशन* एनजीओ बुजुर्गों, बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करके वंचित समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है, जहां हर व्यक्ति को, आगे बढ़ने, सीखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट rswngo.org.in या Rswassociationngo@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

देश में और बढ़ेगी बिजली की मांग पावर शेयरों में दिख सकता है दम

रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान, वित्त वर्ष 2026-27 में 5 फीसदी रह सकती है मांग

बोनस डेस्क

नई दिल्ली। अगर आप 2026 में शेयर बाजार की उथल-पुथल से परेशान हैं तो थोड़ा धैर्य रखते हुए बिजली क्षेत्र की ओर नजर डालिए। जहां व्यापक बाजार दबाव में रहा, वहीं पावर शेयरों ने पिछले कुछ हफ्तों में निवेशकों को चौंकाया है। बीएसई पावर इंडेक्स ने पिछले एक महीने में करीब 21 फीसदी की मजबूत रैली दिखाई है। पिछले छह महीने में यह बढ़त करीब 24 फीसदी तक पहुंच गई है। यह तेजी सिर्फ बाजार की चाल नहीं, बल्कि देश की बदलती बिजली जरूरतों और ऊर्जा नीति का संकेत भी है।

गर्मी, कम बारिश की आशंका, एसी-कूलिंग की जरूरत, कृषि का भार और औद्योगिक गतिविधियों के कारण बिजली खपत में तेजी बनी रह सकती है। पावर शेयरों की बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजह देश में बिजली की यही खपत है। अप्रैल 2026 में भारत ने 256.1 गीगावॉट की अब तक की सबसे अधिक पावर मांग दर्ज की। इससे पहले मई 2024 में 250 गीगावॉट का रिकॉर्ड बना था। सरकार के मुताबिक, यह मांग बिना किसी कमी के पूरी की गई। बाजार की नजर अब बिजली और न्यूक्लियर वैल्यू चेन वाली कंपनियों पर है। एलएंडटी न्यूक्लियर ईपीसी में अहम भूमिका निभा सकती है। भेल टरबाइन, बॉयलर और महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति से जुड़ी है। एनटीपीसी और एनएचपीसी स्वच्छ ऊर्जा और न्यूक्लियर विस्तार में भूमिका निभा सकती हैं। टाटा पावर, अदाणी एनर्जी, एबीबी इंडिया और सीमेंस जैसी कंपनियां ग्रिड, ऑटोमेशन, ट्रांसमिशन और क्लीन एनर्जी थीम से जुड़ी हैं।

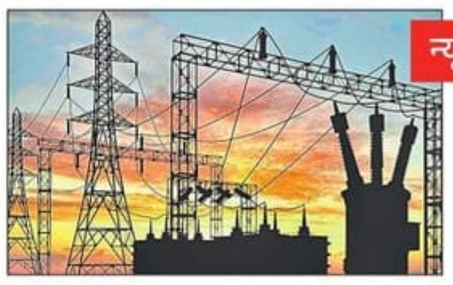

मांग बढ़ने के तीन प्रमुख कारण

बिजली की मांग बढ़ने के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला, गर्मी और मौसम का असर। तापमान बढ़ने से घरेलू और कृषि क्षेत्र में बिजली खपत तेज होती है। दूसरा भारत में डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण जैसे नए सेक्टर तेजी से मांग को बढ़ा रहे हैं। तीसरा, शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार से बेस डिमांड लगातार ऊपर जा रही है।

निवेशकों के लिए संकेत : बाजार विशेषज्ञ वीएलए अंबाला कहती हैं, अगले पांच वर्षों में क्षमता विस्तार, नीतिगत प्रोत्साहन और बिजली की बढ़ती मांग के कारण कच्चा तेल रहित ऊर्जा में मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि, रिटर्न सभी कंपनियों में समान नहीं रहेगा। जिन कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है, क्रियान्वयन क्षमता बेहतर है और जो स्टोरेज, ग्रिड तथा हाइब्रिड समाधानों पर काम कर रही हैं, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। शेयर चुनने में सावधानी जरूरी है।

न्यूक्लियर एनर्जी की अहमियत

बढ़ती मांग के बीच देश में ऊर्जा सुरक्षा का नजरिया भी बदल रहा है। अब सरकार और उद्योग का ध्यान परमाणु ऊर्जा की ओर मुड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 24 घंटे स्थिर बिजली दे सकती है। यानी, यह सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं रहती।

अगर एक गीगावॉट क्षमता वाले अलग-अलग बिजली स्रोतों की तुलना करें, तो तस्वीर साफ दिखती है...

ऊर्जा स्रोत	क्षमता गुणांक	सालाना उत्पादन
सौर ऊर्जा	18-22%	1,650 गीगावाट प्रति घंटा
कोयला	50-65%	4,500 गीगावाट प्रति घंटा
न्यूक्लियर	80-92%	7,500 गीगावाट प्रति घंटा

निजी बैंक बनेंगे दूसरे बैंकों की ताकत, आरबीआई ने दी अहम मंजूरी

बैंकिंग सेक्टर में मजबूत होगा बड़े खिलाड़ियों का प्रभाव, निजी बैंकों के कारोबार में बढ़ेगी पारदर्शिता

नई दिल्ली। अब निजी क्षेत्र के बड़े बैंक सिर्फ ग्राहकों की संख्या और मुनाफे की होड़ तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि एक-दूसरे के कारोबार और पूंजी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हालिया फैसले इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं।

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को अन्य बैंकों में हिस्सा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक को अपने समूह की अन्य कंपनियों के साथ आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कुल 9.95 फीसदी तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति मिली है। एचडीएफसी बैंक समूह में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एर्गो, एचडीएफसी पेंशन फंड और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक में 9.99 फीसदी तक हिस्सेदारी रख सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि ये बैंक दूसरे बैंकों का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। यह एक वित्तीय या रणनीतिक निवेश की तरह है। मजबूत बैंकिंग समूह अपने ही सेक्टर की अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के अवसर देख रहे हैं। इससे कमजोर बैंकों को सहारा मिल सकता है। बोनस डेस्क

बाजार पर क्या असर पड़ेगा: बैंकिंग शेयरों के लिए अब माहौल सकारात्मक हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र कुछ समय से जमा वृद्धि, मार्जिन दबाव और मूल्यांकन की चिंता से जूझ रहा था। ऐसे में बड़े बैंकिंग समूहों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी बाजार को यह संकेत देती है कि सेक्टर में लंबी अवधि की वैल्यू अभी बची हुई है। हालांकि, असर ज्यादा उन्हीं बैंकों पर दिखेगा जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और संपत्ति की गुणवत्ता बेहतर है। बैंकिंग सेक्टर के लिए यह भरोसे की खबर है।

ईसीएल प्रावधान नियमों से बैंकों पर दबाव नहीं : फिच

नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय बैंक आरबीआई के नए अनुमानित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) प्रावधान ढांचे को लागू करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र पर बड़े दबाव की आशंका नहीं है।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी बैलेंस शीट मजबूत की है, प्रावधान कवरेज बढ़ाया है और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया है। ऐसे में एक अप्रैल 2027 से लागू होने वाले ईसीएल ढांचे का असर सीमित रहने की संभावना है।

जापानी बाजार में रिकॉर्ड तेजी, येन स्थिर, बॉन्ड यील्ड नरम

नई दिल्ली। जापान का शेयर बाजार बृहस्पतिवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गया। निक्केई 225 इंडेक्स 5.6 फीसदी उछलकर 62,833.84 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, जबकि दिन के कारोबार में यह पहली बार 63,000 के ऊपर निकल गया। इस तेजी के पीछे दो बड़े कारण रहे, अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद और ग्लोबल टेक शेयरों में जोरदार खरीदारी।

जापान के लिए यह लगभग गोल्डीलॉक्स की स्थिति बनती दिख रही है। गोल्डीलॉक्स का मतलब है जब विकास, महंगाई और ब्याज दरों के बीच संतुलन हो। ये बाजार के लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है। तेल कीमतों में नरमी से आयातक कंपनियों और महंगाई दोनों को राहत मिल रही है। दूसरी ओर, येन में मजबूती से करेंसी में स्थिरता लौटी है। बॉन्ड बाजार ने भी राहत दी है। 10 साल की जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड घटकर 2.48 फीसदी पर आ गई। महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता कम हुई है। बोनस डेस्क

भारतीय बाजार को मिलेगा सहारा

जापानी बाजारों की यह तेजी सिर्फ स्थानीय संकेत नहीं है। एशियाई बाजारों में रिकॉर्ड स्तर, डॉलर में नरमी और कच्चे तेल में गिरावट जैसे संकेत भारतीय बाजार के लिए भी सकारात्मक रह सकते हैं। खासकर, भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए क्रूड में राहत, रुपये और इक्विटी बाजार दोनों को सहारा दे सकती है।

न्यूज डायरी

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 114 अंक गिरा

मुंबई। निवेशकों के सतर्क रुख के चलते बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 77,844.52 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 4.30 अंक गिरावट के साथ 24,326.65 पर रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, सन फार्मा और आईटीसी में गिरावट आई। महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक बैंक और टाटा स्टील लाभ में रहे। एफआईआई ने 340.89 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ब्यूरो

कोल इंडिया में सरकार बेच सकती है 4% हिस्सेदारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया में 3 से 4 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। 31 मार्च 2026 तक कोल इंडिया में केंद्र की हिस्सेदारी 63.13 फीसदी थी। एजेंसी

वाणिज्यिक जहाजों के लिए सब्सिडी पांच साल बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने वाणिज्यिक जहाजों के लिए सब्सिडी योजना को पांच साल के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जुलाई, 2021 में 1,624 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ इस सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई थी। एजेंसी

तेल के खेल से रुपया 27 पैसे मजबूत, सोने-चांदी में भी बढ़त

मुंबई। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी डॉलर सूचकांक के नीचे आने से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ 94.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 94.77 पर खुला।

कारोबार के दौरान यह 94.90 के निचले और 94.08 के उच्च स्तर तक पहुंचा। अंत में रुपया 94.22 प्रति डॉलर पर रहा जो पिछले बंद भाव से 27 पैसे की वृद्धि है। बुधवार को रुपया 69 पैसे मजबूत होकर 94.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। उधर, सराफा बाजार में सोना 600 रुपये बढ़कर 1,56,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को इसमें 2,900 रुपये की मजबूती दर्ज हुई थी। चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी रही। चांदी भी 7,000 रुपये उछलकर 2,61,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में इसमें 3,500 रुपये की बढ़त दर्ज की गई थी। एजेंसी

इमामी ने इंकनट में हासिल की 60 फीसदी हिस्सेदारी

कोलकाता। व्यक्तिगत देखभाल और हेल्थकेयर क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी इमामी ने इंकनट डिजिटल और उसकी सहायक कंपनियों में 60 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौता किया है। इस सौदे की कीमत 321 करोड़ रुपये है। इमामी लि. के वाइस चेयरमैन-एमडी हर्ष वर्धन अग्रवाल ने कहा, यह निवेश तेजी से बढ़ते सौन्दर्य और पर्सनल केयर सेगमेंट में मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। ब्यूरो

निर्यातकों को राहत देने की तैयारी, बढ़ सकता है कर वापसी योजना का दायरा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया युद्ध से उपजी अनिश्चितताओं के बीच सरकार निर्यातकों को राहत देने की तैयारी में है। सरकार निर्यात उत्पादों पर शुल्क व कर वापसी योजना (आरओडीटीईपी) की अवधि पांच साल तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच इस संबंध में चर्चा चल रही है। योजना में कृषि, वस्त्र और इंजीनियरिंग उत्पादों समेत 10,000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं। निर्यातकों को उत्पाद मूल्य का एक से चार फीसदी तक प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना फिलहाल 30 सितंबर तक लागू है। इसके तहत निर्यातकों को केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर उन करों और शुल्कों की भरपाई की जाती है जो अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं मिलते। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना का आवंटन लगभग आधा कर दिया गया था, लेकिन संकट गहराने के बाद प्रोत्साहन फिर से बहाल करना पड़ा। मार्च में वस्तु निर्यात में सालाना आधार पर 7.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। 30 निर्यात श्रेणियों में 24 में कमी देखने को मिली थी। एजेंसी

भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखना चुनौती

नए आधार वर्ष के हिसाब से तय होंगे राज्य व जिला जीडीपी

नई दिल्ली। भारत सरकार नए आधार वर्ष के हिसाब से सकल राज्य घरेलू उत्पाद व जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े तैयार कराएगी। इस संबंध में वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए अलग-अलग मानकों पर आंकड़े एकत्र होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पहली बार जिला घरेलू उत्पादों का नए मानकों पर आकलन होगा। जिला जीडीपी आंकड़े जिलों की स्थानीय आर्थिक संरचना एवं प्रदर्शन के बारे में सूक्ष्म जानकारी प्रदान करते हैं। ये विभिन्न जिलों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करने, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने तथा स्थानीय विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने में उपयोगी होते हैं। ब्यूरो

JobAlert अमर उजाला
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें आवेदन

1865 पद
आवेदन की अंतिम तिथि : 19 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : unionbankofindia.co.in

बिहार लोक सेवा आयोग ■ 1230 पद
अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मई, 2026
पात्रताएं : स्नातक व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : bpsc.bihar.gov.in

यूपीएसएसएससी, लखनऊ ■ 243 पद
प्लाटून कमांडर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 06 जुलाई, 2026
योग्यताएं : स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : upsssc.gov.in

एम्स, ऋषिकेश में मौके ■ 119 पद
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 18 मई, 2026
पात्रताएं : एमडी, एमएस व अन्य योग्यताएं
यहां आवेदन करें : aiimsrishikesh.edu.in

रेल भूमि विकास प्राधिकरण ■ 40 पद
साइट इंजीनियर के पदों पर करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 22 मई, 2026
योग्यताएं : बीई/बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : rlda.indianrailways.gov.in

राइट्स लिमिटेड में निकली भर्ती ■ 35 पद
मुख्य रेजिडेंट इंजीनियर व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 26 मई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : rites.com

यहां भी हैं रोजगार के अवसर...
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो : क्वालिटी मैनेजर का पद खाली।
■ वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 16 मई, 2026
■ sail.co.in
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : काउंसलर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 22 मई, 2026
■ centralbank.bank.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना ही असली प्रगति है।

हरदम तैयार रखें 'प्लान बी'

विकल्पहीनता की स्थिति कई बार तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए छोटे-छोटे विकल्प हमेशा तैयार रखें

जोनाथन ह्यूजेस
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

चाहे आप छात्र हों, व्यवसायी हों या नौकरी पेशेवर, जीवन में कई बार आपको ऐसे संवादों में शामिल होना पड़ता है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यह नौकरी का इंटरव्यू हो सकता है, किसी व्यक्ति से सौदे की बातचीत हो सकती है या आपके बॉस के साथ कोई संवाद। ऐसे कूटनीतिक किस्म के संवादों में समस्या तब आती है, जब आपके पास 'प्लान बी' न हो, यानी यदि यह अवसर हाथ से निकल जाए, तो तुरंत कोई और विकल्प न दिखे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और उसे डर महसूस होने लगता है।

Harvard Business Review

■ छोटे विकल्प तैयार रखें

आपके पास हमेशा कोई बड़ा या उपयुक्त विकल्प होना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार छोटे-छोटे विकल्प भी आपकी स्थिति को मजबूत बना देते हैं। अगर आप पूरी तरह किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर हैं, तो एक छोटी-सी वैकल्पिक व्यवस्था भी आपको सहारा दे सकती है। इससे सामने वाले को संकेत मिलता है कि आप पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं हैं, और यही बात उसे अपनी शर्तों में लचीलापन दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

■ डर को हावी न होने दें

जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो हम डर की वजह से जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि आप शांत रहें; हो सकता है कि सामने वाला भी किसी न किसी रूप में आप पर निर्भर हो। यदि आप केवल अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे, तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है।

■ तुरंत 'हां' या 'ना' न कहें

इस दौरान तुरंत 'हां' या 'ना' कहना जरूरी नहीं होता। कई बार समय लेना ही सबसे प्रभावी रणनीति होती है। आप सामने वाले से सोचने के लिए समय मांग सकते हैं और इस स्थिति का शांतिपूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही, आप ऐसे छोटे-छोटे कदम भी उठा सकते हैं, जो बिना पूर्ण सहमति के ही आपकी स्थिति को मजबूत बनाएं। यह प्रक्रिया आपको धीरे-धीरे एक बेहतर और मजबूत स्थिति में पहुंचाने में मदद कर सकती है।

- *कई बार छोटे-छोटे विकल्प भी आपकी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।*
- *ऐसी स्थिति में आप शांत रहें और यह समझें कि सामने वाला भी आप पर किसी न किसी रूप में निर्भर हो सकता है।*
- *तुरंत 'हां' या 'ना' कहने के बजाय स्थिति का विश्लेषण करें।*
- *अपनी बात को सहज भाव से रखें, ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो।*

■ बात को सहज भाव से रखें

इसमें संवाद का तरीका बेहद महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले से धमकी भरे अंदाज में बात करने के बजाय अपनी बात को शांत और सहज तरीके से रखना बेहतर होता है, ताकि टकराव की स्थिति न बने और बातचीत नियंत्रण में रहे। आप यह कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना पड़ सकता है। साथ ही, अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से भी रखा जा सकता है।

आवेदन आमंत्रित

एएसबीएस इंडिया अचीवर्स अवॉर्ड
- संस्थान : ग्लासगो विश्वविद्यालय
- पात्रताएं : सितंबर 2026 सत्र के लिए योग्य स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश का प्रस्ताव प्राप्त किया हो।
- लाभ : 10,000 पाउंड की ट्यूशन फीस में छूट।
- आवेदन लिंक : gla.ac.uk
- अंतिम तिथि : 18 मई, 2026

फ्री ऑनलाइन कोर्स

इंग्लिश फॉर कॅरिअर डेवलपमेंट
- संस्थान : पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय
- अवधि : चार सप्ताह
- सीखने को क्या मिलेगा : इंटरव्यू व संचार कौशल, व्यावसायिक लेखन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, शब्दावली, सामाजिक कौशल व व्यावसायिकता आदि।
- आधिकारिक लिंक : tinyurl.com/3nse7pp7

एग्जाम अलर्ट

शिनहान पोस्टकार्ड आर्ट कॉन्टेस्ट
- विषय : ए पोस्टकार्ड टू माईसेल्फ : 30 इयर्स फ्रॉम नाउ ड्राइंग टुमारो
- आयु-सीमा : अधिकतम 18 वर्ष
- पुरस्कार : 100 डॉलर से लेकर 600 डॉलर तक नकद, शिनहान कला सामग्री व प्रमाणपत्र।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मई, 2026
- वेबसाइट : tinyurl.com/6suw6ecc

वीडियो एडिटर इंटर्नशिप प्रोग्राम
- अवधि : छह सप्ताह
- पात्रताएं : एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स आदि जैसे वीडियो एडिटिंग टूल्स का बेसिक ज्ञान होना चाहिए।
- स्टाइपेंड : रुपये 6,500 से लेकर रुपये 8,500 प्रतिमाह
- अंतिम तिथि : 06 जून, 2026
- लिंक : tinyurl.com/ywxts36d

खुद को परखें

1. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स किस संस्था द्वारा विनियमित हैं?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(c) वित्त मंत्रालय
(d) भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण
2. ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
(a) महाराष्ट्र (b) कर्नाटक
(c) केरल (d) तमिलनाडु
3. व्यवसायों को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना का नाम क्या है?
(a) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
(b) आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
(c) स्टैंड-अप इंडिया योजना
(d) उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
4. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस पर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था?
(a) हैदराबाद (b) नई दिल्ली
(c) मुंबई (d) चेन्नई

उत्तर-1.b, 2.a, 3.b, 4.b

आज का दिन

8 मई, 2004

श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने कोर्टनी वाल्श के 519 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा था। वह 800 टेस्ट विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड धारक हैं।

- 1915 : भारत के स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद का निधन हुआ था।
- 1929 : प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था।
- 1933 : महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 21 दिन का उपवास शुरू किया था।
- 2000 : लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए थे।

व्रत त्योहार

आज : ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी।
कल : कालाष्टमी व्रत, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 09.00 से 10.30 तक।

कल का पंचांग

सूर्योदय : 05.39
सूर्यास्त : 18.56
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2083, 19 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 26 प्रविष्टे, 21 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी 14.02 तक उपरांत अष्टमी, श्रवण नक्षत्र 23.24 तक उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र, शुक्ल योग 26.35 तक उपरांत ब्रह्म योग, बव करण 14.02 तक उपरांत बालव करण, चंद्रमा मकर राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

पं. विनोद त्यागी

मेष : सरकारी क्षेत्र में विलंब से सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्य का दबाव बना रहेगा।

वृष : मानसिक चिंतन बना रहेगा। घरेलू कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। नौकरी में धैर्य बनाए रखें।

मिथुन : पूर्वनियोजित कार्य में निराशा होगी। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। नौकरी में सम्मान बना रहेगा।

कर्क : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। कार्य विशेष में सफलता मिलेगी। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

सिंह : राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है।

कन्या : मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। नौकरी में आत्मबल बनाए रखें। विरोधी कुचेष्टारत रहेंगे।

तुला : आलस्य प्रगति में बाधक रहेगा। योजना में अल्प सफलता मिलेगी। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा।

वृश्चिक : भाग्य अनुकूल रहेगा। सामाजिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी।

धनु : स्वजनों से मतभेद संभव है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। नौकरी में परेशानी संभव है।

मकर : पूर्व में किए श्रम का लाभ मिलेगा। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा। अचानक व्यय हो सकता है।

कुंभ : नई योजना में पूंजी निवेश से हानि होगी। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। व्यय अधिक होगा।

मीन : सहोदरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में उन्नति हो सकती है।

सुडोकु

				9		6		5
				5	3	8		
							1	3
		3	5		9	4	8	
1								6
	5	7	3		8	1		
2	9							
		4	2	7				
8		6		3				

3	1	8	4	9	7	6	2	5
7	6	2	1	5	3	8	4	9
9	4	5	8	2	6	7	1	3
6	2	3	5	1	9	4	8	7
1	8	9	7	4	2	5	3	6
4	5	7	3	6	8	1	9	2
2	9	1	6	8	5	3	7	4
5	3	4	2	7	1	9	6	8
8	7	6	9	3	4	2	5	1

सुडोकु 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

आपले सत्ताधारी केवळ निवडणुकांत मग्न

''**सिंदूर'चा सांगावा...**' आणि 'घडवून आणलेले 'ऑपरेशन'' हे लेख (लोकसत्ता- ७ मे) वाचले. ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण होत असताना भारत आणि पाकिस्तान यांच्या भूमिकांमध्ये एवढा प्रचंड फरक पडला आहे की हाच तो पाकिस्तान आहे का जिथे दहशतवादी संघटनांना आश्रय दिला गेला, त्यांना फोफावण्यास मदत केली गेली, असा प्रश्न पडतो. पश्चिम आशियातील इराण विरुद्ध इस्राइल- अमेरिका संघर्षामध्ये पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे आणि त्याला अमेरिका आणि इराण दोन्ही देशांकडून तेवढाच पाठिंबा मिळत आहे, यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. भारताने पाकिस्तानातील फक्त दहशतवादी ठिकाणे टार्गेट करून पाकिस्तानला पुरते नामोहरम केले आणि जगभर त्याचे पडसाद उमटले परंतु वर्षानंतर मात्र पाकिस्तानऐवजी आपणच एकटे पडलो नाही ना याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० हून अधिक वेळा भारत पाकिस्तानमधील युद्धविरामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी आपल्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने एकदाही त्याबाबत हू की चू केले नाही, ट्रम्प यांच्या म्हणण्याला प्रतिसादही दिला नाही वा त्याचा इन्कारही केला नाही याचे नवल वाटते. एकीकडे आपण घुसकर मारेंगे म्हणून घोषणा करतो आणि दुसरीकडे आपल्या शीर्षस्थ नेत्यांची अशी काय मजबुरी आहे की वर्षानंतरदेखील त्याबद्दल काहीही ऐकावयास मिळत नाही? बहुधा भविष्यातही या युद्धविरामाच्या ट्रम्प यांच्या श्रेयाबद्दल कधी काही ऐकावयास मिळेल असे वाटत नाही. ज्यावेळी पश्चिम आशियातील युद्धाबाबत पाकिस्तानच्या भूमीवर अमेरिका आणि इराणचे शिष्टमंडळ वाटाघाटी करण्यास येत होते, तेव्हा आपल्याकडील भाजपचे नेतेमंडळी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू येथील विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मश्गूल होती. एकीकडे पाकिस्तानचे भू राजकीय महत्त्व वाढत असताना आपले सत्ताधारी मात्र आपल्याच देशातील राजकीय भूभागावर वर्चस्व प्राप्त करण्याचा आटापिटा करत आहेत. एकंदरीत आपण आणि पाकिस्तान यांच्या भूमिकांमध्ये गेल्या वर्षभरात जो फरक पडला आहे त्यामुळे तात्पुरता विराम दिलेले ऑपरेशन सिंदूर पुन्हा सुरू करावयाचे झाल्यास आपल्याला जागतिक परिस्थितीचा दहादा विचार करावा लागेल.

■ **शुभदा गोवर्धन,** ठाणे.

माती कोपराने खणता येते म्हणून...

''**सिंदूर'चा सांगावा...**' आणि 'घडवून आणलेले 'ऑपरेशन'' हे लेख (लोकसत्ता- ७ मे) वाचले. जागतिक स्तरावर पाकिस्तान या कंगाल राष्ट्राचा अनेक बलशाली राष्ट्रे केवळ प्यादे म्हणून वापर करतात. पाकिस्तान अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतिवार्ता घडवून आणण्याएवढे बलशाली राष्ट्र नाही. दोन्ही राष्ट्रांना पाकिस्तान सोयीचा आणि निरुपद्रवी वाटतो. अमेरिकेचे पश्चिम आशियाईत अनेक लष्करी तळ आहेत आणि त्यांची आता नासधूस झाली आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे सबलीकरण ही अमेरिकेची आशियाई राष्ट्रांवर हुकूमत गाजवण्याची रणनीती आहे. या दोन्ही देशांत माती कोपराने खणण्याजोगी स्थिती आहे, म्हणूनच पाकिस्तानचे महत्त्व वाढले आहे.

■ **बिपीन राजे,** ठाणे.

महासत्तेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होता येईल?

''**सिंदूर'चा सांगावा...**' हा अग्रलेख वाचला. सिंदूर मोहिमेबद्दल लष्कराचे सार्थ कौतुक करताना काही प्रश्न एक वर्षानंतरही अनुत्तरितच राहिल्याचे जाणवते. सिंदूर मोहीम ज्यातून उद्भवली, त्या पहलगाम हत्याकांडातील सुरक्षा त्रुटीला नेमके कोण जबाबदार होते आणि त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली? सिंदूरचा भाजपला राजकीय फायदा झाला, पण भारताला त्यातून नेमके काय मिळाले? पाकिस्तान पुन्हा अशी आगळीक करणार नाही याची कोणती हमी कारवाई अचानक थांबवताना मिळाली? या चार दिवसीय चकमकीत पाकिस्तान दाती तृण धरून शरण आला असे आपले राजकीय नेतृत्व सांगते; मग त्यापुढील एका वर्षात फील्ड मार्शल मुनीर व पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय स्थान उंचावले- उलट भारताच्या वाट्याला ट्रंप यांच्या अमेरिकेकडून वारंवार पाणउतारा (आठवाः 'नरकाचे द्वार!') व टॅरिफ शिक्षा आली हे कसे? सिंदूरपासून इराण- अमेरिकेतील युद्धापर्यंत आशिया खंडात सर्वत्र बलाढ्य चीनचे अस्तित्व स्पष्टपणे जाणवते. त्याच वेळी भारत मात्र महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींत (उदा. इराण युद्ध) कोठेच आढळत नाही. अमेरिका, रशिया व चीन या तिन्ही महासत्ता भारतापासून काहीशा दूर तर पाकिस्तानच्या मात्र जवळ गेल्याचे जाणवते. असे का घडले असावे? सोप्या प्रश्नांना हमखास टाळ्या घेणारी भावनिक उत्तरे देऊन आत्मप्रशंसेत मग्न होत संशयात्म्यांना देशद्रोही ठरवणे सध्याच्या नेतृत्वाला (व त्यांच्या भक्तांनाही) प्रिय आहे, पण एवढ्याच तयारीवर महासत्ता होण्याच्या अतिशय कठीण परीक्षेत भारत कसा उत्तीर्ण होईल?

■ **अरुण जोगदेव,** दापोली (रत्नागिरी)

खेद वा आनंद वाटण्याचे कारण काय?

''**सिंदूर'चा सांगावा...**' हे संपादकीय व प्रवीण सहानी यांचा 'घडवून आणलेले 'ऑपरेशन'' हा लेख वाचला. ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानची प्रतिष्ठा वाढली, या निष्कर्षाशी सहमत होणे कठीण आहे. ट्रम्प यांनी मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची निवड करण्यापूर्वीच 'असे केल्याने पाकिस्तानची प्रतिष्ठा वाढेल,' असे म्हटले होते. 'ट्रम्प बोले व दल हाले' अशी परिस्थिती असताना व इराणला पाकिस्तान विश्वासू वाटल्यामुळे पाकिस्तानकडे मध्यस्थाची भूमिका आली. त्यात आपल्याला खेद किंवा आनंद वाटण्याचे काहीच कारण नाही. मध्यस्थ झाल्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे, असेही नाही. ऑपरेशन सुरू करताना आपल्याकडून आम्ही अमुक करणार नाही, असं पाकिस्तानला सांगण्याची मुळीच गरज नव्हती. परंतु युधिष्ठिराच्या भूमिकेत शिरणे, आपल्याला महागात पडले. तो तर आपला स्वभाव आहे. गुणदोषांसकट माणूस स्वीकारावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय डावपेचात आपण अद्याप अडकलो नाही, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.

■ **अरविंद करंदीकर,** तळेगाव दाभाडे

अजेंडा रेटण्यासाठी सिनेमाचा वापर

'**सिनेमातील इतिहासातून** स्मृतींचे राजकारण' हा हरीश वानखेडे यांचा 'सिनेकारण' सदरातील लेख (७ मे) वाचला. अलीकडच्या काळात प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांनी आपला राजकीय आणि वैचारिक अजेंडा, विशेषतः हिंदुत्वाचा मुद्दा रेटण्यासाठी सिनेमा या माध्यमाचा अत्यंत प्रभावी वापर सुरू केला आहे.

सिनेमा हे समाजाला आरसा दाखवणारे आणि प्रबोधनाचे माध्यम असणे गरजेचे आहे. मात्र, सत्तेत असलेल्या मंडळींनी या माध्यमाला स्वतःच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाचे आणि प्रचाराचे साधन म्हणून वापरले आहे. कलेचा वापर जेव्हा विचारप्रसारासाठी न होता ठरावीक विचारधारा लादण्यासाठी होतो, तेव्हा कलेचे पावित्र्य नष्ट होते. आजकाल ऐतिहासिक सिनेमांच्या नावाखाली इतिहासाचे भगवेकरण किंवा सोयीनुसार फेरबदल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मूळ संदर्भ, अस्सल कागदपत्रे आणि वस्तुनिष्ठ इतिहास बाजूला सारून, प्रेक्षकांच्या भावनांना हात घालणारा 'फॅब्रिकेटेड' इतिहास पडद्यावर मांडला जातो. सामान्य प्रेक्षक मूळ ग्रंथ किंवा इतिहास वाचण्याऐवजी पडद्यावर जे दिसते, त्यालाच अंतिम सत्य मानू लागतो. हा भ्रम समाजाच्या वैचारिक आरोग्यासाठी घातक आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे खऱ्या अर्थाने रयतेचे राजे आणि बहुजन कल्याणकारी शासक होते. मात्र, अलीकडे त्यांच्यावर आलेल्या अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांच्या या व्यापक रूपापेक्षा त्यांना एका विशिष्ट चौकटीत किंवा केवळ धार्मिक संघर्षाच्या भूमिकेत अडकवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. चित्रपट निर्माते धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्मितांना आवाहन करून बॉक्स ऑफिसवर गल्ला भरून घेतात. मात्र, महाराजांनी उभे केलेले स्वराज्य हे अठरापगड जातींना सोबत घेऊन जाणारे, स्त्रियांचा सन्मान करणारे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे राज्य होते, हा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवण्यात हे चित्रपट कमी पडतात.

सिनेमा केवळ करमणूक म्हणून न पाहता, त्याची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. त्यात दाखवलेल्या इतिहासामागे निर्मात्याचा किंवा दिग्दर्शकाचा काय हेतू आहे, यावर विचार करणे, ही सुज्ञ प्रेक्षक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. भावनिक लाटेत वाहून न जाता, विवेकाने इतिहासाकडे आणि सिनेमाकडे पाहण्याची दृष्टी हा लेख देतो.

■ **प्रियदर्शन भवरे**

'आयात' नेत्यांमुळे भाजप पुन्हा एकदा सत्तेत!

रेवड्यांच्या उधळणीमुळे भाजपशासित राज्यांची आर्थिक अवस्था गंभीर आहे. भाजपने सत्ता मिळवली, मात्र त्यांचे सुबत्तेचे दावे फोल ठरले आहेत...

ॲड. हर्षल प्रधान
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख,
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष

भारतीय जनता पक्षाने गेल्या एका दशकात देशाच्या राजकीय नकाशावर जे वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे, ते पाहून कोणीही थक्क होईल. परंतु ही कहाणी खऱ्या जनाधाराची नाही, तर सत्तेच्या लालसेपोटी झालेल्या आयातीची, फोडाफोडीची आणि अभद्र तडजोडींची आहे. प्रश्न साधा आहे मोदींचे कर्तृत्व म्हणजे काय? विचारधारा रुजवणे, की इतरांच्या खांद्यावर बसून सिंहासन टिकवणे?

भाजप ज्या राज्यांत सत्तेत आहे, तेथील बहुतेक लोकप्रतिनिधी अन्य पक्षांतून आलेले आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना यंत्रणांचा धाक दाखवून जनतेच्या मनात प्रतिमावर्धन झालेले उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार भाजपने उलथवले. बिहारमध्येदेखील नितीश कुमार यांच्या प्रतिमेचा लाभ घेत दोनदा सरकार स्थापन केले आणि त्यांनाच मुख्यमंत्री पदावरून पदच्युत केले. हाच प्रकार जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीबाबत केला. आसाममध्ये डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा हे तर काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते त्यांनाही जाळ्यात ओढले, पण ते मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवण्यात यशस्वी झाले. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंना तुरुंगात जाऊन यावे लागले होते आता ते एनडीएबरोबर आहेत. नागालँडमध्ये नेफ्यू रिओ एनपीएफचे नेते, पुदुच्चेरीमध्ये एन. रंगास्वामी हे मूळ काँग्रेस विरोधातील एआयएनआरसीचे नेते, पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी हे मूळ तृणमूल काँग्रेसचे, अरुणाचल प्रदेशमधील पेमा खंडू हे मूळ काँग्रेसचे नेते, मणिपूरमधील एन. बिरेन सिंग हे मूळ काँग्रेसचे नेते, सिक्कीममधील पी. एस. गोले हे एसडीएफ या स्थानिक आघाडीचे नेते असे अर्ध्याहून अधिक नेते हे भाजपने उधारी-उसनवारीवर घेतले. भाजपाच्या विचारांची मुळे त्यांच्या मनात रुजली कशी? या सगळ्यांनी आपापल्या मूळ विचारधारेकडे परतायचे ठरवले तर भाजप २३ पैकी किमान १५-२० राज्ये सहज गमावेल! मग यात मोदींचा करिष्मा आहेच कुठे? हा करिष्मा आहे ईडी, सीबीआय आणि आयटीचा.

तोडा फोडा पण राज्य आणा

मतपेटीतून नव्हे, तर मागच्या दाराने सत्ता मिळवण्याची कला भाजपने अवगत केली आहे. महाराष्ट्र हे याचे सर्वात ठळक उदाहरण. इथे त्यांनी अडीच वर्षांत एकनाथ शिंदेंना मॅनेज करून, रात्री-अपरात्री हुडी घालून एकनाथांना झालमुडी देऊन झोलमुडी करायला भाग पाडले. शिवसेनेत फूट पाडून भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली. जनतेने दिलेला जनादेश बदलला गेला मतपेटीतून नाही, तर गुप्त राजकीय अभियांत्रिकीतून. हेच तंत्र बिहारमध्ये वेगळ्या पद्धतीने वापरले गेले. 'मोदी मॅजिक' ही संकल्पना प्रसारमाध्यमांनी गेल्या दहा वर्षांत अत्यंत काळजीपूर्वक उभी केली आहे. परंतु ते 'मॅजिक' नक्की कशाचे आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे. खरे तर, मोदींनी हिंदी पट्ट्यातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड काही राज्यांत भाजपाचा जनाधार बांधला हे नाकारता येणार नाही. २०१४ आणि २०१९ च्या लाटेत जनतेने स्वतःहून दिलेला जनादेश हा भाजपाच्या पारंपरिक शक्तीवर आधारित होता. परंतु दक्षिण भारत, ईशान्य भारत, आणि अनेक प्रादेशिक राज्यांतील भाजपची सत्ता ही मुख्यत्वे आयात केलेल्या नेत्यांवर अवलंबून आहे.

आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा यांनी काँग्रेस सोडली, तेव्हा त्यांच्यासोबत आलेली ताकद भाजपाची नव्हती ती हिमंतांची होती. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडूंनी केंद्रात पाठिंबा दिला, तेव्हा भाजपाला तेलुगू मतांची गरज होती आणि नायडूंना अनुदानांची. या परस्परांच्या गरजांच्या व्यवहारात 'मोदी मॅजिक' कुठे आहे? भाजपला विरोधी पक्षांना आतून पोखरण्याचे तंत्र अवगत आहे. त्यासाठी ईडी, सीबीआय, आणि इतर तपास यंत्रणांचा वापर हे आता उघड गुपित आहे. महाराष्ट्रात अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होते ते भाजपासोबत आले आणि आरोप करणारे आवाज शांत झाले. ईशान्य भारतातील अनेक नेत्यांच्या बाबतीत हेच घडले. 'वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स' ही संज्ञा त्यातूनच रूढ झाली. जेव्हा निवडून आलेले आमदार पैशाच्या किंवा भीतीच्या जोरावर पक्ष बदलतात, तेव्हा मतदाराचा जनादेश अर्थहीन ठरतो.

संघाच्या विचारधारेला विचारतेय कोण?

भाजपाची मूळ विचारधारा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्वाच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. परंतु ज्या नेत्यांना आयात केले गेले ते त्या विचारधारेशी किती बांधील आहेत? महबूबा मुफ्ती ज्या पीडीपी पक्षाच्या आहेत, त्यांचा पाया काश्मिरी अस्मिता आणि स्वायत्तता हा आहे. नितीशकुमार समाजवादी परंपरेचे आहेत. चंद्राबाबू नायडू तेलुगू अस्मितेचे प्रतिनिधी आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष विचाराच्या पार्श्वभूमीतून आले आहेत. मग भाजपाचा हिंदुत्व विस्तार म्हणजे काय? संघ परिवारातही हा प्रश्न अस्वस्थपणे घोंघावतो आहे. भाजपाचे समर्थक 'देशव्यापी सत्ते'चा उत्सव साजरा करतात. पण या यशाला काय अर्थ आहे? हिंदी पट्ट्यातील भावनिक राष्ट्रवादाला मतपेटीत रूपांतरीत करण्याची ताकद भाजपाने मोदींच्या रूपाने दाखवली हे मान्य करायला हवे, परंतु त्या कर्तृत्वाला राष्ट्रव्यापी रंग देण्यासाठी ज्या फोडाफोडीच्या राजकारणाचा आधार घेतला जातो, ते भाजपाच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेसाठी घातक ठरू शकते. या 'आयाती'त भाजपाची मूळ विचारधारा कुठे आहे? दीनदयाल उपाध्यांचा 'एकात्म मानववाद', अटलजींची 'दुसरे के पार्टी के नेताओ को अलग कर साथ लेकर सत्ता मिलती है तो उसे मैं चिमटी से भी नही छुऊंगा' ही तत्त्वे केवळ स्मरणापूर्तीच उरली आहेत का?

भाजपच्या राज्यात 'झोलमुडी'

भाजप-शासित राज्ये आज कर्जाचा डोंगरावर आहेत आणि बहुतांश डबल इंजिन सरकार असणाऱ्या राज्यांत कायद्याचा बोजवारा उडाला आहे. भाजपने सत्ता तर मिळवली पण त्यांचे सुबत्ता आणण्याचे दावे फोल ठरले आहेत. आरबीआय आणि पीआरएस इंडियाच्या ताज्या अहवालांतील आकडे धक्कादायक आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, बिहार ही भाजपशासित राज्ये आर्थिक कुशासनाशी झुंजत आहेत.

आरबीआयची आकडेवारी

आरबीआयच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, सर्व राज्यांच्या एकत्रित थकीत देणग्या २०१९ मधील ४७.९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये ८३.३ लाख कोटींवर पोहोचल्या आहेत म्हणजे अवघ्या पाच वर्षांत तब्बल ७४ टक्के वाढ. या वाढीचा मोठा वाटा भाजप-शासित राज्यांनी उचलला आहे. मध्य प्रदेशात भाजपने दशकाहून अधिक काळ राज्य केले. परंतु याच राज्याने २०१९ ते २०२४ दरम्यान सर्वाधिक तब्बल ११४ टक्के कर्जवाढ नोंदवली. २ लाख कोटींवरून थेट ४.२ लाख कोटींवर. 'लाडली बहना' सारख्या रोखीच्या लोकप्रिय योजनांमुळे दरमहा १,६०० कोटींहून अधिक खर्च होतो. या कल्याणकारी योजना निवडणुकीत मते मिळवून देतात पण राज्याच्या तिजोरीला खड्डा पाडतात. परिणामी, मध्य प्रदेशचा फिसकल डेफिसिट जीएसडीपीच्या ४.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे जो एफआरबीएम कायद्याने ठरवलेल्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे. राजस्थानात कर्जाचे जीएसडीपीशी गुणोत्तर ३७ टक्के आहे जे राष्ट्रीय सरासरी (२७.६ टक्के) पेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. एकूण थकीत कर्ज ५.६ लाख कोटी आहे. विकासात्मक खर्चापैकी केवळ १० टक्के भाग भांडवली खर्चासाठी वापरला जातो बाकी सगळा पैसा प्रशासकीय खर्च आणि व्याजफेडीत जातो. उत्तर प्रदेशचे एकूण थकीत कर्ज ७.७ लाख कोटी आहे जे कर्जबाजारी राज्यात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जीएसडीपीच्या ३० टक्के इतके हे प्रमाण आहे. योगी मॉडेलचा जयजयकार करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, या राज्याचे आउटस्टँडिंग गॅरेंटी जीएसडीपीच्या ६.४ टक्के इतक्या धोकादायक पातळीवर आहे. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये ११ राज्यांनी महसुली तूट नोंदवली आहे. सरकार रोजच्या खर्चासाठीही कर्ज काढते, तेव्हा भांडवल निर्माण होत नाही, फक्त जबाबदारी वाढते. भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये हेच होत आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेचे दावे फोल

उत्तर प्रदेशात बुलडोझर न्याय गेल्या काही वर्षांत नित्याचाच झाला आहे. पोलीस-प्रशासन स्वतःच न्यायाधीश होते, तेव्हा लोकशाही संपते. कायद्याचे राज्य विरुद्ध राजाचे कायदे यातील फरक धूसर होतो. एनसीआरबीच्या उपलब्ध सर्वात ताज्या अहवालानुसार (२०२२), उत्तर प्रदेशमध्ये देशात सर्वाधिक एकूण ७,५३,६७५ गुन्हे नोंदवले गेले. भाजप-शासित राज्यांतील पोलीस चकमकीच्या धोरणाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. २०१७ ते २०२४ दरम्यान उत्तर प्रदेशात १,२००हून अधिक पोलीस चकमकी झाल्या. 'आउटलूक इंडिया'च्या विश्लेषणानुसार, २०१४ ते २०२४ दरम्यान देशात गोमांस-संबंधित जमावहल्ल्यांच्या ३०० हून अधिक घटना घडल्या, ज्यात बहुतांश पीडित अल्पसंख्याक होते. यातील मोठा भाग भाजप-शासित राज्यांत घडला. लव्ह जिहादविरोधी कायदे १२ भाजप-शासित राज्यांत केले गेले परंतु एकाही प्रकरणात शिक्षा झाली नाही. कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे केवळ गुन्हेगारांना पकडणे नव्हे. सर्व नागरिकांना धर्म, जात, आणि पार्श्वभूमी विचारात न घेता समान संरक्षण देणे. या निकषावर भाजप-शासित राज्ये किती टिकतात? २०२२ मध्ये स्वतः पंतप्रधान मोदींनी रेवडी संस्कृतीवर टीका केली होती, परंतु ज्या भाजप-शासित राज्यांनी लाडली बहना (मध्य प्रदेश), उज्ज्वला गॅस (केंद्र) आणि इतर योजना राबवल्या त्यांची तिजोरी रिकामी होत आहे. मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेवर दरमहा १,६०० कोटींहून अधिक खर्च होतो. वर्षाला जवळपास २० हजार कोटी. आणि राज्याचे कर्ज ४.२ लाख कोटींवर. महाराष्ट्रातदेखील तीच गत आहे. लाडकी बहीण योजनेवर दरमहा ३,७०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. वार्षिक तरतूद २०२५-२६ साठी ३६,००० कोटी. मात्र २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद १०,००० कोटींनी कमी करून २६,००० कोटी केली गेली. महाराष्ट्राचे थकीत कर्ज २०१८-१९ मध्ये ४.०७ लाख कोटी, २०२४-२५ मध्ये ८.४० लाख कोटी, २०२५-२६ मध्ये ९.७४ लाख कोटी, २०२६-२७ मध्ये (अंदाज) ११.०३ लाख कोटी, म्हणजे ८ वर्षांत कर्ज दुप्पटीहून अधिक झाले. २०२७ पर्यंत राज्याला दररोज सुमारे १९२ कोटी केवळ व्याजापोटी द्यावे लागणार आहेत.

विकास आणि कर्ज यांच्यातील हा संघर्ष केवळ अर्थशास्त्राचा नाही तो राजकीय प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. एखाद्या राज्याचा विकास मोजायचा असेल, तर त्याचा भांडवली खर्च पाहावा रस्ते, शाळा, रुग्णालये, उद्योगासाठीची पायाभूत सुविधा. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, राजस्थान विकासात्मक खर्चाच्या केवळ ३.०७ टक्के भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरतो देशातील सर्वांत कमी प्रमाण. याउलट, ओडिशा, छत्तीसगड, आणि झारखंड यांसारख्या गैर-भाजप राज्यांनी खाण महसुलातून स्वतःची आर्थिक पायाभूत व्यवस्था बळकट केली आहे. विकासाची खरी स्पर्धा घोषणांत नाही गुंतवणुकीत आहे. सर्व भाजप-शासित राज्ये एकसारखी नाहीत. भाजपने राज्य पातळीवर जे विकासाचे चित्र रंगवले, त्याची किंमत आता येणाऱ्या पिढ्यांना चुकवावी लागेल.

'डबल इंजिन सरकार' घोषणा देण्यासाठी ठीक आहे, विकासासाठी नाही. इंजिन चालते कर्जाच्या इंधनावर आणि त्याचे व्याज फेडावे लागणार भावी पिढ्यांच्याही पिढ्यांना. मग अशा भाजपमय भारताचे करायचे काय? हा सत्तातुर भाजपा सामान्य माणसाला कायमस्वरूपी चिंतातुर करून जाणार एवढे मात्र निश्चित.

कुतूहल

उल्कावर्षाव कसा होतो?

आपल्याला अधूनमधून 'या तारखांना उल्कावर्षाव होणार आहे' अशा बातम्या वाचायला मिळतात. असे उल्कावर्षाव ठरावीक दिवशीच का होतात आणि ते एखाद्या नक्षत्राच्या दिशेनेच का येतात?

उल्का म्हणजे अवकाशात फिरणारे दगडगोटे. ते पृथ्वीच्या वातावरणात प्रचंड वेगाने शिरतात तेव्हा हवेच्या घर्षणाने इतकी उष्णता निर्माण होते की ते दगड पेटून प्रकाशमान होतात आणि वितळतात. यातले बहुतेक कण वाळूच्या कणांसारखे असल्यामुळे ते हवेतच जळून जातात आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागापर्यंत पोहोचत नाहीत. कधी कधी हा उल्कावर्षाव इतका तीव्र असतो की ताशी हजारपर्यंत उल्का बघायला मिळतात.

'लिओनिड्स' हा एक उल्कावर्षाव दर ३३ वर्षांनी होतो. यापूर्वी तो २००९ साली झाला होता. लिओनिड्स म्हणजे 'सिंहापासून येणारा'. हा 'लिओ' म्हणजेच सिंह राशीकडून येताना दिसतो आणि याचा उगम 'टेम्पल टटल' या धूमकेतूमुळे होतो. मेटेऑर डेटा सेंटर ही संस्था उल्कापातांची नोंद ठेवते. त्यांच्या दप्तरी ९०० उल्कापातांची नोंद आहे. यातले सुमारे १०० ठरावीक अंतराने होत असल्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाची खात्री आहे. पण इतर उल्कापातांबद्दल सतत निरीक्षणं सुरू असतात. 'नासा' उल्कापातांचा दैनंदिन नकाशा तयार करते.

पुरातन काळात उल्कापाताशी अनेक अंधश्रद्धा जोडल्या जात होत्या. उल्का पृथ्वीच्या वातावरणात तयार होऊन बरसतात असाही समज होता. १७९४ साली अर्नेस्ट श्लाडनी या जर्मन शास्त्रज्ञाने प्रदीर्घ अभ्यासानंतर उल्का या अवकाशातून येत असल्याचं सिद्ध केलं. त्यानंतर १८३३ साली अमेरिकी शास्त्रज्ञ डेनिसन ओमस्टेड याने अवकाशीय धुळीचा ढग येणं आणि त्यानंतर उल्कापात होणं या घटनांचा संबंध प्रस्थापित करून त्या सिंह नक्षत्राच्या दिशेने येतात हे दाखवून दिलं. या अभ्यासकाला उल्काशास्त्राचा जनक मानलं जातं. १८६६ साली स्कॅपरेली या इटालियन खगोलशास्त्रज्ञाने उल्का या धूमकेतूच्या 'पिसाऱ्या'मधून उद्भवतात असा सिद्धांत मांडला आणि लिओनिड उल्कापात आणि टेम्पेल टटल या धूमकेतूची कक्षा एकच असल्याचं दाखवून दिलं.

धूमकेतूच्या पिसाऱ्यातील धूलिकण एखाद्या ग्रहाच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कक्षेत आल्यावर त्या ग्रहाकडे आकर्षित होतात. ते पृथ्वीच्या कक्षेत येऊन हवेच्या घर्षणाने पेटून प्रकाशमान होतात. या घटनेला आपण 'उल्कापात' म्हणतो.

– सुनील सुळे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

केरळमधील चित्रपटगृहांमध्ये अलीकडेच म्हणजे १० एप्रिल रोजी लागलेला चित्रपट अजूनही गर्दी खेचतो आहे, हाऊसफुल्ल ठरलेल्या या चित्रपटाचे प्रेक्षकांकडून कौतुक होते आहे, या गोष्टीचा पूर्ण आनंद घ्यायच्या आतच मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते संतोष के. नायर यांचे रस्ते अपघातात निधन झाले. मनोरंजन, प्रयोग, व्यावसायिकता या सगळ्या पातळ्यांवर सध्या शिखरावर असलेल्या मल्याळम चित्रपटसृष्टीत संतोष के. नायर यांची कारकीर्द ४० हून अधिक वर्षांची. पी.जी. विश्वंभरन यांच्या 'इथू नंगळुडे कथा' (१९८२) या चित्रपटातील 'जोसेफ' या भूमिकेच्या माध्यमातून त्यांनी या क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकले. वडील, सी. एन. केशवन नायर आणि आई पी. राजलक्ष्मीअम्मा दोघेही शिक्षक. त्यामुळे घरातले वातावरण सुशिक्षित. या क्षेत्राची काहीच पार्श्वभूमी नसलेले. पण तरीही संतोष नायर यांनी मल्याळम चित्रपटसृष्टीत आपले नीट बस्तान बसवले आणि ४०-४५ वर्षांच्या कारकीर्दीत एकूण १०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या. ते दूरचित्रवाणीवरही तितकेच सक्रिय होते. खलनायक, मुख्य व्यक्तिरेखा, साहाय्यक पात्रे आणि विनोदी भूमिका अशी सगळ्या प्रकारची कामे त्यांनी केली. 'एप्रिल १८' आणि 'इविडे तुडंगुन्नू' (१९८४) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांच्या अभिनयाची विशेष दखल घेतली गेली होती. मोहनलाल हे मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अभिनेते त्यांचे महाविद्यालयीन मित्र होते. मोहनलाल यांच्या बरोबरच्या 'चंद्रोत्सवम' (२००५) आणि 'इरुपाथम नूट्टांडू' (१९८७) या चित्रपटांमध्ये त्यांनी केलेल्या नायकाच्या सहकाऱ्याच्या भूमिका मल्याळी प्रेक्षक अजही विसरलेले नाहीत, असे सांगितले जाते. कृष्णदास मुरली दिग्दर्शित 'भरतनाट्यम २ः मोहिनीअट्टम' (२०२६) हा आता त्यांचा पडद्यावरील अखेरचा चित्रपट ठरला आहे. तो 'भरतनाट्यम' (२०२४) या चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. हे दोन्ही चित्रपट डार्क कॉमेडी या जॉनरमधले मानले जातात.

संतोष के. नायर

संतोष आणि सुपरस्टार मोहनलाल हे दोघेही 'एम.जी. कॉलेज'मध्ये समकालीन होते; जिथे संतोष यांनी गणितात बी.एस्सी.चे शिक्षण घेतले होते, तर मोहनलाल यांनी वाणिज्य शाखेचा अभ्यास केला होता. संतोष यांनी आपल्या अनेक मुलाखतींमध्ये मोहनलाल यांच्याबरोबरच्या महाविद्यालयीन आठवणींना उजाळा दिला होता. ते दोघेही वयाने जवळपास सारखेच असले, तरी संतोष यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्यासाठी काही काळासाठी बी.एस्सी.चा अभ्यास थांबवला होता; आणि त्यानंतर पदवी पूर्ण करण्यासाठी ते पुन्हा परतले होते. यामुळे आम्ही समवयस्क असलो तरी मोहनलाल हे मला 'सीनिअर' होते, असे संतोष के. नायर गमतीने सांगत. त्यांच्या मृत्यूमुळे रस्ते अपघाताचे गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

राजवाडे विचारविश्व

दडवलेली पत्रे, पसरलेला भ्रम

'**तलवारीच्या जोरावर** व मुत्सद्द्यांच्या युक्तीवर भिस्त ठेवून पेशव्यांना (उत्तर) हिंदुस्थानातील आपली सत्ता चालवावी लागे... महाराष्ट्रीयेतर लोकांच्या मनात मुसुलमानांप्रमाणे पेशवेही परकीय आहेत, असाच दुजाभाव कायम राही व परशत्रू आला असता पेशव्यांचे जू झुगारून देण्यास त्या प्रांतांतील लोक तयार असत. या स्थितीची समज येऊनही पेशव्यांनी तिचा उपशम करण्याची काही खटपट केली नाही, हे कबूल केल्याशिवाय गत्यंतर नाही... जिंकलेल्या लोकांची मने आकर्षून घेण्याचे व नवीन जाणिवा त्यांना करून देण्याचे पेशव्यांनी व्यवस्थित प्रयत्न केले नाहीत, हा त्यांचा मोठा दोष होता...' असे राजवाड्यांनी नमूद केले; पण लगेच त्यांनी 'हा दोष दुसऱ्या एका दोषाच्या मानाने केवळ क्षुद्र आहे, असे दिसून येईल', ही पुस्तीही जोडली.

आणि तो अधिक गंभीर, अधिक मोठा दोष कोणता, तर 'कपटी, कुचर व स्वामिद्रोही सरदारांना ताळ्यावर, वठणीवर आणण्यासाठी पेशव्यांनी काहीच व्यवस्था केली नाही' हा! त्यांना उपलब्ध झालेल्या व त्यांनी त्या पहिल्या खंडात संपादकीय संस्कारांसह समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहाराआधारे गंभीर उणीव निदर्शनास आणली. गोविंदपंताच्या आक्षेपार्ह वर्तनाचा तपशील उघड करणारी सर्व पत्रे येरंड्यांजवळ राहिली. सदाशिवरावभाऊने किंवा नारो शंकराने अबदालीविरुद्धची मोहीम चाललेली असताना गोविंदपंताला पाठवलेली पत्रे १६ जानेवारी १७६१पर्यंत किंवा नंतरही बाळाजी बाजीरावाच्या नजरेस पडली नाहीत. परिणामी पानिपतच्या मोहिमेत पूर्वीपासून सतत कुचराई केल्याबद्दल गोविंदपंताला काहीएक प्रायश्चित्त मिळाले नाही, शासन झाले नाही. 'योग्य चाकरी न केल्यास पुढे फार कठीण जाईल', अशी धमकीची पत्रे सदाशिवभाऊने गोविंदपंताला पाठवली होती, याची काडीमात्र कल्पना नसल्यामुळे बाळाजी बाजीरावाने १६ जानेवारी १७६१ला म्हणजे पानिपतची लढाई हरल्यावर तीन दिवसांनी व गोविंदपंत अताईखान नावाच्या शत्रुपक्षाच्या सरदाराकडून मारला गेल्यानंतर पंचवीस दिवसांनी गंगाधरपंताला पाठवलेल्या पत्रात चक्क गोविंदपंताची तारीफ केलेली आढळते.

'ती ऐतिहासिक महत्त्वाची पत्रे येरंड्यांच्या हातात येण्याचे कारण नक्की काय असावे, ते कळत नाही', असे राजवाड्यांनी म्हटले खरे; परंतु परिस्थितीजन्य पुरावा लक्षात घेऊन काय काय झाले असावे, याचा तर्क मांडण्याचे कामही पार पाडले. त्यांनी लिहिले, 'गोविंदपंताविरुद्ध पुरावा म्हणून येरंड्यांनी त्या पत्रांचा ताबा घेतला असावा, असा तर्क करणे साहजिक आहे. पानिपतची मोहीम झाल्यावर, खरे म्हटले असता, गोविंदपंत बुंदेल्याचे कृष्ण कारस्थान बाहेर पडावयाचे. परंतु येरंड्यांची गोविंदपंताच्या चिरंजीवांनी मूठ दाबिली म्हणा वा अंतस्थ मसलतीने म्हणा, गोविंदपंताचे हे बंड बाहेर पडले नाही.'

त्यानंतर त्यांनी एक दावा व खुलासा केला. 'गोविंदपंताच्या विरुद्ध पुराव्याची ही पत्रे येरंड्याने जी दडवून, लपवून वाई येथे आपल्या वाड्यात ठेवली, ती या कालपर्यंत कोणाच्याही दृष्टीस पडली नाहीत. पेशव्यांच्याही नाहीत व ग्रांट डफच्याही दृष्टीस पडली नाहीत, त्यामुळे गोविंदपंताचा संशय कोणालाच आला नाही. अर्थात पानिपतच्या मोहिमेचे मुख्य सूत्र कोठे होते व खरे स्वरूप काय होते, तेही आजपर्यंत कळले नव्हते. सध्या या ग्रंथात छापलेल्या पत्रांच्या द्वारे या स्वरूपाच्या काही भागाचा उलगडा झाला आहे', हा दावा कुणीही अमान्य करण्याची शक्यताच नव्हती. राहिलेल्या भागांचा उलगडा अधिक पत्रव्यवहार सापडेपर्यंत व्हायचा नाही, मल्हाररावाचा व इतर सरदारांचा पत्रव्यवहार अभ्यासला जाईपर्यंत ठाम निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा खुलासाही राजवाड्यांनी केला. अशा रीतीने राजवाड्यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाची मूळ संदर्भसाधने शोधून, त्यांच्यावर संपादकीय संस्कार करून, ती प्रकाशित करण्याचा व त्यांचा अभ्यासपूर्वक अन्वयार्थ लावण्याचा खटाटोप सिद्धीस नेला...

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

यदाकदाचित युद्ध...!

दुसऱ्या प्रयत्नातही इराणची अण्वस्त्रे बनवण्याची क्षमता नष्ट झाली नसेल, तर तिसऱ्यांदा तशी कारवाई होणारच नाही याची हमी ट्रम्प आणि नेतान्याहू देणार का?

इराणविरुद्ध २८ फेब्रुवारीच्या पहाटे अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेली लष्करी कारवाई संपुष्टात आल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी अलीकडेच जाहीर केले. ही मौलिक माहिती त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली हे बरे झाले. कारण सध्या तरी इराण आणि अमेरिका व इस्रायल यांच्या दरम्यान फेब्रुवारीअखेर सुरू झालेल्या विध्वंसक युद्धात विराम घोषित झाल्याचे वाटत होते. रुबियो यांच्या म्हणण्याचा रोख असा, की युद्धविराम जाहीर झाल्यानंतर आणि कित्येक दिवस तो पाळला गेल्यानंतर युद्ध संपल्यातच जमा आहे. कारण युद्धाची सारी उद्दिष्टे सफल झालेली असल्यामुळे ते पुन्हा सुरू करण्यात कुठलाच मतलब नाही. त्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ खुद्द अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' ही नाविक कारवाई स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून व्यापारी आणि तेलवाहू जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर येता यावे, यासाठी अमेरिकी नौकांचे संरक्षण पुरवू, असे आश्वासन ट्रम्प यांनी 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' अंतर्गत दिले होते. त्याचा भलताच परिणाम झाला. कारण इराणने ही कृती म्हणजे एक प्रकारचे आक्रमण मानून प्रतिहल्ले सुरू केले. इतक्या दिवसांनंतर युद्धविरामाचा भंग झाला, तशी ही मोहीम मागे घेऊन ट्रम्प यांनी आणखी एक माघार घेतली. त्यांची ही कृती इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेल्या लष्करी कारवाईतील धरसोडपणाचेच निदर्शक आहे. आता दोन्ही बाजूंकडून कायमस्वरूपी शांतता प्रस्तावावर चर्चा सुरू झालेली आहे. पण मुळात इराणवर आक्रमण करून हजारोंना मृत्युमुखी धाडून, कोट्यवधी डॉलर्सचा चुराडा करून नि जागतिक खनिज तेलसाखळी आणि अर्थव्यवस्थेला अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलून अमेरिका आणि युद्धपिपासू इस्रायलने नेमके काय साधले, याचा लेखाजोखा मांडावा लागेल.

इराणवर गेल्या वर्षी जून महिन्यात इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्त कारवाई केली, त्यावेळी तिचा उद्देश इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम संपुष्टात आणणे, इराणची हवाई संरक्षण क्षमता उद्ध्वस्त करणे हा होता. अमेरिकेने बंकरभेदी बॉम्बचा वापर करून इराणच्या सगळ्या अण्वस्त्र प्रकल्पांना मातीमोल केल्याचे ट्रम्प यांनीच जाहीर केले होते. तरीदेखील नऊ महिन्यांतच पुन्हा एकदा इराणवर हल्ले करण्यात आले, तेव्हा या नवीन मोहिमेची पाच उद्दिष्टे सांगण्यात आली. इराणमध्ये राजवट बदल, इराणी नौदलाचा नायनाट, इराण समर्थित दहशतवादी गटांचा निःपात, इराणच्या क्षेपणास्त्रविकासावर निर्बंध आणि इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून प्रतिबंध या पाच उद्दिष्टांपैकी इराणी नौदलाचा नायनाट हेच १०० टक्के यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. इराणची क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन क्षमता अजूनही ५० टक्के शाबूत असल्याचे पेंटॅगॉन हा अमेरिकेचा संरक्षण विभागच नमूद करतो. हेझबोला आणि हमास यांची सध्या निर्नायकी अवस्था असली, तरी यांतील हेझबोलाचे उपद्रवमूल्य कायम असल्याचे स्पष्ट आहे. हा गट आजही इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागतच आहे. या दोन गटांपेक्षा वेगळा असा हुथी गट अजूनही येमेनमध्ये सक्रिय आहे. त्याचा उपद्रव लाल समुद्रातील व्यापारी सागरमार्गात पुरेसा गंभीर आहे. होर्मुझसारखीच आणखी एक सामुद्रधुनी अर्थात बाब एल मंडेब सर्वस्वी हुथींच्याच ताब्यात आहे. होर्मुझची नाकेबंदी उठली नाही आणि या नव्या सामुद्रधुनीत हुथींनी धुडगूस घातला तर हाहाकार उडेल. कारण एक जगातील प्रमुख तेल वाहतूक मार्ग आहे, तर दुसरा व्यापारी वाहतूक मार्ग.

राहता राहिला मुद्दा इराणमधील राजवट बदलाचा. त्यांचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला अली खामेनी अमेरिका-इस्रायलच्या कारवाईत पहिल्याच दिवशी मारले गेले. या घटनेनंतर इराणमध्ये सरकारविरोधी आणि उदारमतवादी समूहांना बळ मिळेल आणि त्यातून खामेनी राजवट उलथवली जाईल, असा ट्रम्प प्रशासनाचा होरा होता. पण तसे घडलेले नाही. कारण इराणमधील जनतेला

...ती द्यावी की न द्यावी या कात्रीत दोघेही सापडले आहेत. दोघांनी युद्ध सुरू केले ते राजकीय गरजेपोटी. आज तेच युद्ध दोघांसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल अशी चिन्हे आहेत.

तेथील राजवटीविषयी चीड असेल किंवा नसेल. पण इस्रायल आणि त्याला मदत करणारी अमेरिका यांच्याविषयीची चीड मात्र सार्वत्रिक आणि पूर्वापार आहे. सरकारसमर्थक आणि सरकारविरोधी अशा दोहोंना इस्रायलविषयी प्रचंड तिटकारा वाटतो, शिवाय इस्रायलच्या सांगण्यावरून इराणवर विध्वंसक युद्ध लादलेल्या अमेरिकेच्या कोणत्याही कृतीविषयी प्रचंड संशयही.

सबब, पाच उद्दिष्टांपैकी एखादेच सुफळ संपूर्ण झाले. बाकीची अर्धवट, अनिर्णित आहेत. इराणचा प्रतिकार इस्रायलच्या अंदाजापेक्षा आणि अमेरिकेकडील कथित गोपनीय माहिती आधारित अपेक्षांपेक्षा कितीतरी अधिक चिकट आणि चिवट ठरला. त्यांची प्रहारक्षमता आजही शाबूत आहे. सध्या जी काही चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत, त्यांच्या केंद्रस्थानी इराणकडील युरेनियमचे समृद्धीकरण किती स्तरापर्यंत मर्यादित असावे, हा मुद्दा आहे. हे समृद्धीकरण विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करता आले, तर त्याचा उपयोग अणुवीज प्रकल्पांसारख्या नागरी उद्दिष्टांपर्यंत सीमित राहतो. त्या मर्यादेवरील समृद्धीकरण क्षमता प्राप्त केल्यास, इराण अणुबॉम्ब बनवण्यास सिद्ध ठरतो. म्हणून इराणकडील युरेनियम साठा आणि समृद्धीकरण क्षमता कमीत कमी राहील याविषयी दक्षता बाळगली जाते. यासाठी सन २०१५ मध्ये तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रयत्नान्ती करार झाला. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात तो झुगारून दिला. त्याचा फायदा घेऊन इराणने समृद्धीकरणाचा वेग आणि क्षमता वाढवली. तेव्हा करार नाही तर लष्करी कारवाईनेच त्यास वेसण घालावे असा ट्रम्प-नेतान्याहू दुकलीचा प्रयत्न होता. पण यासाठी जून २०२५ आणि फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने जो अण्वस्त्र कार्यक्रम मातीमोल करण्यासाठी अग्निवर्षाव केला, त्याची पाळेमुळे अजूनही शाबूत आहेत! मग कारवाई कशासाठी झाली. आणि दुसऱ्या प्रयत्नातही इराणची अण्वस्त्रे बनवण्याची क्षमता नष्ट झाली नसेल, तर तिसऱ्यांदा तशी कारवाई होणारच नाही याची हमी ट्रम्प आणि इस्रायलचे नरसंहारी पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू देणार का?

ती द्यावी की न द्यावी या कात्रीत दोघेही सापडले आहेत. दोघांनी युद्ध सुरू केले ते राजकीय गरजेपोटी. आज तेच युद्ध दोघांसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल अशी चिन्हे आहेत. इस्रायलमध्ये येत्या ऑक्टोबर महिन्यात तेथील कायदेमंडळाच्या निवडणुका आहेत. त्यांत बहुमत मिळणे हे नेतान्याहूंना अवघड वाटते. तिकडे अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यात मध्यावधी निवडणुका होत आहेत. त्यांत फटका बसल्यास ट्रम्प यांची काँग्रेसवरील पकड ढिली होईल नि पुढील दोन वर्षे सध्या सुरू आहे तशी मनमानी थांबवावी लागेल. ट्रम्प प्रशासनातील, त्यांच्यासह सर्व शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्ती युद्धाविषयी वेगवेगळी वक्तव्ये करत आहेत. परराष्ट्रमंत्री रुबियो म्हणतात 'युद्ध संपले'. संरक्षणमंत्री पीट हेग्सेथ म्हणतात 'युद्धसज्ज आहोत'. खुद्द ट्रम्प म्हणतात युद्ध थांबवण्याविषयी तोडगा अगदी दृष्टिपथात आला आहे. आता हे ते पहिल्यांदा युद्धविराम जाहीर झाला, तेव्हा म्हणजे ८ एप्रिलपासून सातत्याने म्हणत आहेत हा भाग निराळा. युद्धसमाप्तीच्या वाटाघाटींमध्ये होर्मुझची कोंडी फोडण्याचा उल्लेख नाही. ती फुटत नाही तोवर युद्ध संपले असे मानताच येणार नाही. अण्वस्त्र कार्यक्रमासंबंधी इराणने काही तडजोडी करण्याची तयारी दाखवली आहे. होर्मुझबाबत मात्र त्यांचा ताठा कायम आहे. त्यांची नाविक कोंडी करण्याविषयी अमेरिकेचा बाणा कायम आहे. हे सगळे सुरू असताना, नेमके युद्ध सुरू आहे की संपले, संपले तर संबंधित देशांची युद्धसज्जता काय दर्शवते असे अनेक प्रश्न दिवसेंदिवस निरुत्तरित राहिले आहेत. म्हटले तर युद्ध, मानला तर विराम अशा विचित्र अवस्थेत सारे थिजल्यागत झालेले दिसते. असले 'यदाकदाचित युद्ध' प्रत्यक्ष युद्धाइतकेच नुकसानदायी ठरत आहे याची फिकीर ना ट्रम्पना आहे, ना नेतान्याहूंना आहे, ना इराणला!

विरोधक आत्ता नाही तर कधी ठाम उभे राहणार?

लेख

योगेंद्र यादव
'स्वराज इंडिया'चे सदस्य आणि 'भारत जोडो' अभियानाचे राष्ट्रीय निमंत्रक
yyadav@gmail.com

विरोधी पक्षांसाठी हा आत्मपरीक्षणाचा, चिंतनाचा, काही कटू सत्यांना सामोरे जाण्याचा आणि काही कठीण प्रश्न विचारण्याचा काळ आहे, याबाबत कोणतीही शंका नसावी. दोन वर्षांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकांच्या धक्कादायक निकालांमुळे जी संधीची खिडकी उघडली गेली होती, ती तेव्हापासून सातत्याने संकुचित होत गेली आणि आता तर ती पूर्णपणे बंद झाली आहे. पश्चिम बंगालमधील विजय ही, 'सर्वंकष सत्ता' मिळवण्याच्या भाजपच्या मोहिमेतील एक मोठी झेप आहे. त्याच वेळी, समकालीन भारतातील निवडणूक प्रक्रियेच्या सचोटीचे जे काही अवशेष शिल्लक आहेत, त्या संदर्भात मात्र ही एक मोठी पीछेहाट आहे. विरोधी पक्षाने आपला जुना पराभूत दृष्टिकोन सोडून देऊन, नवीन धोरणे आणि कार्यक्षम यंत्रणेसह पूर्ण तयारीने पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे. अन्यथा, लोकशाहीतील विरोधी पक्षाची भूमिका नगण्य होऊन स्पर्धात्मक लोकशाही संपून जाईल. एखादी व्यक्ती किंवा एखादी शक्ती पुढे येऊन निवडणूक क्षेत्रातील समतोल पुन्हा प्रस्थापित करत नाही आणि किमान काही प्रमाणात तरी निष्पक्षता परत आणत नाही, तोपर्यंत निवडणुका या कदाचित यापुढे 'लोकइच्छा व्यक्त करण्याचे माध्यम' उरणार नाहीत आणि ही केवळ विरोधी पक्षांसाठीच नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांसाठीही अत्यंत वाईट बाब आहे.

केरळ आणि तमिळनाडूमधील निकालांमुळे आपण या कटू सत्यापासून विचलित होता कामा नये. केरळमध्ये जे काही घडले आहे, ते सत्तेतील लांबलेल्या दोलायमान अवस्थेचे पुनरुज्जीवन आहे. सत्तेवर असलेला पक्ष बदलून नवे सरकार यावे ही लोकमानसात असलेली भावना आणि एलडीएफ सरकारबद्दलची अस्वस्थता यातून केरळमध्ये सत्तांतर घडले. याचा नैसर्गिक फायदा यूडीएफला झाला. केरळमध्ये सहसा डावे आणि काँग्रेस आलटून-पालटून सत्तेवर येतात. मागच्या २०२१ च्या निवडणुकीत तसे घडले नाही. पुन्हा डावेच सत्तेवर आले. पाच वर्षांचा या विलंबाचा थोडाफार फायदा काँग्रेसला त्यांच्या वाढीव मतांमधून मिळाला. यात भाजपचा मतटक्का वाढला नाही, असा दिलासा विरोधी पक्षांना दिलासा मिळू शकतो, पण सत्तेच्या प्रचंड ताकदीपुढे असा दिलासा तात्पुरता असतो. उलटपक्षी, राज्यातील अल्पसंख्याक मतांवरील यूडीएफचे अतिअवलंबित्व हे त्यांच्यासाठी दीर्घकाळात चिंतेचे कारण असू शकते.

तमिळनाडूमध्ये विजय थलपती यांच्या टीव्हीकेला मिळालेले यश नाट्यमय आणि विस्मयकारक असले तरी, ते इतरत्र अनुकरण करण्याजोगे प्रारुप नाही. द्रमुकचे वर्चस्व निर्माण झाले होते आणि त्याबरोबर आलेल्या उन्माद आणि आत्मसंतुष्टतेमुळे मतदारांना द्रमुकला पर्याय हवा होता. सतत कोसळणाऱ्या आणि पुन्हापुन्हा नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या एआयएडीएमके पक्षाकडे मतदार पर्याय म्हणून बघत नव्हते, कारण तो राज्यातील राजकीय संस्कृतीच्या विरोधात असलेल्या भाजपचीच एक शाखा मानला जात होता. तमिळींना ही पोकळी द्रविड विचारधारेत बसणाऱ्या पण द्रमुकच्या राजकीय प्रारुपापेक्षा वेगळ्या अशा व्यक्तीकडून भरून हवी होती. एमजीआर यांनी घालून दिलेल्या मार्गावर चालत, चित्रपट अभिनेता असलेल्या विजय थलपती यांनी एक आकर्षक आणि नवीन पर्याय लोकांपुढे आणला. विजय थलपतींच्या बाबतीत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ते द्रमुकला आपला 'राजकीय विरोधक' मानतात, तर भाजपला 'वैचारिक विरोधक'. ते स्वतःला पेरियार, कामराज आणि आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवून घेतात. तमिळनाडूसारख्या राज्यात एखाद्या नेत्यासाठी असा हा अवकाश अद्वितीय म्हणावा असाच आहे.

यापुढच्या काळात राष्ट्रीय राजकारणासाठी कोणतीही योजना आखण्याआधी विरोधी पक्षांनी केवळ पश्चिम बंगालमधल्याच नाही, तर पंजाब, कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचलमधील आपल्या प्रशासकीय कामगिरीचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

आसाममध्ये विरोधकांनी कोणत्याही सबबींमागे लपू नये. भारतातील निवडणुकीच्या इतिहासात आपल्या फायद्यासाठी भाजपने अभूतपूर्व अशा प्रमाणावर, मतदारसंघांच्या सीमांची जातीय धर्तीवर फेररचना (gerrymander) करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर केला, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्यक्ष मतदान होण्यापूर्वीच, भाजपने स्वतःच्या पदरात सुमारे १० जागा पाडून घेतल्या होत्या. शिवाय, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेत असतानाच, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी 'मियाँ' समुदायाविरुद्ध उघडपणे आणि निर्लज्जपणे जातीय द्वेष पसरवला. हे सगळे खरे असले तरी, सत्ताधारी पक्षाचा सामना करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती विरोधकांनी अजिबातच दर्शवली नाही, ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारता येत नाही. भाजप सरकार आणि विशेषतः मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. जुबिन गर्ग यांचा मृत्यू हा एक अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक मुद्दा होता. तो सरकारच्या विरोधात जाणारा ठरला असता. तरीही, विरोधकांनी आपली बाजू समर्थपणे मांडण्यासाठी किंवा एकजूट दाखवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले आहेत, असे कधीच दिसून आले नाही. निवडणूक कशी हरायची, याचे हे एक आदर्श उदाहरण ठरले.

बंगालमधील विरोधी पक्षांना मात्र या गोष्टींना सामोरे जावे लागले नाही. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला सहज विजय मिळू दिला, असा आरोप कोणीही त्यांच्यावर करू शकले नाही. भाजपच्या आक्रमणाचा आणि प्रचंड ताकदीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेली रणनीती, चिकाटी आणि यंत्रणा ममतांकडे होती. विरोधी पक्षांमध्ये म्हणावी तेवढी एकजूट नव्हती, हे खरे आहे; पण डाव्या पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्याचा त्यांना फायदाच झाला. काँग्रेसमुळे तृणमूलचे अत्यंत नगण्य म्हणता येईल, असेच नुकसान झाले. अशा प्रकारे, बंगाल हे विरोधी पक्षांसाठी एक 'चाचणी' (test case) ठरली. मात्र ही अशी चाचणी होती, जिच्याकडे प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्याने नक्कीच काहीशा धाकधुकीने पाहिले असेल.

निवडणुकीतील निकालात झालेली ही एवढी मोठी उलथापालथ, लोकांच्या मनात सरकारबद्दल अस्वस्थता आणि नाराजी असते तेव्हा येणाऱ्या 'सत्ताविरोधी लाटे'शिवाय शक्य झाली नसती, पण ही लाट फारशी लक्षातच घेतली गेली नाही. लोकांचा जेवढा राग ममता बॅनर्जी यांच्या स्थानिक नेत्यांवर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर होता, तेवढा ममता यांच्यावर नव्हता. इतर राज्यांमध्ये अशाच आणि त्याहूनही वाईट दर्जाच्या सरकारला लोकांनी अशा पद्धतीने धारेवर धरले नाही, हे खरे आहे. पण भाजप आणि त्यांच्याशी निष्ठा राखणाऱ्या माध्यमांना झडप घालण्यासाठी काही तरी मिळाले. त्यामुळे यापुढच्या काळात विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणासाठी कोणतीही योजना आखण्याआधी, केवळ पश्चिम बंगालमध्येच नाही, तर पंजाब, कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचलमधील आपल्या प्रशासकीय कामगिरीचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

अखेरीस, पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील सर्वात अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती आपण मान्य करू या. या निवडणुकीचा निकाल हा केवळ जनमताचे एक साधे प्रतिबिंब नाही. तर तो केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने सुनियोजितपणे घडवून आणला आहे. २०२४ मधील पीछेहाटीनंतर बंगालमधील भाजपची अवस्था अत्यंत विस्कळीत झाली होती आणि तृणमूल काँग्रेसचा सामना करण्याची त्यांच्यामध्ये अजिबात क्षमता उरली नव्हती. केंद्र सरकार आणि भाजप-समर्थक प्रसारमाध्यमांनीच त्यांना सावरले आणि बळ दिले. केंद्राने पश्चिम बंगाल सरकारला संसाधनांपासून वंचित ठेवून त्याची कोंडी केली; त्यांनी मनरेगा आणि पीएम आवास योजनांसारखे कार्यक्रम रोखून धरले. भाजपने आसामपेक्षाही अधिक प्रभावी ठरेल अशी एक द्वेषपूर्ण आणि जातीयवादी प्रचारमोहीम राबवली बंगालमध्ये, तेव्हा निवडणूक आयोग केवळ बघ्याची भूमिका घेत राहिला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने २७ लाख मतदारांची नावे (एकूण वगळलेल्या ९० लाख नावांपैकी) वगळण्यासाठी इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने, असाधारण पावले उचलली; या मतदारांनी गणना अर्ज भरले होते आणि आपली नागरिकत्वाची कागदपत्रे सादर केली होती. प्रत्येक स्वतंत्र तपासणीतून हेच दिसून येते की, नावे वगळण्याची ही कृती अन्यायकारक आणि हेतुपुरस्सर होती. वगळण्यात आलेली ही नावे राज्यातील एकूण मतदानाच्या ४.३ टक्के इतकी आहेत. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसवर भाजपला मिळालेली आघाडी ४.६ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे या २७ लाख व्यक्तींना मतदान करण्याची परवानगी दिली असती, तर त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर काय परिणाम झाला असता, हा प्रश्न टाळता येत नाही.

आपण रणांगणातून पळ काढत आहोत, असा आभास निर्माण न करता, बनावट पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या निवडणूक निकालांना कायदेशीर मान्यता देणे नाकारण्याचे धाडस विरोधक दाखवू शकतील का? आता विशेषतः पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीनंतरही ते हे धाडस दाखवणार नसतील तर मग ते ठाम भूमिका घेऊन कधी उभे राहणार आहेत? भारतीय निवडणुकांचे पावित्र्य आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान पातळी आता खालावली आहे का, हा खूप कठीण प्रश्न आहे, पण विरोधकांना एकजुटीने त्याचा सामना करावाच लागेल.

अन्वयार्थ

मराठी सरकारच्या 'हिंदी प्रेमा'ची परीक्षा?

रिक्षा – टॅक्सी चालकांसाठी मराठीची सक्ती करण्याच्या शासनाच्या आदेशावरून निर्माण झालेल्या वादाचा धुरळा खाली बसण्यापूर्वीच सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता हिंदी परीक्षेवरून वादाला तोंड फुटले आहे. राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाकडून १९५१ पासून सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे मूलभूत ज्ञान असावे या उद्देशाने वर्षातून दोनदा हिंदी भाषेची परीक्षा घेतली जाते. गरजेनुसार केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हिंदी या २२ पैकी एक असलेल्या अधिकृत भाषेचे ज्ञान असावे हा यामागचा उद्देश. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतरही राज्य शासनाच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते. १९७६ मध्ये राज्य शासनाने हिंदी परीक्षेबाबत काही नियम तयार केले होते. इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत हिंदी हा विषय घेतला नसलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही परीक्षा बंधनकारक असते. यामुळे अशा अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना सेवेत दाखल झाल्यावर तीन वर्षांत ही परीक्षा देणे आवश्यक असते. ती दिली नसल्यास वेतनवाढ रोखली जाते. परिणामी बढतीची संधी हुकते. यानुसारच येत्या २८ जूनला सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्यात येणार होती. आतापर्यंत सुमारे ३५ हजार अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली आहे. या परीक्षेला मनसे, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मराठी भाषा अभ्यास केंद्राने केलेल्या विरोधानंतर ही परीक्षा स्थगित करण्यात येत असल्याचे मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. तूर्त तरी राज्य शासनाने हिंदी विषयावरून निर्माण होणारा वाद टाळला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे धोरण हिंदीला अनुकूल असेच बघायला मिळते. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये महायुती सरकारने केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा धोरणाचा सूत्राचा स्वीकार करताना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची केली होती. या विरोधात रान माजल्यावर गेल्या जून महिन्यात सरकारने हिंदी सक्तीचा आदेश रद्द करीत तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भाषा शिकण्याची मुभा दिली होती. महायुती सरकारचा हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला होता. या विरोधात उद्धव व राज ठाकरे बंधूंनी एकत्र येत मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले होते. या मोर्चाच्या भीतीने तसेच महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर वाद पेटू नये म्हणून फडणवीस सरकारने त्रिभाषा सूत्राचा आदेश रद्द केला होता. तसेच भाषेचे धोरण ठरविण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्रिभाषा सूत्राचा आदेश तूर्त मागे घेण्यात आला असला तरी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून तो लागू करण्याचे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले होते. नवीन शैक्षणिक वर्ष पुढील महिन्यात सुरू होईल. अजून तरी महायुती सरकारने त्रिभाषा धोरणावर काही निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच महाराष्ट्र दिनापासून रिक्षा चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केल्याने भाजप सरकारची पंचाईत झाली. फडणवीस सरकार मराठीची सक्ती करीत असल्याने हिंदी भाषकांमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रियेमुळेच बहुधा हा निर्णय १५ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेचा मुद्दा वादग्रस्त ठरू लागला.

दरम्यान राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झालेल्या बहुसंख्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तिसरी भाषा ही संस्कृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संस्कृतमध्ये पैकीच्या पैकी गुण मिळणे सोपे असल्याने विद्यार्थ्यांचा कल संस्कृतकडे असतो. यामुळेच हिंदी भाषेची परीक्षा देणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असते. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या दक्षिणी राज्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशी परीक्षा द्यावी लागत नाही. मग महाराष्ट्रातच हिंदीचा आग्रह का, असा मनसे, शिवसेनेचा सवाल आहे. त्यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता घेण्यात येणारी हिंदीची परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस मराठी भाषा विभागाने केली आहे. शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यासाठी अनुकूल असले तरी भाजपचे हिंदी प्रेम व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून हिंदीचे केले जाणारे अप्रत्यक्ष समर्थन लक्षात घेता हिंदीच्या विरोधात निर्णय होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. मराठी, हिंदी हे विषय संवेदनशील असताना सत्ताधारीच हा विषय उकरून काढत असल्याने भाषक वाद निर्माण होत आहेत. राज्याचा कारभार मराठीतून होत असताना कर्मचाऱ्यांना हिंदी परीक्षेची सक्ती का, हा सवालही तेवढाच रास्त आहे.

भारतीय बँकांना 'मायथोस'ची भीती का?

विश्लेषण

संजय जाधव
sanjay. jadhav@expressindia. com

मायथोस काय आहे?

कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील अँथ्रोपिक कंपनीने क्लॉड मायथोस हे एआय मॉडेल विकसित केले आहे. गुंतागुंतीची सायबर सुरक्षा कामे हाताळण्याची त्याची क्षमता आहे. सॉफ्टवेअर 'बग' शोधणे आणि सिस्टीमचे विश्लेषण मायथोस सहजपणे करू शकतो. सध्या याची नियंत्रित पद्धतीने चाचणी सुरू असून, त्याला प्रोजेक्ट ग्लासविंग असे नाव देण्यात आले आहे. संरक्षणात्मक सायबर सुरक्षेसाठी काही ठरावीक कंपन्यांना तो वापरण्याची परवानगी सध्या देण्यात आली आहे. सध्याची एआय साधने ही मानवास साहाय्य करणारी आहेत. मायथोसमुळे हे समीकरण बदलले असून, तो स्वयंचलितपणे काम करू शकतो.

मायथोस काय करू शकतो?

सायबर सुरक्षेच्या अनेक कामांमध्ये मायथोस मानवापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करू शकतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आणि वेब ब्राऊजरमधील हजारो त्रुटी शोधून त्यांचा गैरवापर करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. त्यातच मायथोस चाचणीच्या टप्प्यात काही जणांनी अनधिकृतरीत्या वापरल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्याचा गैरवापर होण्याची भीती असून, जागतिक पातळीवर सायबर सुरक्षेचा धोका निर्माण झाला आहे. सायबर सुरक्षा धोके किती जलद निर्माण होऊ शकतात, याचे हे ज्वलंत उदाहरण असल्याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. मानवी सायबर हल्ल्यांच्या पुढे जात मायथोसमुळे एआयद्वारे स्वयंचलित हल्ल्यापर्यंत हा प्रवास आलेला आहे.

भारतीय बँकांना काय धोका?

मायथोससारख्या एआय साधनांचा गैरवापर करून डिजिटल पायाभूत व्यवस्थेतील कमकुवत दुवे शोधून त्यावर हल्ला केला जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत देशातील वित्तीय व्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल बनली आहे. त्यातूनच वित्तीय व्यवस्थेला आता मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत सरकारने बँकांना इशारा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना त्यांची डिजिटल पायाभूत यंत्रणा आणि सायबर सुरक्षा भक्कम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संगणकीय प्रणाली आणि सायबर सुरक्षेविषयी कोणतीही संशयास्पद बाब निदर्शनास आल्यास नियामकांना तातडीने कळविण्यासही बँकांना सांगण्यात आले आहे. भारतीय बँकांच्या संगणकीय प्रणालीचे काम बाह्य स्रोताद्वारे मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. हे काम करणाऱ्या कंपन्यांकडे सायबर सुरक्षेची एकसारखी आणि अद्ययावत साधने नसल्यानेही धोका वाढल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

बँकांकडून कोणती पावले?

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) खर्चात वाढ करण्याचे पाऊल उचलले आहे. यामागे मायथोसमुळे निर्माण झालेला धोका कारणीभूत आहे. बँकिंग प्रणालीसह ग्राहकांच्या विदेची सुरक्षितता जपण्यासाठी बँका पावले उचलत आहेत. सर्वच

जगभरातील बँकिंग नियामकांकडून क्लॉड मायथोससारख्या एआय साधनांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत इशारा देण्यात येत आहे. यामुळे मायथोसची भारतीय बँकांनी धास्ती घेतली आहे. बँकिंग यंत्रणेसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणांची सायबर सुरक्षा या साधनामुळे तकलादू ठरत आहे. देशातील अधिकाधिक डिजिटल बनलेल्या बँकिंग यंत्रणेला यामुळे निर्माण होणारा धोकाही जास्त आहे. त्यामुळे आतापर्यंत साहाय्यकारी ठरणारे एआय तंत्रज्ञान धोक्याची घंटा ठरू लागले आहे.

बँकांकडून चालू आर्थिक वर्षात आयटी पायाभूत सुविधा खर्चात वाढ केली जाणार आहे. जागतिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या तंत्रज्ञानात्मक आव्हानांचा सामना आणि बँकिंग प्रणालीचे संरक्षण यावर बँकांकडून भर देण्यात येत आहे. बँकांकडून आयटीवर वाढणारा खर्च हा एकप्रकारे त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित बनला आहे.

मायथोस सार्वजनिक का नाही?

अँथ्रोपिकने मायथोसचे सार्वजनिक वितरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सायबर सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका ही कारणे यासाठी देण्यात आली आहेत. हे एआय साधन चुकीच्या हातात पडल्यास जगभरात सायबर सुरक्षेचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कंपनीला वाटते. त्यामुळे काही ठरावीक कंपन्यांना नियंत्रित पद्धतीने मायथोसचा वापर करण्याची परवानगी दिली जात असून, त्यातही जास्त जोखीम असलेल्या एआय यंत्रणांचा समावेश आहे.

इतर देशांकडून उपाययोजना काय?

मायथोसमुळे बँकिंग यंत्रणांवर काय परिणाम होतो, यावर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील नियामक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ब्रिटनमधील नियामक आणि प्रमुख बँकांची नुकतीच सायबर सुरक्षा संस्थांशी चर्चा झाली. त्यावेळी महत्त्वाच्या माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांची जोखीम तपासण्यात आली. सध्या असलेल्या सायबर सुरक्षेच्या कवचाला भेदून एआय साधने धोका निर्माण करू शकत असल्याने याबद्दल जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. याच वेळी वित्तीय व्यवस्थेला त्यातून निर्माण होणारी जोखीमही मोठी ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात एआयचे आव्हान एआयच्या मदतीनेच परतवून लावण्यासाठी पावले उचलावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

साइबर अपराध में वृद्धि

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में देशभर में अपराध की घटनाओं में छह प्रतिशत की गिरावट आयी, पर साइबर अपराध 18 फीसदी बढ़ गया. वर्ष 2023 के 62.41 लाख मामलों के मुकाबले 2024 में अपराध के 58.85 लाख मामले दर्ज किये गये. पर इस दौरान साइबर अपराधों में वृद्धि चिंताजनक है. हालांकि 2024 में कई मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ. जैसे, इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 1.5 फीसदी की गिरावट आयी, 2024 में 4.41 लाख मामले दर्ज किये गये, जबकि 2023 में 4.48 लाख मामले दर्ज हुए थे. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामले में भी 2024 में कमी आयी. इस दौरान अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के 55,698 मामले दर्ज किये गये, जो 2023 के 57,789 मामलों की तुलना में 3.6 फीसदी कम थे. अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में भी 23.1 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गयी. वर्ष 2024 में ऐसे कुल 9,966 मामले दर्ज किये गये, जबकि 2023 में 12,960 मामले दर्ज किये गये थे. वर्ष 2024 में हत्या के 27,049 मामले दर्ज किये गये, जो पिछले साल के मुकाबले 2.4 फीसदी की मामूली गिरावट दिखाते हैं. हालांकि, इस अवधि में आर्थिक अपराधों में 4.6 फीसदी की वृद्धि हुई. वर्ष 2023 में आर्थिक अपराध के जहां 2,04,973 मामले दर्ज किये गये थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,14,379 हो गया. बच्चों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी रही. वर्ष 2024 में 98,375 बच्चे लापता हुए, जो 2023 के 91,296 बच्चों के मुकाबले 7.8 फीसदी की वृद्धि है. राज्यों में अपराधों की दर के मामले में केरल प्रति लाख आबादी पर 513 मामलों के साथ सबसे आगे रहा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली अव्वल रही, जहां प्रति लाख आबादी पर 1,258.5 मामले दर्ज हुए. ऐसे ही, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले में कर्नाटक सबसे आगे रहा. लेकिन 2024 में साइबर अपराधों में वृद्धि बेहद चिंताजनक है. इस दौरान साइबर अपराध के कुल 1,01,928 मामले दर्ज किये गये, जो 2023 के मुकाबले 17.9 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2023 में साइबर अपराध के 86,420 मामले दर्ज किये गये थे. रिपोर्ट बताती है कि साइबर अपराधों में सबसे ज्यादा मामले ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े हैं, जिनमें फर्जी निवेश योजनाएं, ओटीपी स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, बैंक फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिये ठगी के मामले शामिल हैं. जाहिर है, तेजी से डिजिटल होते भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में अपराध की घटनाएं कम हुईं, पर साइबर अपराध 18 फीसदी बढ़ गये. तेजी से डिजिटल होते भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.

सोमनाथ हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री
https://x.com/narendramodi

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला. अब 11 मई को मुझे फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है. इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है. मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था. उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी. सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता. आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है. यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है.

जय सोमनाथ. वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला. यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था. अब 11 मई को मुझे फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है. इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है. मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था. उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी. छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है.

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है. इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनूभूति कराता है. इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है. तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता. हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है : 'प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्'. अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझायी नहीं जा सकी. कई साम्राज्य आये और गये, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा. यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे. लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया. चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था. समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी. ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था. कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभायी. भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया. विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की. महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर ने, जिनकी 300वीं जयंती मनायी जा रही है, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा. बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की. इसके साथ ही, हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है. उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है.

पूरे भारत में 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना फैल रही थी. सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी. ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा. तेरह नवंबर, 1947 को दिवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा. सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा. यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी.' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नये उत्साह से भर दिया. दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था. इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इसके बावजूद प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है. उनके विजन को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला. वर्ष 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर उसे ऐतिहासिक बना दिया.

मुझे अक्तूबर, 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था. सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2001 को गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया. उसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनायी जा रही थी. उस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने उसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया. डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई, 1951 को अपने भाषण में कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता. उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी. इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं. पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं. 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है. इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान भी बनाये रखी है. आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है.

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते. भारत के विभिन्न हिस्सों से आये लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया. उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी. वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता. आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है. सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है. इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जायेगी. यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं. सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता. आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है. यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है.

मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें. जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब इसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे. वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई. वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखा. आप समझ पायेंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी. वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है. मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा.

'दृष्टि' के जरिये भारत के नये अंतरिक्ष युग की शुरुआत

पीके जोशी
सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक से जुड़े रहे हैं
pkjoshi@mail.jnu.ac.in

कैलिफोर्निया से गैलेक्सआइ द्वारा एक खास उपग्रह (दृष्टि) को अंतरिक्ष में भेजा जाना दिखाता है कि भारतीय स्टार्टअप अब तेजी से उन्नत अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं. जब 'दृष्टि' पृथ्वी की कक्षा में अपनी यात्रा शुरू करेगा, तो वह सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों और उम्मीदों को भी साथ लेकर चलेगा.

भारतीय स्टार्टअप अब तेजी से उन्नत अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं. कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट में भारतीय स्टार्टअप, गैलेक्सआइ द्वारा एक खास उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाना इस नवपरिवर्तन को दिखाता है. इसका नाम है 'दृष्टि'. यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि दिखाती है कि अब अंतरिक्ष क्षेत्र सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं द्वारा शुरू किये गये स्टार्टअप इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों ने जो मजबूत नींव तैयार की, उस पर निजी कंपनियां नयी ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं.

इसकी महत्ता को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि पारंपरिक उपग्रह संवेदक कैसे काम करते हैं. आमतौर पर उपग्रह संवेदक दो प्रकार की तकनीक पर आधारित होते हैं- ऑप्टिकल (प्रकाशीय संवेदक) और सिंथेटिक (कृत्रिम) अपर्चर रडार (एसएआर). ऑप्टिकल संवेदक बिल्कुल सामान्य कैमरे की तरह काम करते हैं. ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के आधार पर तस्वीरें लेते हैं, जिससे स्पष्ट और समझने में आसान चित्र प्राप्त होते हैं. पर इनकी एक सीमा है- ये बादल, धुएं या सूर्य के प्रकाश के अभाव में काम नहीं कर पाते. दूसरी ओर एसएआर तकनीक, माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग करती है, जो बादलों और धुएं को आसानी से पार कर सकते हैं, और अंधेरे में भी काम करते हैं. इससे हर समय, हर मौसम में निगरानी करना संभव हो जाता है. हालांकि, एसएआर से मिलने वाली तस्वीरें सामान्य चित्र जैसी नहीं होतीं, बल्कि एक्स-रे जैसी जटिल होती हैं, जिन्हें समझने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है. 'दृष्टि' को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें इन दोनों तकनीकों को एक ही उपग्रह में जोड़ा गया है. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि दोनों संवेदक एक ही समय पर एक ही स्थान की तस्वीर लेने के लिए पूरी तरह समन्वित हैं. इस तकनीक को गैलेक्सआइ ने 'ऑप्टोएसएआर' नाम दिया है. पहले ऑप्टिकल और एसएआर के संलयन के लिए विभिन्न उपग्रहों और विभिन्न समयों से प्राप्त चित्र लेने पड़ते थे, जिससे अक्सर अध्ययन में असंगति आ जाती थी. 'दृष्टि' इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है. अब यदि बादलों या अंधेरे के कारण ऑप्टिकल संवेदक काम नहीं कर पाता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एसएआर डाटा से ऑप्टिकल जैसे चित्र तैयार किये जा सकते हैं.

'दृष्टि' को बनाना आसान नहीं था. ऑप्टिकल और एसएआर सेंसर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं तथा पृथ्वी को अलग-अलग कोण से देखते हैं. यदि इनमें ठीक से तालमेल न किया जाये, तो ये अलग-अलग स्थानों की तस्वीरें ले सकते हैं. गैलेक्सआइ ने अपनी विशेष तकनीक के जरिये इस समस्या को हल किया और दोनों संवेदकों को एक साथ काम करने के लिए तैयार किया. इससे हर समय उपयोगी चित्र उपलब्ध रहेंगे. यह सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, व्यावहारिक बदलाव भी है, क्योंकि इससे उपग्रहीय आंकड़े अब अधिक लोगों के लिए उपयोगी और सुलभ हो जायेंगे. इस उपलब्धि को भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में समझना भी जरूरी है. चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉसमॉस और हैदराबाद स्थित स्काइरूट एयरोस्पेस जैसे स्टार्टअप पहले ही थ्रीडी प्रिंटेड रॉकेट इंजन और निजी रॉकेट लॉन्च जैसी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं. वहीं पिक्सेल (नयी दिल्ली), ध्रुवा स्पेस (हैदराबाद) और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (बेंगलुरु) जैसी कंपनियां उपग्रह और प्रणोदन तकनीकों में नये प्रयोग कर रही हैं. ये सभी मिलकर भारत में एक मजबूत और तेजी से विकसित हो रहा अंतरिक्ष बाजार बना रहे हैं. 'दृष्टि' की उपयोगिता भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. यहां अक्सर बादल छाये रहते हैं, खासकर मॉनसून के दौरान, जिससे ऑप्टिकल छायाचित्रण में बाधा आती है. ऐसे में यह उपग्रह आपदा प्रबंधन, कृषि योजना और पर्यावरण निगरानी में मददगार साबित हो सकता है. गैलेक्सआइ के संस्थापकों ने साबित किया है कि बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़े संसाधन हों- जरूरी है सोच, नवाचार और लगातार प्रयास की.

'दृष्टि' जैसी तकनीक हमें सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, अन्य ग्रहों को जानने में भी मदद करेगी. शिक्षा के क्षेत्र में भी 'दृष्टि' एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा. इससे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आने वाले समय में और अधिक नवाचार देखने को मिलेगा. 'दृष्टि' का प्रक्षेपण न केवल अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन को एक नयी दिशा देता है, बल्कि यह भारतीय स्टार्टअप्स की क्षमता और आत्मविश्वास का भी प्रमाण है. जब 'दृष्टि' पृथ्वी की कक्षा में अपनी यात्रा शुरू करेगा, तो वह सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों और उम्मीदों को भी साथ लेकर चलेगा. यह याद दिलायेगा कि प्रगति उन्हीं लोगों के कारण होती है जो अलग सोचने का साहस रखते हैं. भारत के लिए यह एक नये अंतरिक्ष युग की शुरुआत है, और दुनिया के लिए इस बात का संकेत है कि जब नवाचार की कोई सीमा नहीं होती, तब संभावनाएं भी असीमित हो जाती हैं. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

बोधि वृक्ष

शांति की तलाश

आज की दुनिया में सफलता की एक ही परिभाषा रह गयी है- प्रसिद्धि, पद और पैसा. लेकिन क्या कारण है कि इन तीनों को प्राप्त कर लेने के बाद भी व्यक्ति के भीतर एक अजीब-सा खालीपन बना रहता है? बड़े-बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति भी आज भीतर से शांत नहीं हैं. इसका कारण है कि हमने सफलता को केवल 'बाहर' खोजा है और अपने 'भीतर' के संतोष को विस्मृत कर दिया है. हमें सफलता और संतोष के भीतर के अंतर को समझना होगा. जब तक हम इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझेंगे, यूं ही जीवनभर शांति के लिए भटकते रहेंगे. तो क्या है सफलता और शांति के बीच में अंतर. सफलता एक 'उपलब्धि' है, जिसे समाज देखता है, जबकि संतोष एक 'अनुभूति' है, जिसे केवल हम महसूस करते हैं. जब जीवन केवल उपलब्धियों की होड़ में बीतता है, तब अंत में केवल थकान और अवसाद ही हमारे हाथ लगते हैं. लेकिन जब जीवन अनुभूति से जुड़ता है, तब हमारा हर पल आनंददायक बन जाता है. हमें समझना होगा कि जीवन केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु होने के लिए है. दौड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्यहीन दौड़ व्यर्थ है. इससे हमें शांति नहीं मिलती, अपितु हम पूरे जीवन अशांत बने रहते हैं और शांति की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं. यदि आप सचमुच शांति पाना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में से कम से कम दस मिनट स्वयं के लिए निकालिए और ऐसी जगह जाइए जहां न मोबाइल हो और न सांसारिक शोर. यहां आप अपने मन में आने वाले व्यर्थ के विचारों को भी बाहर निकाल दीजिए. इस तरह जब आप भीतर से शांत होकर स्वयं के साथ बैठना शुरू करेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि जिसे आप पूरी दुनिया में खोज रहे थे, जिसे पाने के लिए न जाने कब से भटक रहे थे, वह परम शांति तो आपके भीतर ही विद्यमान थी. इस तरह आप अपने भीतर बदलाव लाकर उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, जिसकी चाह आपके मन में न जाने कब से थी. कमाना जरूरी है, पर जीना सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, इस बात को यदि आप याद रखेंगे, तो कभी भी अशांत नहीं होंगे.

-मुनिश्री प्रमाणसागर जी महाराज

कुछ अलग

प्रतीक्षा का भी अपना सौंदर्यशास्त्र है

सुधांशु शेखर
टिप्पणीकार
sshekhar.shekhar2@gmail.com

अभी पिछले दिनों एक बहुमंजिली इमारत की लिफ्ट के पास खड़ा था. मेरे साथ खड़ा युवक लिफ्ट आने में हुई चंद सेकंड की देरी से इतना बेचैन हो गया कि उसने पांच-सात बार बटन दबा डाला और झुंझलाते हुए मोबाइल पर अपनी अंगुलियां तेजी से चलाने लगा. उसकी छटपटाहट केवल एक लिफ्ट के लिए नहीं थी, बल्कि वह उस 'त्वरित युग' (इंस्टेंट एरा) का प्रतिबिंब थी, जिसमें हम सब आज जी रहे हैं. हम ऐसी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, जहां प्रतीक्षा करना अपराध जैसा लगने लगा है और धैर्य एक लुप्तप्राय गुण बन चुका है.

आज की दुनिया 'टू मिनट नूडल्स' से शुरू होकर 'इंस्टेंट लोन', 'फास्ट ट्रैक' सफलता और '15 सेकंड' की रील संस्कृति तक सिमट गयी है. तकनीक ने हमें गति तो दी है, पर हमारा धैर्य छीन लिया है. हम भूल गये हैं कि प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाएं- चाहे वह फूल हो, मां के गर्भ में पलता शिशु हो या सदियों पुरानी चट्टानों का आकार हो- धैर्य और समय की लंबी प्रतीक्षा से ही निर्मित होती हैं. 'इंस्टेंट' होने के इस मोह ने हमारी मानसिक संरचना को इस कदर बदल दिया है कि हम अब जीवन 'जीने' की बजाय उसे 'स्वाइप' करने के आदी हो गये हैं. इस संस्कृति का सबसे गहरा प्रहार हमारी वैचारिक एकाग्रता और संवेदनाओं की गहराई पर हुआ है. जब हम अतीत की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि महान कृतियां, कालजयी साहित्य और अमर विचार, वर्षों की मौन साधना से उपजे थे. पर आज हम महज हेडलाइन पढ़कर विशेषज्ञ होना चाहते हैं. जब हम चंद सेकंड के वीडियो क्लिप्स के आदी हो जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क गंभीर विमर्श करने या लंबी वैचारिक चर्चाओं को आत्मसात करने का धैर्य खो देता है. यह 'सतहीपन' हमारे समाज के लिए एक बौद्धिक आपदा की तरह है.

विडंबना यह है कि इस गति का असर हमारे मानवीय रिश्तों की गर्माहट पर भी पड़ा है. संवाद अब 'इंस्टेंट मैसेजिंग' तक सीमित है, जहां शब्दों के पीछे की भावनाएं 'इमोजी' के बोझ तले दब गयी हैं. पुराने समय में लोगों को पत्रों का इंतजार होता था, जिसमें शब्दों के साथ लिखनेवाले की धड़कन भी महसूस होती थी. आज 'ब्लू टिक' न आने पर उपजी बेचैनी ने रिश्तों के उस भरोसे को भी घायल कर दिया है, जो कभी 'मौन' रहकर भी एक-दूसरे को समझ लेता था. प्रतीक्षा का अपना सौंदर्यशास्त्र होता है. जब सब कुछ बिना किसी प्रतीक्षा के मिल जाता है, तो उस उपलब्धि का मूल्य भी कम हो जाता है. यही कारण है कि आज सफलताएं और साधन तो बहुत हैं, लेकिन उस 'तृप्ति' का अभाव है, जो केवल ठहर कर मिलती है. अभी भी समय शेष है, तो क्यों न हम 'ठहरने' की कला फिर से सीखें.

आपके पत्र

असंगठित मजदूरों की समस्याएं

असंगठित क्षेत्र के मजदूर देश की प्रगति का आधार हैं, फिर भी वे अनेक कठिनाइयों से जूझते हैं. उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जानकारी की कमी और जटिल प्रक्रियाएं बाधा बनती हैं. कार्यस्थल पर दुर्घटना या आपदा की स्थिति में उनके पास बीमा और आर्थिक सहारा नहीं होता, जिससे उनका जीवन असुरक्षित हो जाता है. सरकार से आग्रह है कि वह योजनाओं को सरल और सुलभ बनाये तथा मजदूरों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करे.

मजहरुल हक, गोड्डा

छात्र आत्महत्या से उठते सवाल

उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्या केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, हमारे शैक्षणिक ढांचे की गहरी खामियों के संकेत हैं. हाल के वर्षों में देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से आत्महत्या के मामलों का लगातार सामने आना बताता है कि यह समस्या सतही नहीं, संरचनात्मक है. यह उन सपनों की हत्या है जिन्हें संजोकर एक छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश करता है. इसका कारण संस्थानों के भीतर के स्वस्थ वातावरण का अभाव होना है, जिसकी विद्यार्थियों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है.

युगल किशोर राही, छपरा

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें** : 0651-2544006 ■ **मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

मार्केट अपडेट सेंसेक्स 77,844.52 ↓ 114.00 (0.15%) | निफ्टी 24,326.65 ↓ 4.30 (0.018%)

क्विक बाइट्स

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 114 अंक टूटा

मुंबई. विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी तथा वैश्विक अनिश्चितता के बीच गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट आयी. सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 77,844.52 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 78,384.70 अंक के उच्चस्तर तक गया और 77,713.21 अंक के निचले स्तर तक आया. वहीं एनएसइ निफ्टी 4.30 अंक के मामूली नुकसान के साथ 24,326.65 अंक पर बंद हुआ.

एमएमटीपी-पीएएमपी ने डिजिटल सोने, चांदी की खरीद का मंच शुरू किया

नयी दिल्ली. बहुमूल्य धातुओं को परिष्कृत करने वाली कंपनी एमएमटीसी-पीएएमपी डिजिटल रूप में सोने और चांदी की खरीद को फिर से शुरू कर दिया है. अब उपभोक्ता गूगल पे, पेटीएम और फोनपे के साथ ही कंपनी की वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से सीधे डिजिटल सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं.

एसबीआइ देगा 80,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज

मुंबई. भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (इसीएलजीएस) 5.0 के तहत बैंक अपने ग्राहकों को 70,000-80,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध करा सकता है. पात्र ग्राहकों की पहचान हो चुकी है और नये दिशानिर्देशों के अनुरूप यह ऋणसुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इसीएलजीएस 5.0 को मंजूरी दी थी.

इलेक्ट्रिक वाहन व बैटरी में चीनी तकनीक पर निर्भरता कम करने की तैयारी

टाटा व जेएसडब्ल्यू ग्रुप इवी क्षेत्र में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश

नेशनल कंटेंट सेल

भारतीय दिग्गज कंपनियां टाटा समूह और जेएसडब्ल्यू समूह लगभग एक अरब डॉलर का निवेश कर रही हैं. दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी तकनीक में घरेलू क्षमताएं विकसित कर रही हैं. इस कदम का उद्देश्य चीनी तकनीक पर निर्भरता कम करना है. अगली पीढ़ी की बैटरी तकनीक और एडवांस्ड इवी प्रणालियों में स्वदेशी विशेषज्ञता विकसित करने के उद्देश्य से दोनों कंपनियां अलग-अलग अनुसंधान और विकास केंद्र बना रहीं हैं. यह निवेश ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. फाडा के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की मांग में 75% की तेजी दर्ज की गयी है. इसलिए बड़ी कंपनियां अब अपनी खुद की टेक्नोलॉजी तैयार करने पर जोर दे रही हैं ताकि भविष्य में विदेशी तकनीक पर कम निर्भर रहना पड़े.

टाटा समूह कर रही 400 मिलियन डॉलर का निवेश

टाटा की बैटरी इकाई, अग्रतास लिमिटेड, बेंगलुरु में एक नये अनुसंधान एवं विकास केंद्र पर 400 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर रही है. यह केंद्र लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) और लिथियम मैंगनीज आयरन फॉस्फेट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर केंद्रित है, ताकि ऐसे उत्पाद बनाये जा सकें जिनके लिए वर्तमान में टाटा चीन पर निर्भर है.

जेएसडब्ल्यू समूह का 500 मिलियन डॉलर निवेश की तैयारी

जेएसडब्ल्यू मोटर्स भी समानांतर रूप से बैटरी टेक्नोलॉजी की दिशा में काम कर रही है. कंपनी के सीइओ रंजन नायक ने बताया कि कंपनी अगले पांच से छह वर्षों में महाराष्ट्र में एक अनुसंधान केंद्र में कम से कम 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है. नायक ने कहा कि जेएसडब्ल्यू वैश्विक साझेदारों के साथ विकसित वाहनों के स्थानीयकरण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा.

चीनी तकनीक के सहारे बढ़ी कंपनियों को आ रहीं दिक्कतें

इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी सबसे महंगी और तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल हिस्सा मानी जाती है. जिन कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम चीनी प्रौद्योगिकी पर आधारित किये थे, उन्हें अब देरी, उच्च अनुपालन बोझ और नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कम गारंटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. चीन भी अपनी अहम तकनीकों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है और उन्हें आसानी से शेयर नहीं करना चाहता है.

नयी तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है लक्ष्य : दोनों भारतीय कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में अपने को और मजबूत करना चाहती हैं. इसलिए सड़क वातावरण से लेकर मूल्य तय करने तक की भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नयी वैश्विक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगी हैं.

देश में 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम शुरू

एजेंसियां, नयी दिल्ली

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम की गुरुवार को शुरुआत की. दिल्ली स्थित इएसआइसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मांडविया ने कहा कि चार श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन देशभर के श्रमिकों के लिए सम्मान, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को दर्शाता है. मांडविया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए अब देशभर में हर वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जायेगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच के जरिये बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है और सामने आयी बीमारियों के उपचार व दवाएं इएसआइसी सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी. ये जांच इएसआइसी के व्यापक अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से की जायेंगी.

कोटक बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक व फेडरल बैंक में लेगी हिस्सेदारी

नयी दिल्ली. कोटक महिंद्रा बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक दोनों में 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआइ की मंजूरी मिल गयी है. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक ने गुरुवार को अलग-अलग से बताया कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी पत्र प्राप्त हुआ है. दोनों बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक को बैंक की चुकता शेयर पूंजी में कुल मिलाकर 9.99% तक हिस्सेदारी की मंजूरी मिली है.

पेटीएम ने एनबीएफसी लाइसेंस लेने की योजना से किया इनकार

एजेंसियां, नयी दिल्ली

पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योजना से इनकार किया है. कंपनी का चौथी तिमाही का आय संबंधी विवरण देते हुए पेटीएम के अध्यक्ष एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (समूह) मधुर देवड़ा ने गुरुवार को कहा, हम एनबीएफसी लाइसेंस लेने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पेटीएम की प्राथमिकता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी साझेदारी मॉडल की है जिसमें पेटीएम वितरण, प्रौद्योगिकी एवं वसूली का काम संभालता है जबकि उसके प्रतिष्ठित ऋण साझेदार पूंजी, जोखिम एवं चक्रीय उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करते हैं.

इस वर्ष 5.5% तक बढ़ सकती है बिजली की मांग : इक्रा

एजेंसियां, नयी दिल्ली

औद्योगिक एवं कमर्शियल गतिविधियों के निरंतर बढ़ने से 2026-27 में बिजली की मांग 5.0-5.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. 2025-26 में यह वृद्धि केवल एक प्रतिशत रही थी. साख निर्धारण करने वाली एजेंसी इक्रा ने यह बात कही. इक्रा ने कहा कि संभावित 'एल नीनो' के बीच सामान्य से कम वर्षा के आसार से वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि एवं घरेलू क्षेत्रों से भी मांग को समर्थन मिलने की संभावना है. साथ ही उद्योगों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों एवं डाटा सेंटर जैसे उभरते स्रोतों से भी मांग बढ़ेगी. देश में तापीय बिजली संयंत्रों का 'प्लांट लोड फैक्टर' (पीएलएफ या क्षमता उपयोग) 2025-26 में मांग में कमी के कारण घटकर 65-66 प्रतिशत रह गया. यह 2026-27 में करीब 65 प्रतिशत पर आ सकता है. नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन में अच्छी वृद्धि और तापीय क्षेत्र में छह गीगावाट क्षमता वृद्धि की संभावना इसकी मुख्य वजह रहेगी.

शिकायतों का सही से समाधान नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर ₹50 लाख तक जुर्माना

ट्राइ का प्रस्ताव

एजेंसियां, नयी दिल्ली

दूरसंचार नियामक ट्राइ ने गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों के लिए ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक नयी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा. इसमें नियमों के उल्लंघन के मामलों में दूरसंचार कंपनियों पर प्रति तिमाही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया है. सेवा प्रदाताओं के वेब पोर्टल, एप और चैटबॉट पर स्पष्ट शिकायत पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. साथ ही पंजीकृत शिकायतों पर की गयी कार्रवाई के बारे में उपभोक्ताओं को नियमित रूप से जानकारी दी जायेगी. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) के मसौदा पत्र के मुताबिक, यदि शिकायत की पड़ताल में यह पाया जाता है कि किसी शिकायत या अपील को अनुचित तरीके से खारिज किया गया है या असंतोषजनक ढंग से निपटाया गया है, तो सेवा प्रदाता पर ऐसी हरेक शिकायत के मामले में 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं, अपील को अनुचित तरीके से निपटाने की स्थिति में, प्रत्येक गड़बडी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

चांदी 7,000 रुपये हुई महंगी सोना भी ₹600 हुआ मजबूत

एजेंसियां, नयी दिल्ली

औद्योगिक मांग में सुधार के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 7,000 रुपये बढ़कर 2,61,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी. यह लगातार चौथा दिन है जब चांदी की कीमतों में तेजी आयी है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार पिछले सत्र में चांदी की कीमत में 3,500 रुपये बढ़कर 2,54,500 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी. वहीं, सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी. बुधवार को सोने की कीमत 2,900 रुपये बढ़कर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी. विशेषज्ञों के अनुसार यह तेजी डॉलर में गिरावट और अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण आयी है. वैश्विक बाजारों में, सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़त रही. हाजिर सोना 0.9% बढ़कर 4,734.28 डॉलर व हाजिर चांदी 5% से भी अधिक बढ़कर 81.35 डॉलर प्रति औंस हो गयी.

पहले पेज से

रिम्स में पांच साल पहले आ...

रिम्स के जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स विभाग में 17 प्रकार की अनुवांशिक जांच की जा रही है, लेकिन जांच में तीन से 15 दिन का समय लग रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग में जांच के लिए सिर्फ दो टेक्नीशियन हैं. यहां पांच लैब टेक्नीशियन की जरूरत है. इसके अलावा डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता भी है.

घूम रही है फाइल, जांच की दर नहीं हुई तय : रिम्स द्वारा आयोजित 37 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 30 जुलाई 2025 को हुई थी. इसमें अनुवांशिक बीमारियों की जांच की सुगमता, मैनपावर, जांच की दर और अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा हुई थी. बताया गया था कि होल एग्जोम सीक्वेसिंग की दर तय करने के लिए पीजीआइ चडीगढ़ की जांच की दर को आधार बनाना होगा. उस हिसाब से जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स विभाग ने जांच की दर 8,000 से 12,000 रुपये तय करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एक साल बाद भी अब तक दर निर्धारण पर फैसला नहीं हुआ है.

सहायक आचार्य के...

उक्त फैसला जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया है. हर शैक्षणिक वर्ष के लिए भी कोर्ट ने शिड्यूल तय किया है. पीठ ने यह आदेश सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया. पीठ ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 तथा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली-2022 के तहत बनायी गयी नियुक्ति प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गये शिक्षक सिर्फ अपनी लंबी सेवा के आधार पर किसी न्यायिक आदेश से नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते. प्रार्थी सुनील कुमार यादव व अन्य की ओर से अलग-अलग एसएलपी दायर की गयी थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राज्य के 24 जिलों के सरकारी स्कूलों में लगभग डेढ़ लाख सहायक शिक्षकों की कमी है.

ट्रेन में लहरा रहे थे...

जानकारी के अनुसार ट्रेन के सामान्य कोच से अचानक यात्रियों के चीखने-चिल्लाने की आवाज आने लगी. शोर सुनकर आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी वहां पहुंची. वहां एक युवक पिस्तौल लहराते हुए यात्रियों को धमका रहा था, जबकि उसका साथी बदसलूकी कर रहा था. जवानों ने बिना समय गंवाये दोनों को पकड़ा. आरोपियों की पहचान बरियातू के सरताज कॉलोनी निवासी अकीब खान (21) पिता-आरिफ खान और रेहान खान (20) पिता-स्व सलीम खान के रूप में की गयी. आरोपियों ने बताया कि हथियार वह रांची में आपूर्ति करनेवाले थे.

पीछा कर रास्ता रोका...

मगर इन दोनों में लगे नंबर फर्जी हैं. कार का चेचिस नंबर भी मिटाया हुआ है. रथ के वाहन के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी है. उनका कोलकाता के एक अस्पताल में उनका चल रहा है. दो ऑपरेशन के बाद भी उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमलावरों ने संभवतः 'ग्लॉक 47 एक्स' पिस्तौल का इस्तेमाल किया. ऐसे हथियार आम अपराधी सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करते. पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसमें पेशेवर शूटर शामिल थे. घटनास्थल से खोखे और कारतूस बरामद किये गये हैं. हमले का मकसद स्पष्ट नहीं है. हमले में उन्नत हथियारों के इस्तेमाल का संदेह है.

विमान में मोइत्रा को देख लगे 'टीएमसी चोर' के नारे

नयी दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने इंडिगो की उड़ान में पुरुषों के एक समूह द्वारा उत्पीड़न और नारेबाजी का आरोप लगाया है. घटना उस समय हुई जब मोइत्रा कोलकाता से दिल्ली एक संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने जा रही थीं. विमान के उतरते ही कुछ यात्रियों ने उनके खिलाफ 'टीएमसी चोर' और 'जय श्री राम' जैसे नारे लगाए और वीडियो बनाया. मोइत्रा ने इस व्यवहार को 'भाजपा संस्कृति' करार देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री और इंडिगो से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने दोषियों को 'नो-फ्लाइ लिस्ट' में डालने का आग्रह करते हुए कहा कि यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है. इंडिगो ने इस मामले में औपचारिक शिकायत मांगी है. पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद राज्य में जारी राजनीतिक तनाव के बीच इस घटना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

झारखंड

झारखंड में अब नहीं चलेगा गिट्टी, बालू व पत्थर का अवैध धंधा : डॉ निशिकांत

संवाददाता, देवघर

झारखंड से गिट्टी, बालू, पत्थर और शराब के गैर कानूनी कारोबार को लेकर गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है. गुरुवार को देवघर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड अब चारों ओर से एनडीए शासित राज्यों से घिर चुका है, इसलिए गैर कानूनी खनिज कारोबार, तस्करी और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को टकराव की राजनीति छोड़कर केंद्र के साथ समन्वय बनाना होगा, क्योंकि अब बिहार और पश्चिम बंगाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से गिट्टी, बालू और पत्थर की ढुलाई नहीं होने दी जायेगी.

गुवाहाटी, सूरत व हैदराबाद की हवाई सेवा इस वर्ष शुरू होगी : सांसद डॉ दुबे ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट से इस वर्ष मुंबई व कोलकाता के लिए प्रतिदिन फ्लाइट सेवा शुरू कर दी जायेगी. नयी हवाई सेवा में गुवाहाटी, हैदराबाद व सूरत के लिए भी यहां से सीधी हवाई सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी मंत्रालय के स्तर से हो गयी है. इस वर्ष नयी हवाई भी शुरू होगी. उन्होंने बताया कि देवघर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 450 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है. जल्द टेंडर कर काम चालू होगा.

पत्रकारों को जानकारी देते डॉ निशिकांत.

गोड्डा से कोटा की सीधी ट्रेन, साहिबगंज व पाकुड़ को मिलेगा वंदे भारत : डॉ निशिकांत ने बताया कि इस वर्ष गोड्डा से वाया देवघर गुजरात और कोटा के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जायेगी. साहिबगंज व पाकुड़ क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन की सुविधा नहीं है,इसलिए भागलपुर से कोलकाता के लिए नयी वंदे भारत ट्रेन चलायी जायेगी. कहा कि बैद्यनाथ धाम स्टेशन के विकास के लिए रेल मंत्रालय ने 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है.

विक्रमशिला पुल का विकल्प बनेगा भवानीपुर व कुर्सेला के बीच रेल पुल : सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने बताया कि गोड्डा से महागामा रेल लाइन का काम दिसंबर 2027 तक पूरा हो जायेगा. उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद रेल मंत्री से विशेष आग्रह कर सरायगढ़ स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया गया है. देवघर को सीधे बुद्ध सर्किट और विक्रमशिला से जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट रेल कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है.

पुनासी में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट : सांसद डॉ दुबे ने बताया कि देवघर के पुनासी व बिहार के बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है. पुनासी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए राज्य सरकार से जमीन मांगी जा रही है. साथ ही गोड्डा में कुल चार कोल ब्लॉक आवंटित किये जाने हैं. इसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन को दो, जबलपुर की कंपनी व एक अन्य कंपनी को एक-एक कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है. सांसद ने कहा कि गोड्डा में पीपीपी मोड पर एक और पावर प्लांट लगाने को लेकर मंत्रालय स्तर पर बात चल रही है.

सेल रिफ्रैक्ट्री की चारों इकाइयों के डीमर्जर की तैयारी, ज्वाइंट वेंचर में होगा संचालन

प्रतिनिधि, भंडारीदह (बोकारो)

- सेल प्रबंधन जल्द जारी करेगा टेंडर, श्रमिकों में बढ़ी चिंता
- प्लांट संचालन में व्यावहारिक समस्याओं की प्रबंधन ने दी जानकारी

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की प्रमुख इकाई सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट (एसआरयू) की चारों इकाइयों का डीमर्जर कर उन्हें ज्वाइंट वेंचर के तहत संचालित किया जायेगा. यूनिटों में बोकारो का भंडारीदह, रामगढ़ जिला स्थित मरार का इफको व रांची रोड और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मरोदा का भिलाई प्लांट शामिल है. एसआरयू के भंडारीदह यूनिट प्रभारी सह जीएम सोमनाथ सेन ने बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सेल प्रबंधन ने एसआरयू की चारों इकाइयों को डीमर्जर कर ज्वाइंट वेंचर में चलाने का प्रस्ताव दिया है. डीमर्जर की प्रक्रिया के बाद ज्वाइंट वेंचर के तहत संचालन के लिए टेंडर जारी होगा. सेल प्रबंधन आगे की प्रक्रिया में जुटा है. इस बीच, एसआरयू भंडारीदह प्रबंधन ने श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्लांट की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया है. प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि प्लांट के संचालन में कई व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं.

इससे आने वाले समय में यहां से उत्पादित मटेरियल का खरीदार मिलना मुश्किल हो सकता है. वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट इसके उत्पादों के प्रमुख खरीदार हैं. लेकिन इन दोनों प्लांटों में उच्च क्षमता वाले ब्लास्ट फर्नेस लगाने की तैयारी चल रही है. इससे भंडारीदह में निर्मित मटेरियल का उपयोग संभव नहीं हो पायेगा. प्रबंधन ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्लांट चलाना कठिन होगा.

तालाब में डूबने लगी बुआ, बचाने के लिए गया भतीजा, दोनों की मौत

प्रतिनिधि, मेराल (गढ़वा)

मेराल के गोबरदहा गांव में गुरुवार सुबह तालाब में नहाने के दौरान डूबने के बुआ और भतीजे की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान जैनब खातून (17) और उसके भतीजे सुहेल खान (12) के रूप में हुई है. घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब जैनब खातून घर के पास तालाब में अपने भतीजे के साथ नहाने के लिए गयी थी. इसी दौरान वह गहरे पानी में चली गयी और डूबने लगी. जैनब को डूबता सुहेल उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया और वह भी डूब गया. इसके बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला. हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना प्रभारी विष्णु कांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया. हादसे की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर व अंचल पदाधिकारी यशवंत नायक मौके पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया.

बाइक की डिक्की से 25 लाख रुपये के जेवर उड़ा कर फरार हो गये चोर

चौपारण (हजारीबाग). चतरा रोड स्थित महाराजगंज बाजार में चोरी की घटना हुई. अलखदेव पोद्दार ने बुधवार देर शाम दुकान बंद करने के बाद बाइक की डिक्की में घर ले जाने के लिए कुछ जेवरात रखे थे. इसी दौरान अज्ञात चोर मौका पाकर डिक्की से लगभग 25 लाख रुपये मूल्य के गहने लेकर फरार हो गये. इसमें दर्जनों चांदी की पायल, सोने के झुमके, ढोलना, कान की बाली, टॉप्स, नथिया के अलावा ग्राहकों के ऑर्डर के पुराने सोने के जेवर भी शामिल थे. कुल मिलाकर लगभग 120 ग्राम सोने के गहने चोरी हुए.

दक्षिण पूर्व रेलवे - निविदा

निविदा सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजी आर एनसी-36-2026, दिनांक: 06.05.2026। भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक/अभियांत्रिकी/दक्षिण पूर्व रेलवे, रांची-834003 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम:** रांची मंडल में मूरी-कोटशिला खंड में झालिदा स्टेशन पर नए 6.10 मीटर चौड़े एफओबी द्वारा पुराने एफओबी की बदली, अनधिकृत प्रवेश और अतिक्रमण की संभावनाओं को रोकने के लिए रांची, नामकोम एवं टाटीसिलवे स्टेशनों के अप्रोचों पर चारदीवारी का निर्माण तथा मूरी सेटलमेंट पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण। **निविदा मूल्य:** ₹10,21,23,680.69। **जमा बयाना राशि का मूल्य:** ₹20,42,500। **निविदा बंद होने की तारीख और समय:** 28.05.2026 को अपराह्न 3:00 बजे। ऑनलाइन निविदा के लिए निविदादाता वेबसाइट www.ireps.gov.in देख सकते हैं। (PR-138)

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

निविदा सं.– टीआरडी/सोन/ई.टी./26–27/3 **1. कार्य का नाम एवं स्थान:** BAGL स्टेशन पर परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बारागोपाल यार्ड में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है **2. कार्य का अनुमानित मूल्य:** रू. 63,48,945/– **3. जमानत राशि:** रु. 1,27,000/– **4. निविदा प्रपत्र का मूल्य:** रु. 0/– **5. ई–निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खुलने की तिथि:** ई–निविदा प्रपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि एवं समय दिनांक 29.05.2026 को 12.00 बजे तक ई–निविदा प्रपत्र खुलने का निर्धारित समय: दिनांक 29.05.2026 को 12.00 बजे वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.) कार्यालय, पूर्व मध्य रेल/सोनपुर में खोले जायेगें । **6. वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड का लोकेशन जहाँ से ई–निविदा संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है:** वेबसाइट www.ireps.gov.in नोटिस बोर्ड मंडल रेल प्रबंधक /सोनपुर के कैम्पस भवन, पूर्व मध्य रेल /सोनपुर

वरिय मंडल विद्युत इंजीनियर / (क.वि) पूर्व मध्य रेल/सोनपुर
पीआर/0185/एसई/टीआरडी/टी/26–27/28

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरीय मंडल विद्युत अभियंता, टी.आर.एस., पूर्व मध्य रेलवे, बरौनी सुयोग्य एवं अनुभवी प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों से ई निविदा सं **BJU-ELS-TRS-2026-2027-01** हेतु खुला ई–निविदा आमंत्रित करती है। विवरण निम्नलिखित है:– **1. कार्य का नाम तथा स्थान:** ईएलएस/बीजेयू के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर थर्मल इन्सुलेशन की व्यवस्था के साथ और बिना ट्रफ वाले एयर कंडीशनर की स्थापनाए परीक्षण और कमीशनिग 2 वर्ष की अवधि के लिए। **2. कार्य का अनुमानित लागत:** रू. 1,55,67,431.60 (एक करोड़ पचपन लाख सड़सठ हजार चार सौ इकतीस रुपये और साठ पैसे मात्र) **3. अग्रधन, राशि:** रू. 3,11,400.00 **4. निविदा शुरू होने की तारीख और समय:** 15.05.2026 **5. बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:** 29.05.2026, 15:00 बजे। **6.** वेबसाइट का विवरण जहाँ निविदा दस्तावेज उपलब्ध है: www.ireps.gov.in विस्तृत निविदा सूचना, पात्रता मानदंड और निविदा दस्तावेज उपरोक्त वेबसाइट से देखे जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो सभी शुद्धिपत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

वरीय मंडल विद्युत अभियंता/टी.आर.एस./पूर्व मध्य रेल/बरौनी
पीआर/0183/ईएलएस/बीजेयू/ईएलईसीटी/टी/26–27/32

Government of Jharkhand
Urban Development & Housing Department
Office of the Gumla Nagar Parishad, Gumla

Very Short Term procurement Tender Notice

Short Term NIT No: GML/NP/01/2026-27

Sl No/ Group No	Name of work	BOQ value of work in Rs	Earnest Money	Cost of Documents Online (In Rs) Non-Refundable	Period of completion in months
1	Water Proofing of Office Building at Ward No 21 Under Nagar Parishad, Gumla	3,82,910.00	7,658.00	1,000.00	01 Month
	Total :	3,82,910.00			

1	Procurement Officer	Executive Officer, Nagar Parishad, Gumla.
2	Place of opening tender	Nagar Parishad, Gumla.
3	Date & Time of Sale of BOQ	13.05.2026 (10.00 AM to 02.00 PM)
4	Submission of Tender Documents	14.05.2026 till 03.00 PM
5	Date & Time of Opening of Tender	14.05.2026 till 03.30 PM

नोट :– (1)नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार में निबंधित संवेदक ही इस निविदा में भाग ले सकेगें।
(2) परिमाण विपत्र (B.O.Q.) के क्रय हेतु वैध एवं अद्यतन संवेदक निबंधन प्रमाण पत्र, GST Registration तथा आचरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिन परिमाण–विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी।
(3) परिमाण विपत्र (B.O.Q.) का क्रय बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जायेगा जिसकी वैधता परिमाण बिक्री की तिथि से कम से कम तीन माह तक होनी चाहिए। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PARISHAD, GUMLA के पदनाम से GUMLA में भुगतेय होगा।
(4) बिना कारण बताए एक या एक से अधिक निविदा को स्थगित करने, रद्द करने या एक से अधिक संवेदकों के बीच कार्य बाँटने का अधिकार निविदा समिति को सुरक्षित रहेगा।
(5) कार्य की प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है। परिणाम विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिणाम विपत्र का मूल्य मान्य होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, गुमला।

PR 379239 (District) 26-27 (D)

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बिहार की चुनौतियां

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां नई सरकार के शपथ का स्वाभाविक ही इंतजार चल रहा है। इस बीच, बिहार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन खास बन गया है और इस पर सबकी निगाह है। इस शपथ ग्रहण के साथ बिहार की राजनीति और सत्ता एक नई दिशा में बढ़ चली है। इसे हम पीढ़ीगत परिवर्तन भी कह सकते हैं। करीब दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं और इसकी चर्चा ज्यादा होना स्वाभाविक है। पचास वर्षीय निशांत कुमार तब राजनीति में आए हैं, जब उनके पिता अति-सक्रिय राजनीति से कुछ पीछे हट रहे हैं और मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया है। यहां लोग वंशवाद की चर्चा करेंगे, पर यह अपने आप में विरल है कि सत्ता में अपने पुत्र को लाने के लिए न पिता लालायित थे और न पुत्र में ऐसी कोई लालसा दिखाई पड़ रही थी। अक्सर भारतीय राजनीति में पिता-पुत्र का सत्ता-संघर्ष भी देखा गया है, पर इस मोर्चे पर नीतीश कुमार और उनके पुत्र एक मिसाल हैं। निशांत कुमार बिहार में नीतीश कुमार की पूरी भरपायी तो नहीं कर पाएंगे, पर उनसे लोगों को उम्मीदें जरूर होंगी।

बहरहाल, यह भी गौर करने की बात है कि निशांत कुमार चाहते, तो उप-मुख्यमंत्री का पद भी मांग सकते थे, पर वह केवल मंत्री बनने के लिए किसी तरह से तैयार हुए। अभी भी बिहार में जहां भाजपा का मुख्यमंत्री है, तो दो उप-मुख्यमंत्री जद-यू से आते हैं। बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत सत्तारूढ़ गठबंधन के 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। सत्ता साझा करने के मामले में भाजपा और जदयू के बीच बेहतरीन समन्वय दिखा है। भाजपा सहज ही जदयू को अपना बराबर का सहयोगी मानकर चल रही है। एलजेपी (रामविलास) के दो, एचएएम और आरएलएम से एक-एक नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर सरकार को मजबूत बनाया गया है। अब एक ऐसे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसे आगामी साढ़े चार साल तक बिहार की सेवा करनी है। यह इतिहास में दर्ज है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में बहुत सुधार किए, पर अभी इस राज्य को बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। जो खूबियां नीतीश कुमार के समय इस राज्य में पैदा हुईं, उन्हें संजोते हुए विस्तार देना होगा।

मंत्रिमंडल को जाति के चश्मे से नहीं, बल्कि योग्यता की दृष्टि से देखा जाए। किसी भी सरकार को उसके आंतरिक जातिगत-क्षेत्रगत समीकरण से नहीं परखा जाए।

मंत्रिमंडल में किस जाति, किस उपजाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, ये मामूली तथ्य हैं, असली सवाल तो यह है कि समग्रता में मंत्रिमंडल का प्रदर्शन कैसा रहेगा? समय आ गया है कि मंत्रिमंडल को किसी जाति के चश्मे से नहीं, योग्यता की दृष्टि से देखा जाए। किसी भी सरकार को उसके आंतरिक जातिगत-क्षेत्रगत समीकरण से नहीं, उसके काम से परखा जाना चाहिए। कोई संदेह नहीं, लालू प्रसाद यादव के बाद से बिहार में सामाजिक चेतना ज्यादा बलवती हो रही है, पर उसे ज्यादा अनुशासित ढंग से सही रचना शक्ति में बदलने का काम शेष है। बिहार की जनशक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक अच्छी सरकार वही होगी, जो इस जनशक्ति का अधिकतम सदुपयोग कर सकेगी। समाज में जरूरी बदलाव तभी आएंगे, जब सामाजिक संकेतकों के मामले में यह राज्य और तेजी से तरक्की करेगा। मुखर राज्य बिहार में राजनीति खूब होती है और आगे भी होगी, लेकिन यहां किसी भी राजनेता को अब विकास से समझौता नहीं करना चाहिए। लोगों ने डबल इंजन के पक्ष में मतदान किया है, चुनावी वादों पर भरोसा किया है, तो इस भरोसे पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश का समय शुरू हो चुका है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 मई, 1951

कांग्रेस की राजनीति

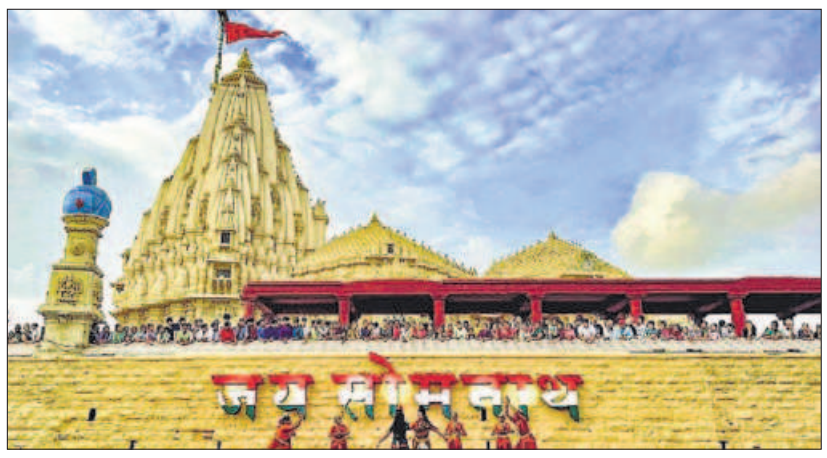

कांग्रेस-महासमिति का दिल्ली-अधिवेशन समाप्त हो गया। कांग्रेस में फूट के जो चिह्न पिछले समय से प्रकट हो रहे हैं, उनके कारण लोगों की दृष्टि इस बात की ओर आकर्षित हो रही थी कि महासमिति उसे रोकने का क्या उपाय करती है। अहमदाबाद में हुए महासमिति के अधिवेशन में एकता की जो मांग कांग्रेसजनों से की गई थी, उसके कारण एकता-प्रयास ने और भी महत्व ले लिया था। कृपलानी-किदवई के नेतृत्व में संगठित प्रजातांत्रिक मोर्चे ने, मुख्यतः नेहरूजी और मौलाना आजाद की प्रेरणा पर, जब अपने को खत्म कर लिया तो ऐसी आशा की गुंजाइश भी हो गई कि रूठे हुए दिल फिर मिलेंगे तथा जिस तरह एक होकर कांग्रेसजनों ने आजादी के लिए प्रयास किया, उसी प्रकार आजादी को सुदृढ़ करने और जन-साधारण को सुखी बनाने के प्रयास में भी वे एक रहेंगे। लेकिन, हमें मानना होगा कि महासमिति के अधिवेशन की समाप्ति के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेसजनों ने निश्चित रूप से एकता की ओर कदम उठा ही दिया है।

महासमिति के अधिवेशन का जहां तक संबंध है, वह निर्विघ्न सम्पन्न हुआ है। जहां तक कांग्रेस की उच्च सत्ता का संबंध है, यह भी निःसंशय कहा जा सकता है कि अपने रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए उदारता का हाथ बढ़ाने में उधर से कसर नहीं रखी गई। जिन मौलाना आजाद के प्रयत्न और प्रेरणा से प्रजातांत्रिक मोर्चा भंग हुआ, उन्हीं की जुबानी जब हम सुनते हैं कि मोर्चे के नेताओं को नजदीक लाने के उनके प्रयत्न में कांग्रेस-अध्यक्ष का रुख बहुत सहायतापूर्ण रहा, तो उसका दूसरा अर्थ यही लगाया जा सकता है कि यदि फिर भी सफलता नहीं मिली, तो दोष दूसरी तरफ हो सकता है। लेकिन एकता के प्रयत्न में दोष का दायित्व किसी पक्ष पर डालना उचित नहीं, क्योंकि उससे केवल खिजलाहट पैदा होती है। यह मान लेना ही ठीक होगा कि उस पक्ष की अपनी कुछ ऐसी कठिनाइयां होंगी, जिनसे विपक्ष की उदारता का साथ देने की स्थिति में वह न हो। मौलाना साहब ने अपने भाषण में ऐसा संकेत भी किया, जब उन्होंने बताया कि मोर्चे के नेता अपने पक्ष वालों के सामने बंध चुके हैं कि वे अभी कोई पद न लेंगे और उन्हें यह भी भय है कि उनका पद लेना सौदेबाजी समझा जायेगा।

सोमनाथ पुनरुद्धार की 75वीं वर्षगांठ

यहां स्कैन करें

नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री

11 मई, 1951 को अपने भाषण में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है।

हमारे प्राचीन शास्त्र में लिखा है : *प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्।* अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी।

ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक-सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक-आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा व राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर ने, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में, एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर, 1947 को दीवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके इस आह्वान ने गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के एम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जाम साहेब का समर्थन मिला। साल 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद उन्होंने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

11 मई, 1951 को अपने भाषण में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था, मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं।

पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है।

मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है।

भारत-अमेरिका संबंधों को फिर सुधारने का मौका

यहां स्कैन करें

सुरेंद्र कुमार | पूर्व राजदूत

जी हां, रोम एक दिन में नहीं बना था। इसी तरह, परस्पर रूप से लाभकारी रिश्ते भी एक दिन में नहीं बनते। अमेरिकी राष्ट्रपतियों और भारतीय प्रधानमंत्रियों को 'इतिहास की झिझक दूर करने' में 25 साल लग गए, तभी वे एक ऐसा संबंध रच सके, जो एशिया और विश्व के लिहाज से व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा को इसी की अगली कड़ी मानना चाहिए। इसमें भारत-अमेरिका संबंधों के तमाम पहलुओं पर खुलकर चर्चा करने और उन्हें संतुलित बनाने का मौका मिलेगा।

गौरतलब है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का मार्च 2000 का भारत दौरा खासा अहम था, क्योंकि यही क्लिंटन थे, जिन्होंने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। वह 1980 के दशक के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार किया, जिसे बाद के वर्षों में अमेरिकी नेताओं ने '21वीं सदी का सबसे निर्णायक संबंध' बताया।

दोनों देशों को संबंध सुधारने में 25 साल लग गए। अमेरिकी विदेश मंत्री की आगामी भारत यात्रा को इसकी अगली कड़ी मानना चाहिए।

इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी कांग्रेस में काफी प्रयास किए और इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक नाजुक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए भी 2005 में असैन्य परमाणु समझौते को संभव बनाया। नतीजतन, एनपीटी पर हस्ताक्षर न किए जाने के बावजूद हमारा परमाणु अलगाव खत्म हुआ। राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल में दो बार भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। वह एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी, 2015) में मुख्य अतिथि रहे हैं। एशिया-प्रशांत की राजनीतिक परिकल्पना उन्हीं की देन है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी सौहार्दपूर्ण संबंधों की झलक मिली, हालांकि व्यापार संतुलन तब भी भारत के पक्ष में था। उस काल को 'हाउडी मोदी' (22 सितंबर, 2019, ह्यूस्टन) और 'नमस्ते ट्रंप' (24 फरवरी, 2020, अहमदाबाद) के लिए भी याद किया जाएगा। 'क्वाड' को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडन, जिन्होंने न सिर्फ भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे और मजबूती दी।

साल 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर दिसंबर 2024 तक के द्विपक्षीय रिश्ते का मोटा-मोटा विश्लेषण करें, तो यही पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध पूरी तरह बदल गए हैं। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, रक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारियों की साझेदारी, आतंकवाद-विरोधी प्रयास, ऊर्जा खरीद जैसे तमाम क्षेत्रों में आपसी रिश्तों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वरिष्ठ नेताओं की द्विपक्षीय और शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से यह भरोसा पैदा हुआ है कि दोनों देशों के रिश्ते अलग मुकाम पर हैं, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली में सत्ता परिवर्तन से अछूते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दो बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता हैं, साथ ही वह तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों से राब्ता रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। जाहिर है, वह किसी अन्य नेता की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से निपटने में कहीं अधिक कुशल हैं।

मौजूदा स्थिति की बात करें, तो 2025 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 149.5 अरब डॉलर था, जिसमें भारत को लगभग 40 अरब डॉलर का सरप्लस था। भारत के रक्षा आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 13 फीसदी हो चुकी है। 14 अरब डॉलर का तेल, गैस और कोयले का आयात 2024 में हुआ था। द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल किया जा सकता है, खास तौर से भारतीय एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीदारी और तेल-गैस की बढ़ी हुई खरीद को देखकर।

साफ है, भारत-अमेरिका संबंधों को सिर्फ व्यापार और टैरिफ के नजरिये से देखना गलत होगा। यहां अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के प्रयासों की भी तारीफ करनी चाहिए, जो यहां आने के बाद से तमाम मंत्रियों से मिलकर संबंधों को नई ऊंचाई देने को तत्पर हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

हमें कैसा समाज चाहिए

मध्यमार्ग सदैव सुनहरा नहीं होता। वह प्रायः क्षीण दृष्टि, गुनगुनी उदासीनता अथवा कायरतापूर्ण अकुशलता के लिए एक प्रिय उक्ति होती है। लोग मध्यमार्गी, रूढ़िवादी अथवा अतिवादी कहलाते हैं और एक सूत्र के अनुसार अपने व्यवहार व विचारों को व्यवस्थित करते हैं। हम व्यवस्थाओं, पार्टियों के आधार पर सोचना पसंद करते हैं और यह भूल जाते हैं कि केवल सत्य ही मानदंड है।

रूढ़िवादी की स्थिति पर आश्चर्य होता है। वे सभी चीज को देवत्व प्रदान करने के लिए परिश्रम करते हैं। हिंदू समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और आदतें हैं, जो केवल रिवाजी हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं कि वे पुरातन समय में थीं और न कोई कारण है कि उन्हें भविष्य में भी क्यों बने रहना चाहिए?... न तो पुरातनता और न आधुनिकता ही सत्य की कसौटी हो सकती है। सभी ऋषि अतीत के नहीं थे; अवतार अब भी होते हैं; रहस्योद्घाटन अभी भी जारी है... आधुनिक समाज को मनु के अनुसार पुनर्निर्मित करना वैसा ही होगा, जैसे गंगा को वापस बहकर हिमालय जाने के लिए कहना।

निस्संदेह मनुष्य राष्ट्रीय हैं, पर ऐसी ही पशुबलि भी है। चूंकि एक वस्तु अतीत में राष्ट्रीय थी, इसके अर्थ यह नहीं कि वह भविष्य में भी राष्ट्रीय बनी रहे। बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार न करना मूर्खता है।... सभी वस्तुओं की एक तिथि और सीमा होती है। बहुत समय तक चलने वाली सभी प्रथाएं अपने समय में श्रेष्ठ रूप से उपयोगी रही हैं। हमें अतीत की उपयोगिता को नजरंदाज नहीं करना चाहिए, परंतु प्राथमिक रूप से हमें वर्तमान और भावी उपयोगिता की तलाश है।

प्रथा और कानून तब उसके अनुरूप बदले जा सकते हैं। प्रत्येक युग के लिए उसका अपना शास्त्र हो, पर हम सीधे-सीधे यह तर्क नहीं कर सकते कि उसे बदलना ही चाहिए या यदि परिवर्तन आवश्यक भी हो, तब भी उसे एक निश्चित दिशा में ही बदलना चाहिए। समाज सुधारकों के नासमझ उत्साह से तो नफरत पैदा होती है। प्रायः उनके मस्तिष्क अनपची यूरोपीय धारणाओं के विचित्र गड्ड-मड्ड होते हैं। उनमें से बहुत कम यूरोप के विषय में कुछ जानते हैं और जो वहां हो आए हैं, उन्हें भी उसकी बड़ी खराब जानकारी होती है। पर वे यूरोपीय धारणाओं के विरुद्ध कही गई बातों या विचारों को अंधवश्विासी, असभ्य, हानिकर के अलावा और कुछ कहना स्वीकार नहीं करेंगे तथा यूरोप में जिसकी प्रशंसा की जाती है, उसे तर्कसम्मत व प्रबुद्ध के अतिरिक्त और कुछ समझना भी उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा।

सबसे महत्व का प्रश्न यह है कि समाज प्रतियोगी होगा या सहकारी, व्यक्तिवादी होगा या साम्यवादी? यदि इन बातों का निर्णय हो जाए, तो छोटी-छोटी बातें खुद ठीक हो जाएंगी।

सबसे महत्व का प्रश्न यह है कि समाज प्रतियोगी होगा या सहकारी, व्यक्तिवादी होगा या साम्यवादी? यदि इन बातों का निर्णय हो जाए, तो छोटी-छोटी बातें खुद ठीक हो जाएंगी।

श्री श्री अरविंद

तो लाम | राष्ट्रपति, वियतनाम

हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि वह जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने हनोई की मुक्ति के चंद हफ्तों के भीतर वियतनाम का दौरा किया था। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले शासनाध्यक्ष थे।

चुनावी वायदों को पूरा करना आसान नहीं

तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनी, तो उस पर 40-सूत्रीय घोषणा-पत्र को पूरा करने का दबाव बढ़ेगा। इस घोषणा-पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए कई आकर्षक योजनाएं शामिल हैं, पर इन वायदों के आर्थिक बोझ को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, तमिलनाडु का वार्षिक बजट लगभग 4,39,293 करोड़ रुपये का है। ऐसे में, यदि घोषणा-पत्र के वायदों को एक साथ लागू किया जाए, तो राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ना तय है। महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये तक भत्ता, पांच लाख नौजवानों को नौकरी, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर और किसानों की ऋण-माफी जैसे वायदों को सामूहिकता में देखें, तो खर्च का आंकड़ा बजट की सीमाओं को चुनौती देता नजर आता है।

हकीकत यह है कि चुनावी लाभ के लिए दी जाने वाली मुफ्त योजनाएं अल्पकालिक राहत तो देती हैं, लेकिन दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती हैं। इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता है, उत्पादक निवेश घटता है और समाज में सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ने लगती है। परिणामस्वरूप, विकास आधारित अर्थव्यवस्था की जगह सब्सिडी आधारित व्यवस्था हावी हो जाती है। निस्संदेह, राजनीति में लोकप्रियता और भावनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शासन केवल भावनाओं पर नहीं चलता। फिल्मों में जहां हर समस्या का समाधान संभव दिखाया जाता है, वहीं वास्तविक प्रशासन में हर फैसले का असर बजट, राजकोषीय घाटे और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ता है। ऐसे में 'फिल्मी अंदाज' में किए गए वायदे, यदि ठोस आर्थिक आधार के बिना हों, तो जोखिम भरे साबित हो सकते हैं।

भारतीय लोकतंत्र की यह एक कटु सच्चाई है कि चुनावी वायदों और उनके क्रियान्वयन के बीच अक्सर बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कई बार वायदे पूरे नहीं होते या सीमित रूप में लागू किए जाते हैं, जिससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। विजय का घोषणा-पत्र भले ही जनहित और जन-कल्याणकारी राजनीति की बात करता हो, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये वायदे कितने यथार्थवादी और आर्थिक रूप से टिकाऊ हैं। लोकतंत्र में केवल आकर्षक घोषणाएं ही नहीं, ठोस और जिम्मेदार नीतियां भी जरूरी होती हैं। यदि राजनीति केवल मुफ्त योजनाओं की होड़ तक सीमित रह गई, तो इसका असर आने वाले समय में राज्य की आर्थिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और समग्र विकास पर पड़ना तय है।

मृदुल विकास तिवारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
चुनावी रेवड़ी

रेवड़ी संस्कृति कई मामलों में फायदेमंद

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत और तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने की एक बड़ी वजह है चुनावी वायदे। यही कारण है कि चुनावी रैलियों में किए गए वायदों को अब कागजों से निकालकर हकीकत की जमीन पर उतारने की मांग तेज हो गई है। इसका अर्थ है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ राजनीतिक दलों को सत्ता सौंपी है, उस पर खरे उतरने का उनका वक्त आ गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वे आर्थिक चुनौतियां भी गिना रहे हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि चुनावी वायदे पूरे नहीं हो सकते। किंतु हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि चुनावी वायदे न सिर्फ पूरे होते हैं, बल्कि उनका प्रभाव भी खूब पड़ता है।

'रेवड़ी संस्कृति' या जिनको मुफ्त की योजनाएं कहकर उपहास उड़ाया जा रहा है, वे मुख्य रूप से गरीब और वंचित वर्गों को तात्कालिक राहत देती हैं और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की राह बनाती हैं। इससे कमजोर वर्गों को सीधे-सीधे लाभ मिलता है। ये योजनाएं शिक्षा-स्वास्थ्य में समानता लाती हैं और कुछ मामलों में महिलाओं को आर्थिक मजबूती का एहसास कराती हैं। भले ही, ऐसी योजनाओं को आर्थिक स्थिरता के लिहाज से बड़ी चुनौती माना जाता हो, लेकिन असलियत में ये वंचित तबकों के लोगों को सशक्त बनाने में मदद करती हैं। बिजली, पानी या राशन जैसी मुफ्त सुविधाएं गरीब परिवारों के घरेलू बजट को संतुलित करती हैं। मुफ्त लैपटॉप या बस पास जैसी सुविधाओं से महिलाओं और छात्रों को शिक्षा व रोजगार में मदद मिलती है। मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को सेहतमंद बनाने और उनमें साक्षरता दर बढ़ाने में मददगार मानी जाती हैं। इसी तरह, मुफ्त टैबलेट या इंटरनेट योजनाओं से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलता है। छोटे कारोबार के लिए कर्ज देने संबंधी सुविधाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हैं। कृषि सब्सिडी से उनको खेती-बाड़ी में मदद मिलती है। क्या इन सब योजनाओं को गलत कहा जाएगा? जिन राज्यों में ये योजनाएं चल रही हैं, क्या वहां की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं आया है?

यही कारण है कि अगर कोई इन योजनाओं का विरोध करता है, तो साफ है कि उसके पास या तो सामाजिक-आर्थिक समझ नहीं है या फिर ऐसी योजनाओं का लाभ न मिल पाने के कारण वह खुन्नस खाए बैठा है। कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की योजनाएं कल्याणकारी राज्य का हिस्सा हैं। इनसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती ही है।

रमेश राम, टिप्पणीकार

हमें तनाव न बनाए बूढ़ा और बीमार

देर रात तक फोन चलाना, हर समय की भागदौड़, गलत खानपान, धूम्रपान और प्रदूषण, ये सब मिलकर ऐसा तनाव पैदा कर रहे हैं, जिसे हमारा शरीर हर पल भुगत रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने से उत्पन्न तनाव। यह आधुनिक जीवनशैली की ऐसी छिपी हुई कीमत है, जो हम अपनी सेहत गंवाकर चुका रहे हैं। शरीर को भीतर से कैसे मजबूत करें, बता रही हैं शमीम खान

हर समय की थकान, मुरझाया चेहरा, कम उम्र में जोड़ों में दर्द और हाल की छोटी-छोटी बातें भूल जाने की शिकायतें, ऐसा झेलने वाले आप अकेले नहीं हैं। गलत खानपान व खराब जीवनशैली के कारण शरीर में लगातार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्तर बढ़ रहा है। यही तनाव हमें समय से पहले बूढ़ा और बीमार बना रहा है। शरीर में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन होने पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है।

ऑक्सीडेटिव तनाव और भावनात्मक तनाव अलग-अलग हैं, लेकिन लंबे समय एक का बने रहना, दूसरे का कारण बन सकता है। इससे बेचैनी, अवसाद आदि समस्याओं से जूझ रहे लोगों में खतरा और बढ़ जाता है।

फ्री रेडिकल्स व एंटीऑक्सीडेंट्स को समझें

हमारा शरीर भोजन पचाने की क्रिया के दौरान फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स उत्पन्न करता है। शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के कुछ अणु अस्थिर हो जाते हैं, यही फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स उन 'बिन बुलाए मेहमानों' की तरह हैं, जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति पैदा करते हैं। ये प्रदूषण, तनाव और गलत खान-पान से पनपते हैं और शरीर के डीएनए को चोट पहुंचाते हैं। इस कारण बीमारियां व बुढ़ापा जल्दी आता है। फ्री रेडिकल्स बढ़ने से त्वचा का कसाव तेजी से कम होता है।

एंटीऑक्सीडेंट्स एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को शांत कर उन्हें बेअसर कर देते हैं, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। शरीर जितना अधिक फ्री रेडिकल्स बनाता है, उतना एंटीऑक्सीडेंट की रक्षा प्रणाली पर जोर बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसा बने रहने से शरीर में नई कोशिका बनने और उनकी कुदरती मरम्मत की प्रक्रिया बाधित होने लगती है।

संभलने का संकेत

■ याददाश्त कमजोर होना ■ कम उम्र में मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द ■ असमय चेहरे पर झुर्रियां व बालों में सफेदी ■ बार-बार संक्रमण की चपेट में आना ■ सिरदर्द ■ नजर तेजी से कमजोर होना ■ अत्यधिक थकान

शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने के कारण

वे सभी कारण जो शरीर में सूजन और फ्री रेडिकल्स की मौजूदगी बढ़ाते हैं, वे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। कुछ कारण हैं- ■ हानिकारक यूवी रेडिएशन का संपर्क ■ धूम्रपान ■ पौष्टिक आहार की कमी ■ वायु प्रदूषण ■ दूषित पानी का सेवन ■ कीटनाशकों का सेवन (अजैविक रूप से उगाई गई सब्जियां) ■ निष्क्रिय जीवनशैली ■ पर्याप्त नींद न लेना ■ धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन आदि।

OXIDATIVE STRESS

80 प्रतिशत से अधिक उम्र बढ़ने के लक्षण (झुर्रियां, याददाश्त कम होना, आंखों की कमजोरी) शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से होते हैं।

06 घंटे से कम नींद लेने वालों में सी-रिएक्टिव प्रोटीन अधिक देखा गया है, जो फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर में होने वाली सूजन का संकेत है।

20 प्रतिशत शरीर की ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारा दिमाग करता है। यही वजह है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का असर दिमाग पर अधिक पड़ता है।

30 प्रतिशत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अधिक देखने को मिला है प्रदूषित इलाकों में रहने वाले और ज्यादा धूम्रपान करने वालों में, एक शोध के अनुसार।

पूरे शरीर पर पड़ता असर

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लंबे समय तक बने रहना शरीर पर कई तरह से असर डालता है।

■ **कोशिकाओं की तेज क्षति** : फ्री रेडिकल्स की अधिकता, कोशिकाओं की झिल्लियों, प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे असमय बुढ़ापा, सूजन और कैंसर, हृदय रोग और अल्जाइमर रोग जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ सकता है।

■ **शरीर में सूजन बढ़ना** : ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अंदरूनी अंगों की सूजन ट्रिगर कर सकता है। लंबे समय तक चलने वाली सूजन ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में गठिया, इन्फ्लामेटरी बॉउल डिजीज और ल्यूपस जैसी स्थितियां से जूझ रहे लोगों की समस्या और बढ़ जाती है।

■ **रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी** : शरीर संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में लगातार थकान, भूख में कमी और यौन इच्छा में कमी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

■ **श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा** : विभिन्न शोधों में श्वसन संबंधी समस्या से जूझ रहे लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ देखा गया है।

■ **गड़बड़ा सकता है मस्तिष्क में प्रोटीन का संतुलन** : नेचर कम्युनिकेशंस में छपे अध्ययन के अनुसार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से न्यूरॉन्स की क्षमता कम होने लगती है, जिन्हें बढ़ती उम्र के प्रमुख संकेतों और याददाश्त में कमी के रूप में देखा जाता है।

जीवनशैली से जुड़ा तनाव कम करेंगे ये उपाय

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। किसी खास दवा या उपचार से इसे ठीक नहीं किया जा सकता। स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली व संतुलित खानपान से इसे काबू रखने में मदद मिलती है-

■ नियमित रूप से व्यायाम करें, शारीरिक सक्रियता से फ्री रेडिकल्स कम होते हैं और इंसुलिन से संवेदनशीलता में सुधार आता है।
■ रोजाना 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के दौरान तनावकारी हार्मोन कार्टिसोल व फ्री रेडिकल्स के स्तर में कमी आती है। इसका त्वचा पर भी अच्छा असर पड़ता है।
■ तले-भूने व प्रोसेस्ड चीजें कम खाएं।
■ धूम्रपान और शराब का सेवन न करें, इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स अधिक बनते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है।
■ प्रदूषकों और हानिकारक रसायनों के संपर्क से बचें।

हृदय और मधुमेह रोगी दें खास ध्यान

हृदय रोग और डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसी 'साइलेंट विलेन' से कम नहीं है। डायबिटीज में खून में शर्करा बढ़ने से शरीर में फ्री रेडिकल्स का हमला तेज हो जाता है, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को और ज्यादा कमजोर कर देता है। वहीं, हृदय रोगियों के मामले में यह तनाव धमनियों के अंदरूनी हिस्से को सख्त बना देता है और कोलेस्ट्रॉल को खतरनाक 'प्लाक' में बदल देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

खानपान सुधारने पर रहे जोर

शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक ग्लूटाथियोन है, जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर सकता है और डीएनए को नुकसान से बचाता है। ग्रीन टी, लीन प्रोटीन, मछली, क्रूसिफेरस सब्जियां और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थ ग्लूटाथियोन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन अधिक करें- ■ खट्टे रसीले रंग-बिरंगे फल ■ हरी पत्तेदार सब्जियां ■ सूखे मेवे बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि बीज ■ अंडे व कम वसा वाला मांस ■ मछली, केकड़े और झींगे ■ गाजर, टमाटर, ब्रोकली, पत्तागोभी, फूलगोभी।

हमारे विशेषज्ञ:
डॉ. आदित्य गुप्ता, डायरेक्टर, न्यूरो सर्जरी, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम
डॉ. जया सुकुल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हेडस्पेस हीलिंग, नोएडा।

देखभाल

ऐसे आहार जो गर्मी की मार से बचाएंगे

गर्मी के दिनों में खूब पानी पीना और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बने रहना बेहद जरूरी है। हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट परिधि गर्ग के अनुसार, 'गर्मियों में हमारा शरीर लगातार तापमान काबू करने, पसीना निकालने व अंदरूनी संतुलन बनाए रखने में लगा रहता है। केवल पानी नहीं, शरीर की ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए शरीर का तरल व पोषक तत्वों को ग्रहण करना जरूरी है।

नारियल पानी

यह बेहद प्रभावी पेय है। जब पसीना आता है, तो सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकलते हैं। नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है।

खीरा व ककड़ी

यह सब्जियां लगभग 96% पानी से बनी होती है, इसलिए गर्मियों में रायता और सलाद में इसका उपयोग आम है। इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में तरल संतुलन बनाए रखते हैं।

छाछ व लस्सी

जीरा और अदरक के साथ बनाई गई नमकीन छाछ गर्मियों का सबसे बेहतरीन पेय हो सकती है। यह शरीर को हाइड्रेट करती है, पसीने से खोए नमक की भरपाई करती है और इसमें मौजूद (प्रोबायोटिक्स) पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।

तरबूज

यह 92% पानी से भरपूर होता है और प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। तरबूज में लाइकोपीन होता है, जो गर्मी से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इससे शरीर को तुरंत ठंडक का एहसास होता है।

लौकी व तोरई

दोनों सब्जियां पानी से भरपूर, हल्की व सुपाच्य होती है। साथ ही इसमें विटामिन सी व पोटैशियम भी होता है। तोरई में लगभग 90% पानी होता है। तोरई में मैग्नीशियम होता है, जो डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली मांसपेशियों की ऐंठन रोकने में मदद मिलती है।

नीबू-पुदीना पानी

एक गिलास नीबू-पुदीना पानी में नमक और चीनी मिलाने पर यह घर का बना ओआरएस जैसा काम करता है। नीबू, विटामिन सी और पोटैशियम देता है, नमक सोडियम की पूर्ति करता है, चीनी ऊर्जा देती है और पुदीना शरीर में ठंडक का एहसास पैदा करता है।

सब्जा के बीज

इन बीजों को 15 मिनट पानी में भिगोने पर ये फूल जाते हैं। यह वास्तव में घुलनशील फाइबर होता है, जो शरीर में पानी को लंबे समय तक बनाए रखता है और धीरे-धीरे हाइड्रेशन प्रदान करता है।

कच्चा आम

गर्मी से बचाव के लिए कच्चा आम सबसे पुराने और प्रभावी उपायों से एक है। यह विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। काला नमक व गुड़ से बना आम पन्ना शरीर को ऊर्जा देता है और भीतर से ठंडक का एहसास करता है।

हाथ और बाजुओं के सुन्नपन का सही कारण जानें

सवाल-जवाब

डॉ. पुलिन गुप्ता
प्रोफेसर (मेडिसिन) राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली

■ **सवाल : मेरी मां का साल भर से इलाज चल रहा है। दवा का असर ही नहीं हो रहा। उनके हाथ व बाजू सुन्न हो जाते हैं। पूरे शरीर में जलन और करेंट जैसी झनझनाहट बनी रहती है। नहाते समय सुई चुभने का एहसास होता है। हम किन्हें दिखाएं?**

जवाब: हाथ और बाजुओं के सुन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस की स्थिति में डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। गर्दन झुकाने या हिलाने पर दर्द और झनझनाहट बढ़ सकती है। पर, इसके लक्षण हर किसी में गंभीर नहीं होते। यदि नहाते समय सुई चुभने जैसा एहसास हो, तो यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस का लक्षण हो सकता है। इसके लिए तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तीसरी स्थिति, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की है, जिसमें मधुमेह होने पर पैर की नसें कमजोर हो जाती हैं। तीनों ही समस्याओं का इलाज संभव है। डॉक्टर रंगीन एक्स-रे और एमआरई करा सकते हैं।

■ **सवाल : मेरी पत्नी की उम्र 45 वर्ष है। बीते साल अपेंडिक्स हटाया गया था। तब से पेट की समस्याएं रहने लगी हैं। डॉक्टर का कहना था कि अपेंडिक्स हटाने से फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करें?**

अपेंडिक्स हटाने से पेट की अन्य समस्याएं नहीं होतीं। यह एक अंग है, जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। इस हिस्से में सूजन आने पर, इलाज न कराने से यह फट सकता है और संक्रमण शरीर में फैल जाता है, इसलिए इसे हटाना जरूरी हो जाता है। पेट की समस्याओं के अन्य कारण हो सकते हैं। पेट में संक्रमण, छोटी आंत में सूजन या ऑपरेशन के बाद आंतों का आपस में चिपक जाना इसके कारण हो सकते हैं। आप सर्जन से दोबारा सलाह लें। अल्ट्रासाउंड के जरिये पित्त की थैली में पथरी या गैस्ट्राइटिस की जांच करवाएं। दूसरी तरफ, लैप्रोस्कोपी के माध्यम से चिपकी हुई आंतों को खोला जा सकता है।

■ **सवाल : मेरी उम्र 50 साल है। ऑफिस में देर तक बैठकर काम करना पड़ता है। हालांकि, मैं व्यायाम भी करता हूं। क्या यह पथरी का दर्द हो सकता है? कमर दर्द व पथरी के दर्द में क्या अंतर है?**

कमर दर्द और किडनी स्टोन के दर्द में कुछ अंतर स्पष्ट होते हैं। किडनी स्टोन का दर्द 'कोलिकी पेन' कहलाता है, जो बहुत ही तेज होता है और इसमें मरीज को उल्टी, पसीना आना और पेशाब आने में दिक्कत व जलन महसूस होती है। इसके विपरीत, लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठने के कारण होने वाला डिस्क का दर्द हल्का और लगातार बना रहने वाला होता है। ऑफिस में लंबे समय तक बैठने वाले लोगों को सपोर्ट बेल्ट लगानी चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में सीट से उठकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। हालांकि, कमर दर्द के अन्य कारण जैसे पेंक्रियाटाइटिस या गॉलब्लेडर स्टोन भी हो सकते हैं, इसलिए विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराना ही सबसे उचित विकल्प है।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-
तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, 201301

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सम्मान मिलेगा।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

मिथुन : नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

सिंह : मन अशांत हो सकता है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। खर्च बढ़ेंगे।

कन्या : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

तुला : मन में निराशा व असंतोष से बचें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ बढ़ेगा।

वृश्चिक : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के योग हैं।

धनु : वाणी में मधुरता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आय के साधन बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मकर : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त काम मिल सकता है।

कुंभ : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध व वाद-विवाद से बचें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी धार्मिक स्थान पर भी जाना हो सकता है।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में सुधार हो सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

08 मई, शुक्रवार, **शक संवत्** : 18 वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 25 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 20 जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत्**: प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि दोपहर 12.22 बजे तक पश्चात सप्तमी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 09.20 बजे तक पश्चात श्रवण नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.22 मिनट से रात्रि 01.13 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि घर में कांटें वाले पौधे जैसे कैक्टस आदि क्यों नहीं लगाने चाहिए?
-अतिशय शर्मा, दिल्ली

■ घर में प्रेम, सौम्यता व समृद्धि का निवास होना चाहिए। कैक्टस या अन्य कांटे वाले पौधे लगाना, इस मूल भावना के विपरीत कार्य करना है। चूंकि, कांटे का स्वभाव होता है- चुभना, दूरी बनाना व काटना, तो जैसा भाव वैसा ही परिणाम होता है। जब घर के अंदर या आसपास ऐसे पौधे होते हैं, तो कटुता और विवाद की ऊर्जा बढ़ती है। इनका मूल स्थान रेगिस्तान है। जहां हरियाली नहीं होती, न जल होता, वहां समृद्धि स्थायी नहीं रहती, इसलिए कैक्टस घर में सूखेपन एवं अभाव का प्रतीक बनते हैं।

वर्ग पहेली : 8322

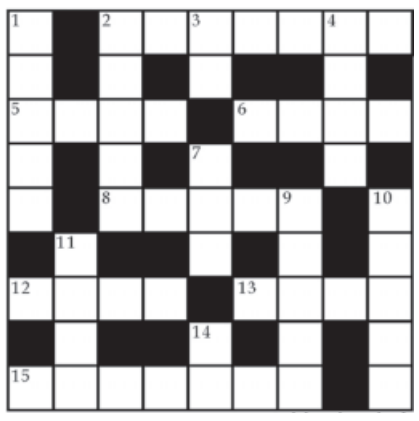

बाएं से दाएं
2. कहीं का नहीं; बेकार; निकम्मा; धोबी का कुत्ता (2,1,1,2,1)
5. तकलीफ देने वाला; दर्द देने वाला; पीड़ादायक (4)
6. पत्रवाहक; डाकिया (4)
8. जिसमें मसाला पड़ा हुआ हो; चटपटा; चरपरा; सुवासित; स्वादिष्ट (5)
12. आलिंगन कराना; गले लगाना; लिपटाना; सटाना; जोड़ना; लगाना (4)
13. उत्तेजित होना; क्रुद्ध होना; चौंकना; बिदकना; तेजी से जल उठना (4)
15. अर्चना करना; पूजा-पाठ करना (2,2,3)

ऊपर से नीचे
1. मदद करने वाला; दूसरों की सहायता करने वाला; सहायक (5)
2. कथानक; कालक्रम; घटनाचक्र; घटनाओं का सिलसिला (5)
3. कर्ण; श्रवणेंद्री (2)
4. हटाना; टालना; धता बताना; चलता करना (4)
7. जलपान; नाश्ता; पाथेय (3)
9. घुटवाना; पिसवाना; रगड़ा लगवाना (5)
10. औषध; दवा; बीमारी दूर करने वाला; रोगशामक; रोगहर (5)
11. गुप्त रूप से; मौन रह कर (4)
14. कीड़ों-मकोड़ों का लंबा पतला अंग; बिच्छू, भिड़, मधुमक्खी आदि कीड़ों का जहरीला कांटा (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8321

1 स		2 स	म्मा	3 न	क	4 र	5 ना	
रा		ह		का		6 सा	ग	र
7 ह	व	न	क	र	ना		रि	
ना		क		ना		8 न	क	ली
	9 धा	र	क		10 स	म	ता	
11 दी	वा	ना		12 सा		न		13 अ
	बो		14 स	मा	प्त	क	र	ना
15 मि	ल	16 ना		जि		र		द
	17 ना	रा	ज	क	र	ना		र

सुडोकू : 8304

*मध्यम

				7				
		6	8			2		
	1	7			5	4	3	
		2	6		7		8	
6								4
	9		5		4	3		
	5	4	3			7	6	
		9			2	8		
				8				

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8303

8	3	5	6	9	1	7	2	4
7	1	4	5	2	3	9	6	8
6	2	9	8	7	4	3	5	1
5	6	3	9	1	8	4	7	2
2	4	1	3	5	7	8	9	6
9	8	7	2	4	6	5	1	3
3	5	6	1	8	9	2	4	7
4	9	8	7	6	2	1	3	5
1	7	2	4	3	5	6	8	9

प्रेरणा

आपकी तुलना सिर्फ उस व्यक्ति से होनी चाहिए, जो आप कल थे। **-जॉर्डन पीटरसन**

संपादकीय

अमेरिका और ईरान अब नई मिसाल कायम करें

सुकरात ने कहा था कि अगर अज्ञानता न रहे तो मनुष्य की प्रवृत्ति आदतन शुभोन्मुख होती है। हाल में उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों के अध्ययन से पता चला है कि खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अति-संवर्धित आयुधों को बड़ी क्षति हुई है, लेकिन ट्रम्प सरकार ने यह जानकारी छिपा रखी थी। कुल 228 ढांचों और उपकरणों की क्षति में थाड, अवाक्स और पैट्रियट जैसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम भी थे और हैंगेर्स भी। ईरानी हमले सटीक और टार्गेटेड थे। यह भी पता चला कि युद्ध के दौरान ट्रम्प ने सैटेलाइट्स संस्थाओं को ये तस्वीरें सार्वजनिक न करने की ताकीद की थी। उधर ईरान की माली हालत खस्ता हो चुकी है और बीजिंग में ईरान के विदेश मंत्री की चीनी नेताओं से हुई वार्ता में भी यही दबाव था कि अब मूल हितों की तिलांजलि दिए बिना सहमति बना लेनी चाहिए। ट्रम्प भी जानते हैं युद्ध में उनके पास अब एक ही विकल्प है- भारी सैनिक बल और हथियारों के साथ ईरान में तबाही यानी धन-जन हानि। ईरान इसे आसानी से नहीं सफल होने देगा और अमेरिकी जनता इसकी कीमत वहन करने को तैयार नहीं है। ट्रम्प का भविष्य मिड-टर्म इलेक्शन काफी हद तक तय करेगा। जाहिर है कि दोनों युद्धरत देश समझौते के बाद अपने को विजेता घोषित करेंगे। लेकिन याद रखें कि हर युद्ध के बाद हुक्मरानों का भविष्य भी जनता के आशीर्वाद पर ही टिका होता है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

राम-काज में आतुर और राज-काज में तत्पर हो जाएं

देश-सेवा में तत्पर रहें और देव-सेवा में आतुर रहें। वैसे तो विवेकानंद जी कहते हैं, देश ही पहला देव है। हम भारत को और परमात्मा के जिस स्वरूप को हम पूजते हों- बराबर रखें। इन दो शब्दों पर ध्यान दें- तत्पर होना और आतुर रहना। भाषा की दृष्टि से तो तत्पर कटिबद्ध व्यक्ति है। जो सकारात्मक होकर अनुशासित भाव से काम करे, वो तत्पर। आतुर में एक उतावलापन है, परिणाम प्राप्त होने की बेचैनी है, कहीं-कहीं अशांति है। लेकिन तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की सातवीं चौपाई में लिखा है- विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये आतुर शब्द हनुमान जी पर जमता है क्या? असल में राम काज शब्द को समझेंगे तो आतुर के अर्थ बदल जाएंगे। ईश्वर का काम करने में तत्पर से अधिक आतुर रहिए और देश का काम करने में आतुर से अधिक तत्पर रहिए। परमात्मा को जीवन में लाना हो तो उतावलापन करने में दिक्कत नहीं। व्याकुलता ही तो हमारे अधूरेपन में ईश्वर को भरेगी।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विशेष • सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ

सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर जीवंत

आस्था

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

जय सोमनाथ!

2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।'

दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। पं. नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बनाया।

जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको भक्ति का ही अनुभव नहीं होगा, उस सभ्यतागत चेतना की धड़कन भी सुनाई देगी, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई।

मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अटल जी और गृहमंत्री आडवाणी जी की मौजूदगी ने इसे और गरिमापूर्ण बना दिया।

मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का ही अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा।

ऑपरेशन सिंदूर • शक्ति का अनुशासित प्रयोग

प्रहार करने की क्षमता और फिर रुक जाने का विवेक भी

समरनीति

सैयद अता हसनैन
बिहार के राज्यपाल और कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष बाद अगर हम उससे मिलने वाली सबसे बड़ी सीख के बारे में सोचें, तो न तो वह हमले की सटीकता है और न ही उसके क्रियान्वयन की गति, बल्कि वह वो रणनीतिक स्पष्टता है, जो इसका आधार बनी। भारत ने यह दिखाया था कि प्रभावी होने के लिए शक्ति-प्रयोग का अधिकतम-वादी होना आवश्यक नहीं है। ऐसे दौर में, जब देश अकसर लंबे चलने वाले संघर्षों में उलझ जाते हैं, भारत ने एक अलग मार्ग चुना। यह एक संयमित, सुनियोजित और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित मार्ग था। इसी ने उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को आकार दिया है।

दुनिया भर में हालिया संघर्षों ने एक कठोर सत्य उजागर किया है; आज युद्ध शुरू करना तो आसान है, लेकिन उन्हें समाप्त करना कहीं ज्यादा मुश्किल। निर्णायक जीत की अवधारणा लगातार दुर्लभ होती जा रही है। टेक्नोलॉजी ने अप्रत्याशित तरीकों से शक्ति-संतुलन को समतल कर दिया है। छोटे या अपेक्षाकृत कम विकसित देश भी अब बड़ी ताकतों को लंबे खिंचने वाले संघर्षों में फंसा सकते हैं, जो उनके संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों को क्षीण करते हैं। परिणामस्वरूप एक ऐसी रणनीतिक अस्पष्टता उभरती है, जिसमें लागत अत्यधिक होती है, उपलब्धियां सीमित रहती हैं और अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं होती।

ऐसे में भारत का दृष्टिकोण इस समझ को प्रतिबिम्बित करता है कि ताकत की आजमाइश का उद्देश्य केवल शक्ति-प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय ढांचे के भीतर विशिष्ट और सीमित उद्देश्यों की प्राप्ति है। ऑपरेशन सिंदूर इसी तर्क का प्रतीक था। इसका उद्देश्य न तो किसी के भूगोल को बदलना था और न ही अधिकतम-वादी लक्ष्यों का पीछा करना; इसका उद्देश्य रणनीतिक स्थिरता को बनाए रखते हुए एक स्पष्ट और विश्वसनीय संदेश देना था। ऐसा करके भारत ने उस सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया, जो समकालीन भू-राजनीति में लगातार दुर्लभ होता जा रहा है। और वह है : शक्ति का अनुशासित प्रयोग।

इस अनुशासन को अकसर सतर्कता से उपजे संयम के रूप में गलत समझ लिया जाता है। वास्तव में, यह आत्मविश्वास से उपजा संयम है। भारत के नेतृत्व ने यह प्रदर्शित किया कि उसके पास न केवल प्रहार करने की क्षमता और इच्छाशक्ति है, बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद रुक जाने का विवेक भी है। आक्रामकता और संयम के बीच यह संतुलन सहजता से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए राजनीतिक उद्देश्य की स्पष्टता, पेशेवर सैन्य क्षमता और ऐसी संस्थागत संस्कृति की आवश्यकता होती है, जो परिणामों को महत्व देती हो।

साथ ही, भारत का दृष्टिकोण अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता पर आधारित है। जीवन की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन सर्वोपरि बने हुए हैं। इस आवश्यकता का पालन दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों से पृथक होकर नहीं किया जाता। बल्कि इसे एक व्यापक रणनीतिक दृष्टि में समाहित किया गया है। यह ऐसी दृष्टि है, जो स्वीकार करती है कि स्थायी सुरक्षा आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और वैश्विक विश्वसनीयता से अलग नहीं है। इस दृष्टिकोण के कुछ और प्रमुख तत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जैसे उद्देश्य की स्पष्टता, जिसमें शक्ति का प्रयोग परिभाषित और प्राप्त करने योग्य परिणामों के लिए किया जाता है- न कि अनिश्चित लक्ष्यों के लिए। नियंत्रित एस्केलेशन, जिसमें निर्णायक कार्रवाई की क्षमता होती है। साधनों का समन्वय, जिसके तहत राजनीतिक, सैन्य, कूटनीतिक और सूचनात्मक उपकरण परस्पर सामंजस्य में कार्य करते हैं। और दीर्घकालिक हितों की प्रधानता, जिसमें तात्कालिक प्रतिक्रियाएं राष्ट्रीय हित के अनुरूप होती हैं।

ऐसे दौर में, जब देश अकसर लंबे चलने वाले संघर्षों में उलझ जाते हैं, भारत ने एक अलग मार्ग चुना। यह एक संयमित, सुनियोजित और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित मार्ग था। इसने उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को आकार दिया है।

यह फ्रैमवर्क भारत की व्यापक आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना निरंतर आर्थिक गति की मांग करती है। व्यापक संघर्ष उन परिस्थितियों को बाधित कर देता है, जो विकास को संभव बनाती हैं : निवेशकों का विश्वास, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक एकता। इसलिए भारत का रणनीतिक संयम उसकी सीमा नहीं, बल्कि उसकी सावधानीपूर्वक चुनी गई प्राथमिकता है। यह इस समझ को भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड सैन्य क्षमता ही नहीं, आर्थिक सुदृढ़ता में भी निहित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक — ऊबर : अमेरिकी मल्टीनेशनल राइड हेलिंग कंपनी

चार साल में 1.4 लाख करोड़ का घाटा हुआ था, ऊबर अब सबसे बड़ा राइड-बुकिंग एप

ऊबर दुनिया का नंबर एक राइड बुकिंग एप है। करीब 70 देशों में यह अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें से 63 में ये शीर्ष पर है। भारत में भी यह राइड के मामले में दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर रैपिडो है।

दुनियाभर में हर सेकंड इसकी करीब 300 राइड बुक होती हैं, लेकिन 2017 में एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका में डिलीट ऊबर कैम्पेन चला और कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने ऊबर एप को डिलीट कर दिया। दरअसल अमेरिका में कुछ प्रवासियों के खिलाफ बैन लगाया गया था। इसके विरोध में न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी, लेकिन ऊबर ने टैक्सी सेवाएं चालू रखीं। लोगों को लगा कि ऊबर देश की जगह मुनाफे को तरजीह दे रहा है। इससे लोग नाराज हो गए और #DeleteUber अभियान चल पड़ा। 2017 में कानूनी पचड़ों में फंसने से लेकर 2020 में कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन तक ऊबर को करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे कंपनी संकट में आ गई। को-फाउंडर ट्रेविस कलानिक को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि लीडरशिप और वर्क कल्चर में बदलाव, नियमों में पारदर्शिता जैसे कदम उठाकर कंपनी वापस पटरी पर लौट आई।

सबक... आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। यह सिर्फ नैतिक नहीं, व्यावहारिक जरूरत है।

40% मार्केट शेयर के साथ भारत में दूसरे नंबर पर है ऊबर

20 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ

97 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स और कूरियर पार्टनर जुड़े हैं ऊबर से

14 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है ऊबर वर्तमान में

• वर्तमान स्थिति

ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और 'सुपर एप' है ऊबर

वर्तमान में ऊबर केवल राइड-हेलिंग एप नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लॉजिस्टक और डिलीवरी 'सुपर एप' बन चुका है। कैब राइड के अलावा ऊबर इस समय माल ढुलाई के लिए 'ऊबर फ्रेट', कॉर्पोरेट के लिए 'ऊबर फॉर बिजनेस' और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 'ऊबर हेल्थ' जैसी सेवाएं भी चला रहा है।

ऊबर एप दुनियाभर के 10 हजार से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। 40 प्रतिशत यूजर्स इसकी मल्टीपल सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वर्तमान में यह करीब 14 लाख करोड़ रुपए मूल्य की कंपनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी की अधिकांश सेवाएं मुनाफे में हैं।

यूं संकट में फंसी थी...

- **खराब वर्क कल्चर:** 2017 में ऊबर की पूर्व इंजीनियर सुसान फाउलर ने गंभीर भेदभाव की शिकायत वाला ब्लॉग लिखा। इससे वैश्विक स्तर पर कंपनी की छवि एक महिला-विरोधी बन गई।
- **ग्रेबॉल और धोखाधड़ी :** ऊबर 'ग्रेबॉल' नामक एक गोपनीय सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था। इससे शहरों में अवैध सेवाएं चलाईं। कंपनी इससे गंभीर कानूनी संकट में फंस गई। लोगों का विश्वास घटा।
- **लीडरशिप की मनमानी:** ब्लूमबर्ग ने 2017 में एक वीडियो जारी किया, जिसमें तत्कालीन सीईओ ट्रैविस कंपनी के ड्राइवर से गाली-गलौज करते दिखे थे।
- **आईपी चोरी :** गूगल की सेल्फ-ड्राइविंग यूनिट 'वेमो' ने ऊबर पर मुकदमा दायर किया। आरोप था कि गूगल से सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट के 14,000 अत्यंत गोपनीय डिजाइन के दस्तावेज चुराए गए।

इस तरह की वापसी...

- **दारा खोसरोशाही की लीडरशिप :** 2017 में एक्सपीडिया के पूर्व प्रमुख दारा खोसरोशाही ने सीईओ का पद संभाला। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। 'हम सही काम करते हैं' का नारा दिया।
- **कड़ा बदलाव :** पुराने भेदभाव वाली संस्कृति को खत्म करने के लिए सख्त नीतियां लागू की गईं। लापरवाही करने पर पूरी एचआर टीम को बदल दिया। नए और भरोसेमंद लोगों की टीम बनाई।
- **रणनीतिक अधिग्रहण :** 2.6 बिलियन डॉलर में 'पोस्टमेट्स' व शराब डिलीवरी एप 'ड्रिज्ली' का अधिग्रहण किया। डिलीवरी क्षेत्र में भी मजबूत हुई।
- **नुकसान वाले व्यवसाय बंद किए :** रूस, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया में घाटे वाले व्यवसाय बेच दिए। ऊबर के महंगे और विवादित 'सेल्फ-ड्राइविंग' और 'फ्लाइंग टैक्सी' प्रोजेक्ट्स को भी बेच दिया।

शुरुआत : टैक्सी न मिलने की परेशानी से जन्मा ऊबर का विचार

2008 की सर्दियों में पेरिस में लेवेब कॉन्फ्रेंस के दौरान दो उद्यमी दोस्त ट्रैविस कलानिक और गैरेट कैंप को टैक्सी नहीं मिल रही थी। इसी परेशानी से उनके दिमाग में आइडिया आया कि 'कैसा हो कि केवल एक बटन दबाने से कोई गाड़ी मिल जाए'। इस तरह 2009 में सैन फ्रांसिस्को में ऊबर-कैब के रूप में कंपनी की शुरुआत हुई।

नए कामों में कर रही निवेश : रोबोटैक्सी, डिजिटल विज्ञापन

वर्तमान में कंपनी भविष्य की तकनीक पर भी दांव लगा रही है। ड्राइवरलेस कारों के लिए गूगल की कंपनी 'वेमो' के साथ बड़ी साझेदारी की है। कई अमेरिकी शहरों में एप के जरिए सीधे 'रोबोटैक्सी' सेवा शुरू की है। इसके अलावा डिजिटल विज्ञापन और ग्रॉसरी/लोकल डिलीवरी कंपनी के तेजी से बढ़ते नए क्षेत्रों में शामिल हैं।

ऐसे पड़ा नाम : ऊबर जर्मन शब्द Uber से प्रेरित माना जाता है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, बेहतर या ऊपर। पहले इसका नाम UberCab था। बाद में कैब हटाया।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : अमेरिकी बाजार में 'लिफ्ट', भारत में रैपिडो, ओला से कड़ी टक्कर मिलती है। यूरोप और अफ्रीका में 'बोल्ट' और चीन में 'दीदी' प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं।

पीपुल भास्कर — लक्ष्मी मित्तल, भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति

कभी जमीन पर सोए मित्तल, 15 साल में 47 कंपनियां खरीदीं, महंगी पेंटिंग्स का भी शौक

चर्चा में क्यों : अदार पूनावाला के साथ मिलकर आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स और उसकी फ्रेंचाइजी खरीदी हैं, जिसमें 75% हिस्सेदारी है।

27 जनवरी 2006, लक्ष्मी मित्तल ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी 'आर्सेलर' को खरीदने के लिए एक बोली लगाई। चूंकि कंपनी एक तरह से यूरोप का गौरव थी, तो फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्पेन की सरकारों तक ने इसका जोरदार विरोध किया। लक्ष्मी मित्तल के बोली लगाने से खुद को अपमानित महसूस कर रहे आर्सेलर के तत्कालीन सीईओ 'गाई डोले' ने मित्तल के प्रस्ताव को 'मंकी मनी' तक कह डाला। यह एक तरह से उनके खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी थी। इस टिप्पणी से पूरा यूरोप घिर गया। हालांकि मित्तल पीछे नहीं हटे। उन्होंने बोली को इतना बड़ा कर दिया कि शेयर होल्डर्स तैयार हो गए और मैनेजमेंट को हारना पड़ा। मित्तल की इस डील ने उन्हें दुनिया का स्टील किंग बना दिया।

'लक्ष्मी मित्तल ने सिर्फ स्टील प्लांट नहीं खरीदे, बल्कि इस उद्योग का भविष्य खरीदा है'
-टिम गार्टन ऐश, चर्चित लेखक

दुनियाभर में व्यापार करने के बावजूद लक्ष्मी मित्तल पूरी तरह शाकाहारी हैं। विदेश यात्राओं के दौरान भी इसका कड़ाई से पालन करते हैं। उनके बेटे आदित्य एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी प्लांट में कोई मशीन ब्रेकडाउन होती थी तो वे आधी रात को भी खाना छोड़कर प्लांट पर पहुंच जाते थे। यह आदत आज भी उनके रूटीन का हिस्सा है। उनकी कंपनियां अलग-अलग टाइम जोन में होने के कारण रूटीन काफी थकाऊ होता है। भारी वर्कलोड और तनाव को झेलने के लिए वे नियमित रूप से योग करते हैं। तैराकी उनके वर्कआउट का हिस्सा है। उन्हें दुनियाभर की बेहतरीन कलाकृतियों और पेंटिंग्स को इकट्ठा करने का शौक है।

उद्योग का एकीकरण होना ही चाहिए। एक बिखरा हुआ उद्योग हमेशा कमजोर होता है। अगर हमें अपने भाग्य का स्वामी बनना है, तो इतना बड़ा होना होगा कि हम बाजार को प्रभावित कर सकें।

जन्म : 15 जून 1950, राजस्थान।

शिक्षा : सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता से स्नातक।

परिवार : पत्नी- ऊषा मित्तल, बच्चे- एक बेटा और बेटी।

संपत्ति : 2.83 लाख करोड़ रु (फोर्ब्स के अनुसार)

• शुरुआत

25 लोगों का परिवार, जमीन पर सोते थे

राजस्थान के सादुलपुर गांव में जन्में लक्ष्मी मित्तल के घर पर बिजली तक नहीं थी। करीब 25 लोगों का संयुक्त परिवार था, जिसमें दादा, दादी, चाचा, ताऊ और उनके बच्चे रहते थे। कई बार जमीन पर सोना पड़ता था। जब लक्ष्मी मित्तल 2 साल के थे तब पिता मोहनलाल कोलकाता चले गए। यहां स्टील का छोटा काम शुरू किया।

• विवाह

क्लब में मुलाकात हुई, लव लेटर भी मिला था

लक्ष्मी मित्तल की शादी 1971 में ऊषा डालमिया से हुई थी। यह कॉर्पोरेट जगत की मशहूर अरेंज-कम-लव मैरिज में से एक है। दोनों की मुलाकात कोलकाता के एक क्लब में चाय पर हुई थी जब ऊषा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रही थीं। पहली मुलाकात के बाद एक फोन कॉल हुई जो करीब 2 घंटे चली। ऊषा ने लव लेटर भी लिखा।

• करियर

एक मिल से स्टील किंग तक का सफर

लक्ष्मी मित्तल ने 1970-75 तक पिता की स्टील मिल में काम किया। 1976 में इंडोनेशिया में स्टील मिल लगाई। यहीं से उन्होंने एक नया तरीका खोजा। वे दुनियाभर में घाटे की सरकारी मिलों को खरीदते और उन्हें मुनाफे में ले आते। 15 वर्षों में करीब 47 कंपनियां खरीदीं। 2006 में आर्सेलर के टेकओवर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई।

खास : हार्वर्ड और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं को अरबों रु. दान किए

- 2004 में उन्होंने बेटी वनिशा की शादी पेरिस में की थी। करीब 514 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तब यह दुनिया की सबसे महंगी शादी थी।
- 2004 में लंदन के केंसिंगटन पैलेस गार्डन में करीब 700 करोड़ में घर खरीदा था। उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा घर था।

उपलब्धि : 2008 में भारत सरकार ने दिया पद्म विभूषण

- टाइम मैगजीन ने 2007 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था।
- 2006 में फाइनेंशियल टाइम्स ने लक्ष्मी मित्तल को 'पर्सन ऑफ द ईयर' चुना था।
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) तकनीक को दुनियाभर में बढ़ाया है।

रोचक : पहले सरनेम 'Mital' था बाद में उसे 'Mittal' किया

- लंदन के 'सरे' में 340 एकड़ में 'जीरो-कार्बन' और इकोफ्रैंडली हवेली बनवाई थी। घर पूरी तरह सोलर और बायोमास एनर्जी से चलता है।
- 2000 के ओलिंपिक में भारत को एक मेडल मिलने से निराश मित्तल ने 2005 में करीब 40 करोड़ रु. से 'मित्तल चैम्पियन ट्रस्ट' बनाया था।

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ

नई दिल्ली, शुक्रवार 8 मई , 2026

बिजनेस ब्रीफ

स्काईरूट यूनिकॉर्न बना, 564 करोड़ रुपए जुटाए

बेंगलुरु| स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ₹564 करोड़ की फंडिंग जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है। इस निवेश के बाद कंपनी का वैल्युएशन 1.1 अरब डॉलर यानी ₹10,351 करोड़ हो गया है। यह प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि है। कंपनी रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी पर काम करती है और तेजी से वैश्विक बाजार में जगह बना रही है।

इमामी ने इंकनट डिजिटल में 60% हिस्सेदारी खरीदी

मुंबई| इमामी ने ब्यूटी, स्किनकेयर स्टार्टअप इंकनट डिजिटल में 60% हिस्सेदारी ₹321 करोड़ में खरीदी है। वेडिक्स व स्किनक्राफ्ट की पैरेंट कंपनी से इस डील के साथ इमामी डिजिटल ब्यूटी सेगमेंट में पकड़ मजबूत करेगी। इंकनट पर्सनलाइज्ड स्किनकेयर और हेयरकेयर ब्रांड्स चलाती है। इसके अधिग्रहण से इमामी की ऑनलाइन पहुंच बढ़ेगी।

एपल ₹100 करोड़ से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी

नई दिल्ली| एपल ने भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी 6 ग्रीन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, जो सोलर एनर्जी जैसे अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत में प्रदूषण कम करना और सप्लाई चेन को स्वच्छ बनाना है।

फेयरफैक्स ने IIFL में ₹2,000 करोड़ लगाया

मुंबई| फेयरफैक्स इंडिया ने गुरुवार को आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज में ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाने की घोषणा की। यह निवेश कंपनी का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस मजबूत करेगा। फेयरफैक्स का यह कदम भारत में उसकी लंबी अवधि की रणनीति दर्शाता है। आईआईएफएल कैपिटल ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है।

रॉयल एनफील्ड लगा रही 2,200 करोड़ का प्लांट

चेन्नई| बुलेट बाइक बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने आंध्र प्रदेश में ₹2,200 करोड़ की लागत से नया कारखाना लगाने की घोषणा की है। यह तमिलनाडु के बाहर कंपनी का पहला प्लांट होगा। इस फैसले से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। कंपनी वैश्विक बाजारों में भी विस्तार कर रही है। नए मॉडल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए बड़ा निवेश कर रही है।

टाटा • होल्डिंग कंपनी की लिस्टिंग पर ₹17 लाख करोड़ के कॉरपोरेट ग्रुप में मतभेद के संकेत

नोएल की 'ना', पर दो ट्रस्टी चाहते हैं टाटा सन्स का IPO, आज ला सकते हैं प्रस्ताव

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश के सबसे बड़े और पुराने कॉरपोरेट ग्रुप में से एक टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर समूह के शीर्ष नेतृत्व के बीच कथित रूप से मतभेद गहरा गए हैं। इस मामले में एक तरफ ट्रस्टी हैं, दूसरी तरफ नोएल टाटा।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स के छह ट्रस्टियों में से दो प्रमुख ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह 8 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग का प्रस्ताव रखने की तैयारी में हैं। उनका तर्क है कि लिस्टिंग से समूह में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ेगा। दूसरी तरफ, ट्रस्ट के मुखिया नोएल टाटा कंपनी को प्राइवेट रखने पर अड़े हुए हैं। विवाद इतना गहरा है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल का फैसला तक टल गया है। नोएल टाटा चंद्रशेखरन से यह गारंटी चाहते हैं कि लिस्टिंग नहीं होगी। चंद्रशेखरन ने कथित तौर पर ऐसी गारंटी देने से मना कर दिया है। दरअसल टाटा समूह में ज्यादातर फैसले ढेर सारे परोपकारी ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें शेयर बाजार के कायदे-कानून पसंद नहीं आते।

टाटा सन्स की लिस्टिंग की संभावना कितनी...

पहलू	स्थिति
नई गाइडलाइन:	1 जुलाई 2025 से लागू, टाटा सन्स अपर-लेयर एनबीएफसी घोषित
पुराना रास्ता बंद:	2022 में कर्ज पुनर्गठन का जो रास्ता निकाला था, वह अब उपलब्ध नहीं
रिजर्व बैंक का रुख:	आरबीआई ने अनौपचारिक रूप से स्पष्ट किया- टाटा को छूट नहीं मिलेगी
सरकार की भूमिका:	रिजर्व बैंक ने अपनी राय सरकार को भेजी, अंतिम फैसला वहीं से आएगा
ट्रस्टियों का रुख:	दो प्रमुख ट्रस्टी लिस्टिंग के पक्ष में, पुरानी एकजुटता कथित तौर पर टूटी

- हालात संकेत दे रहे हैं कि लिस्टिंग की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा है
- रिजर्व बैंक अब टाटा सन्स की लिस्टिंग के मामले में किसी अपवाद के मूड में नहीं नजर आ रहा
- सरकार यदि आरबीआई के रुख से सहमत हुई, तो टाटा सन्स को आईपीओ लाना पड़ सकता है

नोएल का रुख श्रीनिवासन, सिंह से अलग

लिस्टिंग हुई तो 16.9 लाख करोड़ के ग्रुप में आम लोग निवेश कर पाएंगे

1. शापूरजी पालोनजी को सबसे बड़ा फायदा: टाटा सन्स में 18.4% हिस्सेदारी वाले शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने ये शेयर गिरवी रखकर कर्ज उठाया है। परिवार की कुल संपत्ति (₹3 लाख करोड़) का करीब 75% टाटा सन्स में फंसा है।

2. टाटा ट्रस्ट पर असर: दो-तिहाई हिस्सेदारी वाले टाटा ट्रस्ट्स को बाजार की निगरानी, खुलासों के नियमों का पालन करना होगा। इससे नियंत्रण कमजोर हो सकता है।

3. आम निवेशकों के लिए मौका: नमक से लेकर जगुआर-लैंड रोवर (जेएलआर) और आईटी सर्विसेज तक फैले 16.9 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट ग्रुप में पहली बार आम जनता निवेश कर सकेगी।

4. पारदर्शिता: समूह के वित्तीय प्रदर्शन, घाटे में चल रही कंपनियों और टॉप मैनेजमेंट के सभी बड़े निर्णय सार्वजनिक होंगे। शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी।

चंद्रशेखरन का तीसरा कार्यकाल अटकना भी मतभेद का संकेत

टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का तीसरा कार्यकाल अब तक औपचारिक रूप से तय नहीं हुआ है। वजह साफ है, लिस्टिंग को लेकर विवाद के अलावा एयर इंडिया जैसी कुछ कंपनियों के भारी-भरकम घाटे को लेकर भी मतभेद हैं। शीर्ष नेतृत्व के समक्ष यह अनिश्चितता तब है जब ग्रुप बड़े नियामकीय दबाव का सामना कर रहा है।

भास्कर नॉलेज

आखिर नोएल टाटा लिस्टिंग के खिलाफ क्यों अड़े हैं?

- **नियंत्रण कमजोर पड़ने की आशंका**
टाटा ट्रस्ट्स अभी टाटा सन्स में दो-तिहाई हिस्सेदारी के जरिये समूह की सभी बड़ी लिस्टेड कंपनियों, मसलन टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन आदि पर मजबूत पकड़ रखते हैं। पब्लिक लिस्टिंग से यह पकड़ कमजोर पड़ने की आशंका है।
- **लंबी अवधि की नीति बनाम बाजार का दबाव**
टाटा ग्रुप में लंबी अवधि की धैर्यपूर्ण व्यावसायिक रणनीति और तिमाही नतीजों को लेकर शेयर बाजार की उम्मीदें अक्सर टकराती हैं। नोएल टाटा और उनके नजरिये के समर्थक ट्रस्टी संभवतः ये नहीं चाहते।
- **पहचान, स्वायत्तता का मसला**
टाटा सन्स दशकों से प्राइवेट रही है। इसे प्राइवेट रखना समूह की पहचान और स्वायत्तता का प्रतीक माना जाता है।
- **फिलहाल परिवर्तन का दौर**
नोएल टाटा रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। लिस्टिंग इस प्रक्रिया को जटिल बना देगी। नए शेयरधारक, नई आवाजें और नए दबाव सामने आएंगे।

परेशानी • आलू-प्याज अभी तक सस्ते, पर अब सप्लाई घटी

महंगाई बढ़ रही, 20 जरूरी चीजों में से 16 के दाम 36% तक बढ़े

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

खाने के तेल, टमाटर और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में 36% तक बढ़ोतरी ने अप्रैल में रिटेल महंगाई 4% तक पहुंचा दी है। आगामी महीनों में महंगाई और बढ़ने का जोखिम बना हुआ है क्योंकि मई में भी कीमतें बढ़ रही हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा के 'एसेंशियल कमोडिटी इंडेक्स' के मुताबिक, अप्रैल में महंगाई सूचकांक सालाना 1.1% और मासिक आधार पर 0.3% बढ़ा। यह अगस्त, 2025 के बाद सबसे तेज मासिक बढ़ोतरी है। बीते महीने आम जरूरत की 20 में से 16 वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं। सनफ्लावर ऑयल 15%, सोया तेल 7.8% और टमाटर 35.8% महंगा हो गया। हालांकि बीते महीने आलू, प्याज और तुअर दाल जैसी चीजें 5-16% सस्ती भी हुई हैं। दिक्कत यह है कि युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर एनर्जी (जैसे तेल-गैस), मेटल और खाद्य तेल के दाम 78% तक बढ़े हैं। इसका असर भारतीय बाजार पर भी हो सकता है।

टमाटर, प्याज, आलू की आवक 13% घटी: मौसम विभाग ने देशभर के अलग-अलग हिस्सों में लू की चेतावनी दी है। इससे पहले ही मंडियों में 'टॉप' (टमाटर, प्याज, आलू) की आवक औसतन 12.8% घट गई है। इसके चलते अब आलू और प्याज के भाव भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी कीमतें मार्च से लगातार कम हो रही हैं।

हाल के महीनों में ये 5 चीजें सर्वाधिक महंगी

जरूरी चीजें	मार्च	अप्रैल	मई
टमाटर	▲33.3	▲35.8	▲45.8
सनफ्लावर ऑयल	▲13.1	▲15.2	▲15.0
सरसों तेल	▲10.3	▲10.6	▲11.0
सोया तेल	▲4.4	▲7.8	▲8.1
मूंगफली तेल	▲3.0	▲4.5	▲6.1

...पर इन 5 चीजों के दाम सबसे ज्यादा घटे

जरूरी चीजें	मार्च	अप्रैल	मई
आलू	▼12.2	▼14.5	▼16.4
प्याज	▼25.0	▼16.2	▼8.1
तुअर दाल	▼9.0	▼5.3	▼3.3
आटा	▼2.6	▼1.6	▼0.1
मूंग दाल	▼1.4	▼0.6	▼0.4

(मई के आंकड़े पहले 5 दिन के, स्रोत: सीएमआईई, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसर्च)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बेतहाशा बढ़े

कमोडिटी	अप्रैल में वृद्धि
क्रूड (ब्रेंट)	▲77.8%
यूरिया	▲121.5%
एल्युमीनियम	▲51.8%
सोया तेल	▲45.1%
गेहूं	▲12.6%
सोना	▲46.7%

अब इनका भी असर दिखने की आशंका...

- मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वी तटीय राज्यों में लू की चेतावनी दी है। इससे टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन प्रभावित होगा।
- पश्चिम एशिया में शांति पर बात न बनने से अप्रैल में कच्चा तेल 78%, एल्युमीनियम 52%, यूरिया 121% महंगा हुआ। भारत इनका आयात करता है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल के दाम 45% तक बढ़ गए। घरेलू बाजार में आयातित तेल महंगे होंगे।

मार्केट • कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने से कमजोरी

ईरान-यूएस डील पर सतर्क रुख, 114 अंक गिरा सेंसेक्स

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 77,845 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 4.30 अंक फिसलकर 24,327 पर फ्लैट रहा।

ट्रेडिंग के दौरान एक समय सेंसेक्स 426 अंकों की तेजी के साथ 78,385 तक पहुंच गया था। लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका-ईरान डील को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 101 डॉलर से बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने से भी सेंटिमेंट बिगड़ा। हालांकि बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 1% तक चढ़कर बंद हुए। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक, हॉर्मुज जलमार्ग खोलने की खबर से कच्चा तेल 100 डॉलर से नीचे आया था, लेकिन परमाणु डील की बातचीत पर संशय बढ़ते ही निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। आगे चौथी तिमाही के नतीजे और पश्चिम एशिया के हालात बाजार की चाल तय करेंगे। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में कैपिटल गुड्स 2% बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। साथ ही ऑटो 1.8%, इंडस्ट्रियल्स 1.7% चढ़कर बंद हुए। आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर जापान के निक्केई ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। शांति समझौते की उम्मीद में सोने की कीमत भी 0.3% बढ़कर 4,701 डॉलर प्रति औंस हो गयी। निवेशक अब कंपनियों के नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रखें।

वडोदरा में छापेमारी, 31.61 लाख का दूषित पानी जब्त

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने गुजरात के सावली इंडस्ट्रियल हब में छापेमारी कर 31.61 लाख रुपए का दूषित एल्कालाइन वॉटर जब्त किया है। जांच में सामने आया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पानी में प्रतिबंधित फुल्विक एसिड मिला रही थी। लैब रिपोर्ट के अनुसार पानी में अलग से काला खनिज मिलाया गया था, जिससे इसमें खतरनाक एसिड आ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मिलावट किडनी और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर हुई जांच में बोतलों के भीतर काले और भूरे रंग के कण तैरते मिले। पैकेजिंग पर उत्पाद का नाम और सामग्री की जानकारी भी गायब थी।

यूपीआई मेटा फीचर • ई-कॉमर्स एप्स पर यूपीआई पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड जितना तेज होगा

एनपीसीआई का मास्टर प्लान: बिना पिन यूपीआई पेमेंट

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

निकट भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बार-बार यूपीआई पिन डालने और एप बदलने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (एनपीसीआई) जल्द 'यूपीआई मेटा' फीचर ला रहा है। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूपीआई पेमेंट क्रेडिट कार्ड जितना तेज हो जाएगा। अभी भुगतान के लिए मर्चेंट एप से यूपीआई एप पर जाना होता है। नई तकनीक में यूपीआई अकाउंट मर्चेंट एप पर ही 'डिफॉल्ट' सेव कर सकेंगे। फिर पेमेंट के लिए सिर्फ फेस आईडी या फिंगरप्रिंट जरूरी होगा। एनपीसीआई इसे इसलिए ला रहा है क्योंकि जल्द 'एपल पे' की एंट्री होने वाली है।

सुविधा: क्यूआर कोड स्कैनिंग जैसा होगा अनुभव

एनपीसीआई का लक्ष्य ऑनलाइन पेमेंट को ऑफलाइन स्कैनिंग जैसा सहज बनाना है। यूपीआई मेटा के जरिये 'बाय नाउ' पर क्लिक करते ही यूजर सीधे ऑथेंटिकेशन पेज पर पहुंचेगा। इससे देरी खत्म होगी और ट्रांजैक्शन फेल होने का जोखिम भी कम होगा। इसे सितंबर में मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लॉन्च किया जा सकता है।

प्रतिस्पर्धा: एपल पे के साथ होगा सीधा मुकाबला

एपल पे की भारत में संभावित लॉन्चिंग ने एनपीसीआई की चिंता बढ़ा दी है। एपल अपने हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर तालमेल से तेज पेमेंट का अनुभव देता है। अभी ₹1,000 से ऊपर के भुगतान के लिए लोग क्रेडिट कार्ड पसंद करते हैं। एनपीसीआई चाहता है कि यूपीआई भी कार्ड्स के बराबर खड़ा हो सके।

चिंता: छोटे एप्स को बाजार में एकाधिकार की आशंका

अमेजन पे, नवी, क्रेड जैसे छोटे यूपीआई एप मेटा फीचर से बेचैन हैं। उन्हें डर है कि इससे फोन पे, गूगल पे का दबदबा बढ़ेगा। अधिकांश यूजर्स के फोन में ये एप पहले से हैं। इन्हें ही 'डिफॉल्ट' सेट होने की संभावना है।

दबदबा: डिजिटल लेनदेन में 86% शेयर यूपीआई का

- हर माह करीब 30 लाख करोड़ के 22 अरब ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं। 63% भुगतान दुकानदारों को।
- एनपीसीआई 'मार्केट कैप नियम' से किसी एक एप की हिस्सेदारी 30% तक सीमित करना चाहता है।

प्रतिद्वंद्विता खत्म • मस्क के सुपरकम्प्यूटर से अब क्लॉड एआई होगा और ताकतवर

स्पेसएक्स और एंथ्रोपिक के बीच बड़ी डील, इससे क्लॉड एआई को मिलेगा हैवी कम्प्यूटिंग पावर

एजेंसी | न्यूयॉर्क

एआई की दुनिया के दो बड़े प्रतिस्पर्धी साथ आ गए हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के बीच साझेदारी हुई है। इसके तहत मस्क की टेनेसी स्थित कोलॉसस 1 फैसिलिटी से एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई को एक महीने के भीतर 300 मेगावाट नई कम्प्यूट क्षमता मिलेगी।

यह डील एंथ्रोपिक के लिए गेमचेंजर है। अब यूजर क्लॉड कोड और क्लॉड एपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। यह पार्टनरशिप चौंकाने वाली है क्योंकि मस्क पहले एंथ्रोपिक के आलोचक रहे हैं, लेकिन अब वे खुद उसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। कोलॉसस 1 दुनिया के सबसे बड़े सुपरकम्प्यूटरों में शुमार है। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के मुताबिक, कंपनी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय बड़ी कंपनियों से कम्प्यूट पावर ले रही है। कंपनी का अमेजन के साथ 5 गीगावाट का समझौता है। इसमें 2026 के अंत तक 1 गीगावाट नई क्षमता जुड़ेगी। गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ भी 5 गीगावाट का करार है, जो 2027 से शुरू होगा।

इलॉन मस्क

डारियो अमोदेई

भविष्य: अंतरिक्ष में डेवलप होगी एआई कम्प्यूट क्षमता

एंथ्रोपिक स्पेसएक्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। समझौते के तहत ऑर्बिटल एआई कम्प्यूट क्षमता विकसित करने में रुचि जताई गई है। इसके जरिये अंतरिक्ष में कई गीगावाट की क्षमता तैयार होगी। दोनों कंपनियां अब बड़े सहयोग की संभावनाएं तलाश रही हैं।

लुक्का: ऑडी ने 91 साल पुरानी 'स्पीड मशीन' री-क्रिएट की; चांदी की ये कार 327 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है

इंगोल्स्टैड (जर्मनी)| ऑडी ने अपनी 91 साल पुरानी 'ऑटो यूनियन लुक्का' रेस कार नए सिरे से तैयार की है। यह वन-ऑफ क्रिएशन 6.0-लीटर वी16 इंजन से लैस है, जो 512 हॉर्सपावर पैदा करता है। मूल कार 1935 में 327 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड रफ्तार से दौड़ी थी। ऑडी ने इसे पुराने ब्लूप्रिंट्स और तस्वीरों की मदद से दोबारा बनाया है। सिल्वर बॉडी, एयरोडायनामिक डिजाइन और विमान जैसे आकार वाली यह मशीन 'गुडवुड फस्टिवल ऑफ स्पीड' में नजर आएगी। यह बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

राहत • सरकार ने शुरू की ईसीएलजीएस 5.0 स्कीम

एयरलाइंस को अब सात साल के लिए मिलेगा कर्ज

सुब्रत पांडा, दीपक पटेल | मुंबई

देश की तीन प्रमुख एयरलाइंस को ईसीएलजीएस-5.0 स्कीम के तहत अधिकतम 7 साल के लिए कर्ज मिल सकेगा। इन्हें शुरुआती 2 साल तक मूलधन चुकाने से छूट मिलेगी और वे ब्याज के आधे हिस्से को भी कर्ज में बदल सकेंगी। बैंकों के बोर्ड दरों को कम रखने पर भी स्वतंत्र फैसला लेंगे। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संकट, महंगे ईंधन और रुपए की कमजोरी से जूझ रही कंपनियों को राहत देने के लिए कुल 2.55 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट की योजना बनाई है। एविएशन सेक्टर के लिए फंड की सीमा ₹5,000 करोड़ तय की गई है। इसमें प्रति कंपनी ₹1,000 करोड़ का कर्ज और इक्विटी निवेश के बदले ₹500 करोड़ का अतिरिक्त फंड मिलेगा। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एविएशन सेक्टर को 'नेगेटिव' श्रेणी में रखा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इंडस्ट्री का सामूहिक घाटा 18 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

इस महीने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 25% कटौती की गई

आर्थिक दबाव के कारण भारतीय एयरलाइंस ने मई में साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 25% कटौती की है। तीसरी तिमाही में इंडिगो का मुनाफा 77.6% घटकर 549 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं एयर इंडिया को बीते वित्त वर्ष 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटा हुआ है।

बिजनेस एंकर अब पैसा सीधे बैंक खाते में, दस्तावेज ईमेल पर और ट्रेड मोबाइल एप से, ये क्रांतिकारी

10 साल में शेयर निवेशक 8 गुना हुए, पर शिकायतें आधी

सचिन मामपट्टा | मुंबई

देश के शेयर बाजार में हाल के वर्षों में दिलचस्प उलटफेर हुआ है। एक दशक में सक्रिय निवेशकों की संख्या के मुकाबले ब्रोकरेज कंपनियों के खिलाफ शिकायतों में लगातार कमी आई है। यह महज संयोग नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, नियामकीय सुधार और निवेशक जागरूकता का मिला-जुला असर है।

वित्त वर्ष 2025-26 में एनएसई पर ब्रोकरेज फर्मों के खिलाफ कुल 15,770 शिकायतें दर्ज की गईं। 4.57 करोड़ सक्रिय ग्राहकों के आधार पर यह प्रति 10 लाख पर 340 शिकायतों का अनुपात बनता है। यह आंकड़ा पिछले साल के 400 से कम है। लेकिन असली चौंकाने वाली तुलना तब सामने आती है जब इसे एक दशक पहले से नापा जाए। वित्त वर्ष 2015-16 में हर 10 लाख सक्रिय निवेशकों पर 900 शिकायतें आती थीं। तब सक्रिय ग्राहकों की संख्या 52 लाख थी, जो अब 784 फीसदी बढ़कर 4.57 करोड़ हो चुकी है। यानी निवेशक लगभग 8 गुना बढ़े, लेकिन शिकायतों की दर 63% से ज्यादा घट गई।

अब शिकायतें ज्यादातर तभी आती हैं, जब कोई तकनीकी गड़बड़ी हो

एक वक्त था जब ब्रोकरेज का बकाया चेक या डिमांड ड्राफ्ट से आता था, कॉन्ट्रैक्ट नोट डाक से मिलता था और ट्रेड किसी डीलर के जरिये होता था। हर कदम पर शिकायत की गुंजाइश थी। अब पैसा सीधे बैंक खाते में, दस्तावेज ईमेल पर और ट्रेड मोबाइल एप से होते हैं। लुधियाना रिटेल इन्वेस्टर्स एसोसिएशन से जुड़े जे आर जैग कहते हैं, 'सिस्टम में सुधार हुआ है। पुरानी दिक्कतें तकनीक की वजह से काफी हद तक खत्म हो गई हैं।' अब शिकायतें ज्यादातर तभी आती हैं जब कोई तकनीकी गड़बड़ी हो।

बीएसई का आंकड़ा तो और भी चौंकाता है। बीएसई पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या 998 फीसदी बढ़कर 2.4 करोड़ हो गई, जबकि प्रति 10 लाख शिकायतें वित्त वर्ष 2015-16 के 506 से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में महज 34 रह गईं। यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी की देन नहीं है। सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 'इन्वेस्टर एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन' के चेयरमैन भावेश वोरा के मुताबिक, शेयर बाजारों के बदलते ढांचे के साथ-साथ निवेशकों की शिक्षा और जागरूकता के लिए नियामकीय हस्तक्षेप ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।

पुराने दिनों को याद करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। निवेशक संघ 'मिडास टच' के संस्थापक वीरेंद्र जैन का कहना है कि पहले शिकायतें मुख्यतः लाभांश न मिलने या दस्तावेजों की डिलिवरी न होने जैसे मुद्दों पर केंद्रित होती थीं। यह संघ 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले से निवेशकों के लिए हेल्पलाइन चला रहा है। संख्याओं का यह खेल बताता है कि भारत का रिटेल निवेशक अब बाजार में आने से नहीं डरता। साथ ही सिस्टम पर उसका भरोसा भी बढ़ा है।

प्रस्ताव • अभी जेब पर पड़ने वाले बोझ का मूल्यांकन

जन सुरक्षा: बीमा कवर 2 लाख से बढ़ा 5 लाख करने की तैयारी

अंजलि कुमारी | मुंबई

सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा यानी पीएमबीएसवाई और जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मिलने वाले 2 लाख रुपए का कवर बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने गुरुवार को मुंबई में इस प्रस्ताव की जानकारी दी। सरकार फिलहाल प्रीमियम की लागत और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ का मूल्यांकन कर रही है। विभाग के पास आंकड़े तैयार हैं, मंजूरी के बाद विस्तृत ब्योरा साझा किया जाएगा। साल 2015 में शुरू हुई ये कम लागत वाली बीमा योजनाएं बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। इसमें ऑटो-डेबिट से प्रीमियम जमा होता है। अभी जीवन ज्योति बीमा का सालाना प्रीमियम 436 रुपए और सुरक्षा बीमा का 20 रुपए है।

मंथन: प्रीमियम और खर्चों के आधार पर मूल्यांकन

अभी सिर्फ कवरेज राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मंजूरी के बाद ही नई प्रीमियम दरें घोषित होंगी। सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों को दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता कवर देती है। जीवन ज्योति 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए है।

₹797 करोड़ प्रॉफिट

बीएसई का मुनाफा 61% बढ़ा, 10 रुपए डिविडेंड

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

जनवरी-मार्च तिमाही में देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का मुनाफा 61% बढ़कर 797.3 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 494.42 करोड़ रुपए था। बीती तिमाही एक्सचेंज की आय भी 85% बढ़कर 1,563.51 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल की समान तिमाही में एक्सचेंज की कमाई 846.64 करोड़ रुपए रही थी। मुनाफा बढ़ने की मुख्य वजह ट्रांजैक्शन चार्ज से आय बढ़ना है। यह सालाना आधार पर 114% बढ़कर 1,311 करोड़ हो गई। तिमाही आधार पर भी मुनाफे में 32% और आय में 26% की ग्रोथ दर्ज हुई है। बेहतर नतीजों के साथ बोर्ड ने निवेशकों के लिए प्रति शेयर 10 रुपए फाइनल डिविडेंड की मंजूरी भी दी है।